3 राजधानी
छह फरवरी को मिलेगा नया मेयर

6 अभिमत
तेजी से प्रगति करती अर्थव्यवस्था

10 बजट विशेष
रियल एस्टेट ने सराहना की

11 विदेश
मोदी को बाइडेन ने किया आमंत्रित

RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 11 अंक 89
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 2 फरवरी, 2023
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

सचिन ने विश्वकप विजेता टीम को सम्मानित किया
स्पोर्ट्स-12

आयकर मोर्चे पर राहत, बुजुर्गों व महिलाओं को तोहफा

आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में सबको साधने का प्रयास

सालाना आय	नया टैक्स
0-3 लाख	कुछ नहीं
3-6 लाख	5%
6-9 लाख	10%
9-12 लाख	5%
12-15 लाख	20%
15 लाख से अधिक	30%

- सालाना स्लैब में बड़ा बदलाव
- सात लाख तक वार्षिक आय पर नहीं लगेगा कोई कर

बजट 2023-24

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेश नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में सभी तबकों को साधने का प्रयास किया। उन्होंने जहां एक तरफ मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर राहत देने की घोषणा की, वहीं लघु बचत योजनाओं के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों और नई बचत योजना के जरिए महिलाओं को भी सौगात दी है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर खर्च में 33 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि करने का भी प्रस्ताव किया है। नई कर व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की आय सात लाख रुपए है, उसे कोई कर नहीं देना होगा। अबतक यह सीमा पांच लाख रुपए है। साथ ही कर स्लैब को सात से घटाकर पांच किया गया है। साथ ही अधिभार की दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के बाद कर की अधिकतम दर 42.7 प्रतिशत से घटकर लगभग 39 प्रतिशत रह जाएगी।

वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं मासिक आय योजना के तहत जमा सीमा बढ़ाकर नौ लाख रुपए की गई है। महिलाओं के लिए अलग से नई बचत योजना...महिला सम्मान बचत पत्र...की घोषणा की गई। इसमें दो वर्ष के लिए दो लाख रुपए तक की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। सीतारमण ने अपना पांचवां पूर्ण बजट ऐसे समय पेश किया जब वैश्विक चुनौतियों के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है और सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने मोबाइल फोन कल-पुर्जों तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लीथियम बैटरी और अन्य ऐसे सामान के लिए सीमा शुल्क में कटौती की भी घोषणा की। यह अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। अगले साल फरवरी में अंतरिम बजट यानी लेखानुदान पेश किया जाएगा। बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय लगातार तीसरी बार उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है। इसे 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत बैठता है। (शेष पेज 8)

- एक अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर सात लाख किया गया, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा सीमा 30 लाख हुई, मासिक आय योजना में जमा सीमा नौ लाख की गई
- महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान, इसमें दो वर्ष के लिए दो लाख रुपए तक की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा

मुख्य बिन्दु

- लगभग नौ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है।
- बजट की सात प्राथमिकताएं सप्तऋषि। इनमें शामिल हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र।
- 5जी सेवाओं पर आधारित एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी।
- विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल 2023 से कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होगी।
- वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी।
- लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।
- बजट अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत है।

क्या होगा महंगा

- सिगरेट
- किचन की चिमनी
- आयातित साइकिल और खिलौने
- पूर्ण रूप से आयातीत कारें और इलेक्ट्रिक वाहन
- नकली आभूषण
- कम्पाउंडेड रबड़
- अप्रसंस्कृत चांदी (सिल्वर डोर)
- नेफ्था

क्या होगा सस्ता

- मोबाइल फोन
- घरेलू स्तर पर विनिर्मित टीवी सेट
- झींगे का आहार
- जलीय जीवों के आहार के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाला मछली का तेल
- प्रयोगशाला में हीरों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री
- पूंजीगत माल
- इलेक्ट्रिक वाहन

देशभर में खुलेंगे 157 नर्सिंग कॉलेज

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 10 हजार करोड़ की बढ़ोतरी करते हुए 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किया है। जो 2022-23 में आवंटित की गई 79,145 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि देशभर में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। (शेष पेज 8)

एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की होगी भर्ती

नई दिल्ली। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और अन्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी। शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र और इंजीनियरिंग संस्थानों में 5-जी सेवाओं का उपयोग करते हुए अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। (शेष पेज 8)

पीएम आवास योजना के लिए 66% अधिक धन

नई दिल्ली। सभी को अपनी छत देने के सरकार के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री की ओर से यह घोषणा भी की गई कि केंद्र सरकार शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष की स्थापना करेगी तथा इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शहरी आधारभूत अवसंरचना विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सीतारमण ने कहा कि सभी शहरों और नगरों में सीवरों और सेप्टिक टैंकों को मैन होल से पूरी तरह मशीन होल मॉडल पर परिवर्तित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कोष का उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में अवसंरचना तैयार करने में किया जाएगा।

गरीब-मध्य वर्ग के सपने पूरे करेगा बजट : प्रधानमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि अमृत काल के पहले बजट ने विकसित भारत के संकल्प और गरीबों एवं मध्यम वर्ग सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा बढ़ा दी, छोटी बचत पर रियायतें दीं और पिछले एक दशक में पूंजीगत खर्च में सबसे बड़ी वृद्धि की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे जीवन की सुगमता सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री ने 2047 के सपनों को साकार करने में मध्यम वर्ग की क्षमता को रेखांकित किया और कर की दरों में कमी के साथ-साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण, पारदर्शिता और गति पर भी प्रकाश डाला। (शेष पेज 8)

कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपये की घोषणा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सरकार ने बुधवार को पेश बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की। कृषक समुदाय को रियायती दरों पर अधिक कृषि कर्ज देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की नई उप-योजना 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी, ताकि मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने, मूल्य श्रृंखला क्षमता में सुधार के साथ मत्स्यपालन के लिए बाजार का विस्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा मछली के चारे के घरेलू विनिर्माण के लिए प्रमुख लागतों पर सीमा शुल्क भी कम किया जाएगा। (शेष पेज 8)

रेल के सफर को और आरामदायक बनाएंगे

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- रेलवे के लिए अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय, 2.40 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत परिव्यय है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि रेलवे को मौजूदा बजट प्रस्ताव में उपलब्ध कराया गया परिव्यय, 2013-14 में कुल पूंजीगत परिव्यय का लगभग 9 गुना है।

सीतारमण ने कहा कि कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम-मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसे 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। इसमें 15 हजार करोड़ रुपये निजी क्षेत्र का होगा। उन्होंने कहा कि रेल में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोच के आंतरिक हिस्सों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा और यात्रियों के आराम के हिसाब से इसमें सुधार किया जाएगा। (शेष पेज 8)

रक्षा क्षेत्र के लिए 5.94 लाख करोड़ आवंटित

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है जो पिछले साल 5.25 लाख करोड़ रुपये थी। जो पिछले बजट से 71 हजार करोड़ रुपये अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट पेश किया जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए कुल 1.62 लाख करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। इनमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान की खरीद शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में, पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार व्यय 1.50 लाख करोड़ रुपये था। अगले वित्त वर्ष के बजट दस्तावेजों के अनुसार, राजस्व व्यय के लिए 2,70,120 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिनमें वेतन भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर होने वाले खर्च शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय के लिए बजटीय आवंटन 2,39,000 करोड़ रुपये था। (शेष पेज 8)

संवारे जाएंगे 50 हवाईअड्डे

नई दिल्ली। क्षेत्रीय हवाई परिवहन को बेहतर बनाने और देश के भीतर आवाजाही को आसान बनाने के लिए 50 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, जलीय हवाई अड्डों और उन्नत लैंडिंग भूमि का पुनर्विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई यातायात सुदृढ़ बनाने के लिए कई कार्यक्रम, खासकर उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना चलाई है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, जलीय हवाई अड्डों और उन्नत लैंडिंग भूमि का पुनरोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन्हें 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता के तौर पर लिया जाएगा। इसमें 15,000 करोड़ रुपए निजी स्रोतों से आएंगे।

बाजार

सेंसेक्स	59,708	↑ 158	
निफ्टी	17,616	↓ 45	
सोना	57,830	↑ 640	/10g
चांदी	70,059	↑ 1230	/kg

क्विक न्यूज

अडाणी एंटरप्राइजेज ने एफपीओ वापस लिया

नई दिल्ली। अडाणी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20 हजार करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की। हालांकि, कंपनी के एफपीओ को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। समझा जाता है कि अडाणी एंटरप्राइजेज ने यह कदम अमेरिका की शॉर्टसेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उठाया है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, अडाणी एंटरप्राइजेज के एफपीओ के तहत 4.55 करोड़ शेयरों की पेशकश की गई थी, जबकि इसपर 4.62 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन मिले थे। गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित 96.16 लाख शेयरों पर करीब तीन गुना बोलियां मिली थीं। वहीं पात्र संस्थागत खरीदारों के खंड के 1.28 करोड़ शेयरों पर पूर्ण अभिदान मिला था।

भाजपा ने सराहा, विपक्ष बोला-जनता की उम्मीदों पर आघात

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- राहुल गांधी ने करार दिया मित्रकाल बजट, चिदम्बरम ने सरकार को बताया जमीनी हकीकत से अनजान
- खड़गे, ममता, अखिलेश, मायावती, बीआरएस के केशव राव ने कहा- बेरोजगारी, महंगाई से निपटने के लिए कुछ नहीं

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट को जनता की उम्मीदों के साथ विश्वासघात करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दावा किया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट ने देश के ज्यादातर लोगों को निराश किया है। यह जनता की उम्मीदों पर आघात है। उन्होंने एक बयान में कहा कि बजट और वित्त मंत्री का बजट भाषण यह प्रदर्शित करता है कि जनता, उसके जीवन, आजीविका तथा अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई से सरकार कितनी अनजान है। चिदंबरम ने दावा किया कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बेरोजगारी, गरीबी और असमानता जैसे शब्दों का कहीं उल्लेख नहीं किया। शुक्र है कि उन्होंने गरीब शब्द का उल्लेख दो बार किया। मुझे यकीन है कि भारत के लोग इसका संज्ञान लेंगे कि सरकार को किन लोगों की चिंता है और किन लोगों की नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार की ओर से अनुमानित जीडीपी (वास्तविक मूल्यों पर आधारित) 232,14,703 करोड़ रुपए बताई गई थी और 11.1 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया गया था। वहीं, वर्ष 2022-23 के लिए 258,00,000 करोड़ रुपए की जीडीपी का अनुमान लगाया गया था। मौजूदा बजट में सरकार ने 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान 273,07,751 करोड़ रुपए का लगाया है। इस तरह, वास्तविक मूल्यों पर आधारित जीडीपी दोगुनी होनी चाहिए थी, जबकि वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) द्वारा और आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि जीडीपी की वृद्धि दर सात प्रतिशत रही। सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। चिदंबरम ने इसे संवेदनहीन बजट बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बजट भारतीय जनता पार्टी पर जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है तथा इसे सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के संदर्भ में कोई समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट 38,468 करोड़ रुपए कम कर दिया, तो गरीबों का क्या होगा? कुल-मिलाकर मोदी सरकार ने जनता का जीवन दुश्वार किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को मित्रकाल बजट करार देते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है। (शेष पेज 8)

अमृत काल की मजबूत आधारशिला : शाह

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे दूरदृष्टिपूर्ण और अमृत काल की मजबूत आधारशिला बताया है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी और दूरदर्शी है और यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देगा। वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला है। पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपए करना और राजकोषीय घाटे को 5.9 प्रतिशत रखे जाने के लक्ष्य की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि यह केंद्र सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नए भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है। (शेष पेज 8)

समावेशी, हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला बजट: अनुराग ठाकुर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम बजट को समावेशी, सर्वस्पर्शी और हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पंच प्रण से प्रेरित इस बजट के सात आधार नए भारत-आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बुनियाद बनेंगे। ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट अमृतकाल का पहला बजट है, जो पिछले बजट में खड़ी की गई नींव पर आधारित है। सूचना प्रसारण मंत्री ने अपने बयान में कहा, समावेशी विकास व दूरगामी नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर चलते हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। (शेष पेज 8)

डेढ़ गुना दामों पर बिके ग्रेनो के भूखंड

तीन बिल्डिंग से 200 करोड़ का था अनुमान, अब मिलेंगे 305 करोड़

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तय रिजर्व प्राइस से करीब डेढ़ गुना दामों पर तीन बिल्डर भूखंड बेचने में सफलता पाई है। रिजर्व प्राइस पर इन तीन भूखंडों से करीब 200 करोड़ रुपये मिलने का आकलन था, लेकिन औसतन डेढ़ गुना अधिक रेट पर बिकने से प्राधिकरण को इन तीन भूखंडों से अब 305 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। ये पैसे 90 दिनों में एकमुश्त मिल जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में पहली बार बिल्डर भूखंड का आवंटन ई-ऑक्शन के जरिए हुआ है।

इससे ग्रेटर नोएडा में आशियाना चाहने वाले खरीदारों का सपना भी पूरा हो सकेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की पहल पर बिल्डर विभाग ने 11 भूखंडों की योजना 06 दिसंबर 2022 को निकाली थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर थी। इनमें से सेक्टर 10 व सेक्टर 12 के तीन भूखंडों के लिए 9 निविदाएं प्राप्त हुईं। मंगलवार को इनकी बिड खुली।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अदिति सिंह ने बताया कि सेक्टर 10 प्लॉट. जीएच 03, के 22 हजार वर्ग मीटर के भूखंड के लिए रिजर्व प्राइस के आधार पर 70.84 करोड़ रुपये कीमत मिलने का आकलन था, लेकिन मंगलवार को इस भूखंड के लिए 18 राउंड की बिडिंग हुई। मैसर्स गोल्फग्रीन मैनसंस ने सर्वाधिक 127.05 करोड़ रुपये की बिड लगाई। इस तरह ये भूखंड रिजर्व प्राइस से करीब 60 फीसदी अधिक दर पर बिका है।

दूसरा भूखंड भी सेक्टर 10 प्लॉट-जीएच 04, में ही 20240 वर्ग मीटर का बिका है। रिजर्व प्राइस से इसकी कीमत 70.84 करोड़ रुपये थी, लेकिन ये 57 प्रतिशत अधिक दर पर 125.38 करोड़ रुपये में बिका है। इस प्लॉट के लिए आयरिश इंफ्रा स्ट्रक्चर और अंशु हॉस्पिटल ने ये बिड लगाई है। वहीं, तीसरा भूखंड सेक्टर 12 में जीएच.02सी, 14998 वर्ग मीटर एरिया का बिका है। रिजर्व प्राइस से इसकी कीमत 52.49 करोड़ रुपये तय की गई है, लेकिन यह 53.01 करोड़ रुपये में बिका है।

इस भूखंड के लिए सवाना बिल्डर्स कंपनी और एल्डिको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ने सर्वाधिक बिड लगाई। इन भूखंडों के आवंटन से प्राधिकरण को 90 दिन में करीब 305 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। एसीईओ ने बताया कि 90 दिनों में इन तीनों भूखंडों की पूरी कीमत प्राप्त हो जाएगी। इनका आवंटन पत्र भी तत्काल जारी कर दिया जाएगा। सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि बिल्डर भूखंडों का पहली बार ई.ऑक्शन हुआ है। इसके बावजूद रिजर्व प्राइस से डेढ़ गुना अधिक कीमत प्राप्त हुआ है।

ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से लाखों की ठगी

- आरोपियों ने 14 बार पैसे अपने खाते में हस्तांतरित कराए

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की अरिहंत एंबियंस सोसायटी के एक युवक से साइबर अपराधियों ने आस्ट्रेलिया की एक कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर 12.88 लाख रुपये ठग लिए।

आरोपितों ने खुद नौकरी डाट काम का अधिकारी बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने युवक का दो चरणों में इंटरव्यू भी कराया और चयन होने की बात झांसे में लिया। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अरिहंत एंबियंस सोसायटी के पीड़ित नवीन वर्मा का कहना है कि उनके पास अजय दीक्षित नाम के एक व्यक्ति ने अंजान नंबर से काल किया था। अजय ने खुद को नौकरी डाट काम का अधिकारी बताकर आस्ट्रेलिया में नौकरी लगवाने की बात कही थी। कुछ देर बाद उनके पास बालाजी नाम के व्यक्ति का काल आया और उसने अपने आप को कंपनी के एचआर विभाग से बताते हुए उनके इंटरव्यू की तारीख तय कर दी। नवीन का कहना है कि पहले चरण में इंटरव्यू किसी आस्ट्रेलिया के व्यक्ति ने लिया और दूसरा चरण का इंटरव्यू थॉमस नाम के युवक ने लिया।

इंटरव्यू से पहले उन्हें कंपनी में उपमहाप्रबंधक और बाद में महाप्रबंधक के पद पर रखने की बात तय हुई। बाद में आरोपितों ने उनसे विभिन्न मदों में शुल्क के नाम 14 बार में 12.88 लाख ले लिए। एसीपी वेव सिटी रवि प्रकाश सिंह का कहना है कि मामले में शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

प्रबंधक जल और सीवर के नेतृत्व में अधिकारियों ने गांव वालों के साथ बैठक की

ग्राम नंगली वासियों के साथ बैठक की

नोएडा। ग्राम नंगली वाजिदपुर में संजय पाराशर, वरिष्ठ प्रबंधक जल और सीवर के नेतृत्व में जल व सीवर संबंधित अधिकारियों ने गांव वासियों की समस्याओं के निदान हेतु दौरा किया और ग्राम वासियों के साथ बैठकर जल और सीवर से संबंधित समस्याओं को जाना और ग्राम वासियों को आश्वस्त किया कि जल्द ही मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम वाजिदपुर को स्वच्छता के मामले में जल और सीवर विभाग से समस्या का सामना न करना पड़े व गांव वासियों को स्वच्छ जल सुगमता से मिल सके ऐसा भरकस प्रयाश किया जाएगा क्योंकि किसानों ने माँ रूपी अपनी जमीन देकर विश्वस्तरीय शहर नोएडा बनाने में ग्राम वासियों ने सहयोग किया है। इस दौरान ग्राम चौपाल में श्याम सुंदर सिंह भगत जी, सुभाष चौहान, नीरज चौहान, नरेश चौहान, रिंकू उर्फ उदय सिंह, किसान नेता राजू पंडित, बृजेश मास्टर, नोएडा क्षेत्र के ग्राम वासियों के जीवन बेहतरी के लिए कार्य करने वाली संस्था नोवरा। नोएडा विलेज रेजिडेंट एसोसिएशन से अजय चौहान, उपाध्यक्ष नोवरा व सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।

चार साल से फरार 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा में चोरी के एक मामले में चार साल से फरार चल रहे एक आरोपी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस पर 25 हजार का इनाम रखा था। आरोपी को सेक्टर.62 गोल चक्कर के पास सेक्टर.63 से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान संजय उर्फ मामा पुत्र रामधारी निवासी सोनीपत के रूप में हुई है। आरोपी ने थाना फेज.3 क्षेत्र में चोरी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी चार साल से फरार चल रहा था। उसे डर था कि वह कही गिरफ्तार न हो जाए इसके लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इसको पकड़ने के लिए कई बार दबिया दी गई थी। लेकिन ये फरार हो जाता था।

स्वामी प्रसाद के खिलाफ किया प्रदर्शन

गाजियाबाद। राष्ट्रीय जागरूक ब्राहम्ण महासंघ ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष तरूण शर्मा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित्र मानस का अपमान किया है, हिन्दू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। महासंघ ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि सरकार भारतीय संस्कृति आयोग का गठन करें और मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई जाए। साथ ही मौर्य को आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।

दूल्हे के ताऊ से नकदी-ज्वेलरी का बैग लूटकर आरोपी फरार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने शादी समारोह में चढ़त के दौरान दूल्हे के ताऊ से ज्वेलरी से भरे 2 बैग लूट लिए हैं। ये वारदात तब हुई, जब दूल्हे के ताऊ डांस कर रहे थे। इसी दौरान बाइकर्स बदमाश आए और बैग झपटकर फरार हो गए।

पुलिस ने थ्स् दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद में खोड़ा स्थित सरस्वती विहार निवासी मंगूलाल शर्मा सेना से रिटायर सूबेदार मेजर हैं। उनके भतीजे अभिषेक शर्मा की एक फरवरी की रात ग्रीन वैली फार्म हाउस में शादी थी। रात करीब सवा 10 बजे दूल्हे की चढ़त सिकंदरपुर पुलिस चौकी के नजदीक थी और बाराती डांस कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश तेज रफ्तार से आए और मंगूलाल शर्मा से दो बैग लूटकर ले गए। एक बैग में कुल 1 लाख 20 हजार रुपए रखे हुए थे।

जिसमें 500, 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोटों की नई गड्डियां व रिश्तेदारों के 19 लिफाफे रखे हुए थे। जबकि दूसरे बैग में दुल्हन का मंगलसूत्र, पायजेब, सिंदूर, सुहागपूड़ा आदि जेवरात रखे थे। कुछ बारातियों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए।

मर्सिडीज कार में लगी आग, चालक की मौत

- अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया था वाहन

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा के फेज दो कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर-93 में मंगलवार रात दो बजे के करीब तेज गति मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई और गेट लाक हो गया। चालक अंदर ही रह गया और आग लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद मृत अवस्था में चालक को बाहर निकाला जा सका।

मृतक की पहचान न्यू दिल्ली के रोहिणी सेक्टर नौ के अनुज सहरावत के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एडीसीपी विशाल पांडेय ने बताया कि बीती रात्रि पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर.93 के पास एक मर्सिडीज कार में आग लग गई है और चालक कार में फंसा हुआ है। सूचना के आधार पर तुरंत मौके पर पुलिसकर्मी वह दमकल कर्मी पहुंचे।

टक्कर की वजह से दरवाजे लाक होने की वजह से चालक उसी में फंसा हुआ छटपटा रहा था। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया और दरवाजा काटकर चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे में कार भी पूरी तरह से जल गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घटना के समय कार की रफ्तार काफी तेज थी। पुलिस ने मृतक के स्वजन को भी घटना की जानकारी दी।

तेज गति होने के कारण चालक कार पर से नियंत्रण खो बैठा और कार डिवाइडर पर चढ़कर पेड़ से टकरा गई। जिस पेड़ से मर्सिडीज टकराई वह उखड़ गया। एसीपी अमित प्रताप सिंह ने बताया कि अनुज का एक घर सेक्टर-168 पाम ओलंपिया सोसायटी में भी है। देर रात वह दिल्ली वाले घर से नोएडा आ रहा था, तभी हादसा हुआ। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। अनुज फरीदाबाद में जेसीबी बनाने वाली कंपनी में कार्यरत थे। मौत की सूचना मिलते ही घर में मातम पसर गया।

ICICI Bank

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 23, शाल टॉवर, तीसरी मंज़िल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग दिल्ली -110005

सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी

[नियम 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुन: निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।

सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्जदार एवं ज़मानतदार को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति के संरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/ अधिभारित है। उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" एवं "जिस भी स्थिति में है" के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कर्ज़दार (रों)/ सह-कर्ज़दारों/ गारंटरों का नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	संपत्तियों निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	जितेंद्र कुमार छाबड़ा (कर्ज़दार)/ राम देवी (सह कर्ज़दार) LBNOD00002116807	फ्लैट नंबर ए-2002, टॉवर ए, स्प्रिंगव्यू फ्लोर्स, क्रिसेंट पार्क टाउनशिप, एनएच- 24, गाजियाबाद, यूपी, क्षेत्रफल : 1243 वर्ग फुट	रु. 66,63,747.35 (जनवरी 30, 2023 तक)	रु. 32,50,000/- / रु. 3,25,000/-	फरवरी 18, 2023 को दोप. 12:30 बजे से दोप. 01:30 बजे तक	फरवरी 24, 2023 को सु. 11:00 बजे से दोप. 12:00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी ई-नीलामी संस्था **मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** की वेबसाइट **(URL Link- https://disposalhub.com)** पर संचालित होगी। बंधकदाताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को **फरवरी 23, 2023** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस/ इन संरक्षित संपत्ति/यों की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (सारणी **ई** संदर्भ) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग दिल्ली -110005** में **फरवरी 23, 2023** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज, **फरवरी 23, 2023** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करें। कृपया नोट करें कि संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहने पर वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग दिल्ली -110005** में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को **फरवरी 23, 2023** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैडूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **दिल्ली** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।

संपत्ति अवलोकन, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** को फोन नंबर **9372730494/ 7304914763** पर संपर्क करें।

कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसियाँ **1. मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड व 2. ओजीओ असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड** इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न हैं।

प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट **www.icicibank.com/n4p4s** पर संपर्क करें।

तिथि : फरवरी 02, 2023
स्थान : दिल्ली/एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

शिक्षिका ने 7वें फ्लोर से कूदकर की आत्महत्या

नोएडा। गार्डेनिया ग्लोरी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने 7वें फ्लोर से कूदकर जान दे दी। वह फिजिक्स टीचर थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पारुल गुप्ता गार्डेनिया ग्लोरी सोसाइटी के फ्लैट-702 में अकेली रहती थी। उनका पति से तलाक हो चुका है। नोएडा जोन के रजनीश वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया।

विद्युत सप्लाई रिपोर्ट में खेल, चीफ इंजीनियर का तबादला

- मुरादाबाद के नीरज स्वरूप अब यह पद संभालेंगे

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

बारिश के चलते 29 जनवरी को आधे से अधिक शहर में हुआ ब्लैक आउट गाजियाबाद के पॉवर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर मुकेश मित्तल के तबादले की वजह बन गया। उन्हें मेरठ मुख्यालय से अटैच किया गया है और उनकी जगह मुरादाबाद के चीफ इंजीनियर नीरज स्वरूप को यहां तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि विद्युत सप्लाई की गलत रिपोर्ट भेजकर शासन को गुमराह करने के चलते यह कार्रवाई की गई है।

बता दें कि रविवार को आधे से अधिक शहर में 24 घंटे तक लाइट गुल रही थी। कई क्षेत्रों में तो सुबह तक भी सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। विद्युत कटौती को लेकर लोग लगातार बिजली अधिकारियों व मुख्य अभियंता को फोन कर रहे थे। इतना ही नहीं गाजियाबाद से भी सैंकड़ों लोगों ने ट्वीट कर विद्युत कटौती की जानकारी मुख्यायल को दी थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के फोन तक उठाने जरूरी नहीं समझे।

हजारों लोग बिजली न होने से परेशान रहे, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सप्लाई रिपोर्ट में ही खेल कर दिया। विभागीय सूत्रों की मानें तो 29 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ट्रांसमिशन की ओर से सप्लाई 23 से 24 घंटे रही। यानि ट्रांसमिशन स्तर से कटौती नहीं की गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन स्तर से लोगों को बिजली नहीं मिल सकी। अधिकारियों ने इसी रिपोर्ट में बड़ा खेल करते हुए ट्रांसमिशन की रिपोर्ट को ही शासन को भेज दिया। इसमे कहा कि गया उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली सप्लाई की गई कहीं कोई कटौती नहीं है, जबकि कटौती के सम्बंध में सैंकड़ों ट्वीट ऊर्जा मंत्री से लेकर सीएम तक को किए गए थे।

अधिकारियों के इस खेल पर शासन ने कल दोपहर बाद चीफ इंजीनियर मुकेश मित्तल का तबादला मेरठ कर दिया। बताया जा रहा है कि मुकेश मित्तल की शासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जनता से वह दूरी बनाकर रखते थे तो अधीनस्थ से भी उनका तालमेल खराब था जिसकी वजह से जिले में विद्युत सप्लाई को लेकर हालात लगातार बिगड़ रहे थे। ब्लैक आउट के दौरान खुद पीवीएनएल की एमडी वी चैत्रा रात भर मॉनीटिरिंग करती रहीं। सप्लाई बहाल कराने को लेकर वह खुद सब स्टेशनों का दौरा करती रहीं।

वेबसाइट पर फर्जी ब्रोकर बनकर धोखाधड़ी

- नोएडा पुलिस ने चार शातिर ठगों को किया गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

थाना सेक्टर-39 पुलिस ने प्रॉपर्टी सेल्स एंड परचेज की वेबसाइट पर फर्जी मालिक या ब्रोकर बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के चार शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग फ्लैट व कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आदि के फर्जी मालिक बनकर रेंट पर देने के नाम पर ठगी करते थे।

एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 12 जनवरी को सेक्टर-46 में मकान किराए पर दिलाने के नाम पर ठगी की शिकायत मिली थी। जिसके बाद नौ और इसी तरह की शिकायत आई। जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर इनको ट्रैक किया और बुधवार को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान अमितेश , अनिल चौहान , मृत्युंजय चौबे, पुष्पेंद्र हुई है। इन सभी को सेक्टर.46 से गिरफ्तार किया गया है।

इनके कब्जे से एक एटीएम कार्ड, 7 फर्जी आधार कार्ड, 1 पासबुक व नगद 20000 रुपए बरामद किए। एडीसीपी ने बताया कि इन लोगों ने प्रॉपर्टी सेल परचेज संबंधित वेबसाइट पर रेंट में प्रॉपर्टी को देने के लिए अपना ऐड एक मोबाइल नंबर के साथ डालते थे। जब कोई कस्टमर फ्लैट, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आदि को चैक करता है तो इनके के मोबाइल नंबर पर उन कस्टमर का फोन नंबर नाम के साथ आ जाता था।

आरोपी अमितेश मिश्रा प्रॉपर्टी की लोकेशन व किराया को लेकर बात करता था। वहीं कस्टमर से फ्लैट को विजिट करने का समय निर्धारित करता है। समय निर्धारित होने के बाद पुष्पेन्द्र कस्टमर को फ्लैट विजिट कराता था।

अट्टा मार्केट सेक्टर-27 में अनाधिकृत/नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चालान और टोइंग करती पुलिस।

ICICI Bank

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग दिल्ली- 110005

सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी

[नियम 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुन: निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।

सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्जदार एवं ज़मानतदार को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति के संरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/ अधिभारित है। उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" एवं "जिस भी स्थिति में है" के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कर्ज़दार (रों)/ सह-कर्ज़दारों/ गारंटरों का नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	संपत्तियों निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	मिस्टर फ्रेंच अरेबियन अरोमा, नीता बेदी, सुबीर बेदी, मेसर्स इटियोशा पान (कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार) 081505500664, 081555000002, 140555000010 और 140505500288	संपत्ति संख्या 40, सेक्टर 53, चरण-1, औद्योगिक एस्टेट कुंडली, सोनीपत, हरियाणा-132103/ क्षेत्रफल -10764 वर्ग फुट	रु. 6,60,73,698.85/- (जनवरी 26, 2023 तक)	रु. 5,04,00,000/- / रु. 50,40,000/-	फरवरी 06, 2023 को दो. 02:00 बजे से दो. 04:00 बजे तक	फरवरी 24, 2023 को सु. 11:00 बजे से

ऑनलाइन नीलामी हमारी ई-नीलामी संस्था **मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** की वेबसाइट **(URL Link- https://disposalhub.com)** पर संचालित होगी। बंधकदाताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को **फरवरी 23, 2023** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर संरक्षित सम्पतियों की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (सारणी **ई** संदर्भ) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग दिल्ली- 110005** में **फरवरी 23, 2023** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज, **फरवरी 23, 2023** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करें। कृपया नोट करें कि संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहने पर वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल शाल टॉवर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग दिल्ली-110005** में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को **फरवरी 23, 2023** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैडूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **दिल्ली** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।

संपत्ति अवलोकन, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** को फोन नंबर **8584874809/ 9599281817** पर संपर्क करें।

कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसियाँ **1. मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड व 2. ओजीओ असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड** इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न हैं।

प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट **www.icicibank.com/n4p4s** पर संपर्क करें।

तिथि : फरवरी 02, 2023
स्थान : दिल्ली/एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

जागरूकता वाहन को सीडीओ ने दिखाई झंडी

गाजियाबाद। समग्र शिक्षा व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल वैन द्वारा इसका प्रचार.प्रसार जिले में किया जाएगा। इस प्रचार वैन को सीडीओ विक्रमादित्य मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन लखनऊ से चलकर गाजियाबाद आई है, यहां वैन 30 दिन तक प्रचार करेगी।

इस दौरान हर दिन चार स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। नगर क्षेत्र और चारों ब्लॉकों में छह.छह दिन इस वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद यह वैन यहां से अन्य जिले के लिए रवाना होगी। इस मौके पर बीएसए विनोद कुमार मिश्रा, डीसी गौरव त्यागी, पूनम शर्मा, विनीता त्यागी आदि मौजूद रहे।

गाड़ियों के गेट खोलकर युवकों ने किया स्टंट

सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए युवा लगातार अपनी जान जोखिम में डाल रहे

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए युवा लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा युवा चार से 5 गाड़ियों में स्टंट और हुड़दंग बाजी करते हुए नजर आए। उनके स्टंट करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।

सूरजपुर थाना क्षेत्र के पास का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में 5 गाड़ियां हैं, जिनमें करीब एक दर्जन युवक सवार है और वह स्टंट कर रहे हैं। इसमें एक गाड़ी में एक युवक गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ है, जबकि तीन युवक खिड़कियों पर बाहर बैठे हुए हैं। इसके अलावा अन्य दो गाड़ियों पर भी इसी तरह से युवक बैठे हुए हैं।

बैकग्राउंड में पीतल पीतल कर देंगे गाना चल रहा और इन लोगों के द्वारा यह स्टंट किया जा रहा है। इन युवकों के द्वारा यह वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाला गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। गाड़ियों के नंबर को ट्रेस करने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौतमबुद्ध नगर में आए दिन इसी तरह के स्टंट करने के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ जमकर कार्रवाई भी हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी स्टंट बाज अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। कार्यकारी संपादक: नवीन उपाध्याय, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879900।

राजधानी ने कमाकर दिए 1.75 लाख करोड़, मिले 325 करोड़ : केजरीवाल

सीएम बोले- इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी समस्याओं से कोई राहत नहीं मिली

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट-2023-24 पर निराशा जताई। उन्होंने इस बजट में दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि पिछले साल 1.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आयकर चुकाने के बावजूद शहर को केंद्रीय बजट में मात्र 325 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

इस बजट में में महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी समस्याओं से कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक के बाद एक किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में कहा इस बजट में मंहगाई से कोई राहत नहीं है।

उल्टे इस बजट से मंहगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। शिक्षा बजट को 2.64 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट को 2.2 फीसदी से घटाकर 1.98 प्रतिशत करना हानिकारक है।

केंद्र ने बोला ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है लेकिन जिस वक्त देश का हर दसवां युवा बेरोजगार है, जिनके पास रोजगार है उनकी आय भी बहुत कम है। ये देख कर समझना पड़ेगा की दुनिया ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। इस बजट में बेरोजगारी से लड़ने का कोई विजन नहीं है। दुनियाभर की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी से लड़ने के लिए खपत को बढ़ाया गया क्योंकि खपत बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और इससे रोजगार का सृजन होता है लेकिन इस बजट में खपत बढाने पर भी कोई काम नहीं किया गया।

भारत में एक बड़ा खपत बाजार है और सारी दुनिया इसे मार्केट के रूप में देख रही है लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुछ काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी दूर करने के लिए विजन चाहिए।

खान मार्केट में टीवी पर बजट का सीधा प्रसारण देखते दिल्ली के व्यापारी। फोटो: रंजन डिमरी

देश को कर्ज में डुबा देगा बजट : सिसोदिया

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने खतरनाक बजट दिया है। 45 लाख करोड़ के बजट में 15 लाख करोड़ का कर्जा है इससे देश पर महंगाई की मार पड़ेगी। ये कुछ अरबपतियों को फायदा पहुँचाने और देश को 15 लाख करोड़ रूपये के और कर्जे में झोंकने का बजट है। देश में बेरोजगारी दर 8.3फीसदी लेकिन फिर भी बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई विजन नहीं है। मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। इन दोनों कार्यकाल में इन्होंने अच्छे दिन को जुमला करार दिया। नौकरी देने के वादे को जुमला करार दिया और अब दोबारा एक ऐसा बजट लेकर आये है जिसमें केवल जुमला और जुमला है। वर्ष 2014 के बजट के बाद भी इस सरकार से बुलेट ट्रेन लाने से लेकर किसानों की आय को दोगुना करने सहित पिछले साल के बजट में 60 लाख नौकरी देने का जुमला सुन चुके है ।

रैपिड रेल के लिए 3596 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में देश के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 3596 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया वर्तमान में देश के पहले 82 किमी लंबे आरआरटीएस कॉरिडोर (दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर) का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस आरआरटीएस कॉरिडोर में दो डिपो और एक स्टेबलिंग यार्ड समेत 25 स्टेशन बनाए जायंगे। पूरे कॉरिडोर पर 14 हजार से अधिक मजदूर और 1100 इंजीनियर काम कर रहे हैं। कॉरिडोर के लिए अब तक 35 फीसदी सुरंग के अलावा 65 फीसदी एलिवेटेड वायाडक्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

दिल्ली पुलिस को पहले से ज्यादा मिले

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस को 2023-24 के केंद्रीय बजट में 11,933.03 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15.22 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालती है। साथ ही दिल्ली पुलिस शहर में यातायात प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। यह आवंटन नियमित खर्चों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए है। वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए, दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 10,096.29 करोड़ रुपए था। हालांकि, इसी अवधि के लिए इसे संशोधित कर 11,617.59 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

सभी का हित, बढ़ेंगे रोजगार: भाजपा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा

प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि 2023-24 के लिये आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट अमृत काल का पहला बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार का रोजगार सृजन करने वाला सर्वहितकारी बजट है।

यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर समाज के उच्चतम व्यक्ति तक के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बजट में युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, निवेशकों एवं उद्योग जगत समेत सभी के लिये कुछ न कुछ सार्थक लेकर आया है। यह एक समग्र बजट तो है ही, साथ ही ग्रीन बजट भी है। वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आय कर छूट सीमा 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये किये जाने से शहर में रहने वाले निम्न मध्यम वर्ग को लाभ होगा तो वहीं यह बजट जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को भी लाभान्वित करेगा। देशभर के 48 लाख युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर योजना से लाभ मिलेगा।

नियमित फैक्ट्री लाइसेंस की स्वीकृति मिलेगी ऑनलाइन

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने फैक्ट्री मालिकों और व्यापारियों की सुविधा के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत नियमित फैक्ट्री लाइसेंस की ऑनलाइन स्वीकृति 9 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

इस नई योजना के तहत नियमित फैक्ट्री लाइसेंस की ऑनलाइन स्वीकृति 9 दिनों के भीतर दी जाएगी, अगर नागरिक द्वारा किया गया आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होगा। ऑनलाइन प्रणाली में एक इनबिल्ट सिस्टम जिसके द्वारा फैक्ट्री लाइसेंस आवेदन 3 दिनों के बाद स्वीकृति के लिए अगले वरिष्ठ अधिकारी तक स्वत: पहुँच जाएगा, यदि आवेदन 3 दिनों तक प्रोसेस नहीं हुआ है। दिल्ली नगर निगम का यह सकारात्मक प्रयास कर रहा है।

छह फरवरी को मिलेगा नया मेयर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

एलजी ने एमसीडी की बैठक बुलाने को दी मंजूरी, इससे पहले 2 बार टल चुका है चुनाव

मेयर के चुनाव के लिए एक बार फिर तारीख तय कर दी गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 6 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए एमसीडी का हाउस सत्र बुला ने की मंजूरी दे दी है।

अब सोमवार को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए पार्षद मतदान करेंगे। इससे पहले छह और 24 जनवरी को हंगामे के चलते दिल्ली मेयर का चुनाव दो बार टल चुका है। राजनिवास के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को इस तारीख का प्रस्ताव दिया था। महापौर चुनाव के लिए उपराज्यपाल ने छह फरवरी को एमसीडी सदन का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि एमसीडी की स्थगित हुई पहली बैठक आयोजित करने के लिए उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों ने सोमवार को बताया था कि एमसीडी ने महापौर के चुनाव के लिए 10 फरवरी को सदन का सत्र बुलाने का प्रस्ताव दिया था।

वहीं, केजरीवाल सरकार ने तीन तारीखों- तीन, चार और छह फरवरी का सुझाव दिया था। आप और भाजपा के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी।

बाल आयोग में शिकायत करना हुआ और आसान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र किया जारी

चैटबॉट को लॉन्च करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा चैटबॉट बाल मित्र आयोग द्वारा शुरू किया गया, गवर्नेंस को सिटीजन-फ्रेंडली बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल है।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत पंजीकरण, सूचना खोजना और शिकायत की स्थिति पर नजर रखना और दाखिले की जानकारी मांगना आसान हो गया है। आयोग ने व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र शुरू किया है। बच्चों और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ, यह चैटबॉट इसके माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को डीसीपीसीआर का नया चैटबॉट का उद्घाटन किया। बाल अधिकार आयोग द्वारा विकसित यह अनूठा चैटबॉट लोगों और आयोग के बीच संवाद को सुगम बनाने का एक प्रयास है। चैटबॉट नागरिकों और आयोग को अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत करने में मदद करेगा।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के और नागरिकों के बीच संवादहीनता को खत्म करेगा। इससे पहले आयोग ने अर्ली वार्निंग सिस्टम की शुरू किया था, जिसने शिक्षा विभाग को 50 हजार से अधिक छात्रों को स्कूलों में वापस लाने और ड्रॉपआउट दरों को कम करने में मदद की है। मालूम हो कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली सरकार की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वैधानिक संस्था है जो बच्चों के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा पर काम करती है। आयोग विज्ञापनों, सोशल मीडिया, जन सुनवाई, शिविरों आदि के माध्यम से जनता के लिए कई आउटरीच प्रयास कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में संकटग्रस्त और उच्च जोखिम वाले बच्चों की जरूरतों के लिए आयोग को अधिक सुलभ, कुशल बनाने के लिए एक व्हाट्सएप-आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है। चैटबॉट संबंधित जानकारी देते हुए डीसीपीसीआर के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने कहा यह एक ऑटोमेटेड रिस्पांस एप्लिकेशन है जो सूचना वितरण में सहायता करेगा, लोगों को शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा, शिकायतकर्ताओं के साथ नियमित संचार आदि करने में मदद करेगा।

इस मौके पर शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने कहा चैटबॉट बाल मित्र शिक्षा निदेशालय के लिए भी बहुत मददगार होगा, क्योंकि यह डीओई को पूरी दिल्ली में बेहतर तरीके से बच्चों की शिक्षा से जुड़ी जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। पहले भी डीसीपीसीआर ने शिक्षा निदेशालय को अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ काफी सहयोग प्रदान किया है।

बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया

अमृतकाल का अमृत कलशः अश्विनी चौबे

केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अमृतकाल का यह बजट देश के लिए अमृत कलश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश किया है, वो अमृत काल में सशक्त, समृद्ध व शक्तिशाली नए भारत की नींव रखेगा। यह बजट देश के गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के साथ जन-जन की आकांक्षाओं, उम्मीदों को पूरा करने वाला है। केंद्रीय राज्यमंत्री चौबे ने सर्वसमावेशी और लोक-कल्याणकारी बजट के लिए वित्तमंत्री को बधाई दी है।

"इस साल का बजट काफी अच्छा है। इस बात की खुशी है इस बार के बजट में स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए हेल्थ केयर बजट में बढ़ोत्तरी की गई है। 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय अच्छा है। इससे मरीजों को फायदा होगा। अगर चैरिटेबल अस्पतालों के लिए भी कुछ कहा जाता तो और भी अच्छा होता। साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और अनुसंधान करने के लिए धन और प्रोत्साहन पर कुछ ध्यान देना दिया जाता तो यह स्वागत योग्य कदम होता।"

-डॉ. अजय स्वरूप अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड सर गंगा राम अस्पताल

"बजट में युवाओं, किसानों, डिजिटल इंडिया, प्राकृतिक खेती, पर्यावरण के लिए बहुत सी योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन जब तक इनका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इनका लाभ नहीं हो पाएगा। पेंशनर्स को भी इनकम टैक्स में राहत मिली है। जहां सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव इनकेशमेन्ट की सीमा को 5 लाख से 25 लाख किया गया है लेकिन इसका लाभ बाकी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिल पायेगा।"

-अशवनी, फाउंडर वॉयस ऑफ बैंकिंग

"बजट से औषधि निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए घोषित नए कार्यक्रम से औषधियों की गुणवत्ता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। सहयोग परक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देने से रोगों का जल्दी पता लग पाएगा जिससे गंभीर रोगों से होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी।"

-डॉक्टर आर. पी. पाराशर, सीएमओ

"बजट में वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक के प्रीमियम के बीमा पॉलिसी पर कर के दायरे में लाने से लोगों की बचत करने की योजना प्रभावित होगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। सरकार के इस फैसले से बीमा बचत की योजनाएं प्रभावित होंगी।"

-डॉ. अनिल तोमर
समूह चिकित्सा निदेशक, नवीन अस्पताल

"वर्ष 2023 -24 के बजट में सभी वर्गों के छात्रों व युवाओं के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा व शोध के क्षेत्र में नए बदलाव आएंगे। वित्त मंत्री ने वर्ष 2023-24 में शिक्षा के लिए 112899 करोड़ रुपये आबंटित किए है जबकि गत वर्ष शिक्षा के लिए 1,04, 278 करोड़ रुपए आबंटित किए थे जो कि पिछले वर्ष के बजट से 8.26 फीसदी की वृद्धि हुई है। बजट में कौशल शिक्षा पर भी अधिक जोर दिया गया है। नए टीचर ट्रेनिंग के लिए संस्थान खोलने , बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की बात कही गई है जो काफी अच्छा कदम है।"

-डॉ. हंसराज सुमन, फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन

"यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को संबल देने वाला है। हेल्थ सेक्टर में भी उठाये गए कदम बहुत जनोपयोगी हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा लैब की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए नई मशीन लाने की बात हो, उससे रोगियों को फायदा मिलेगा। क्योंकि भारत में नई मशीन आने से बड़ी से बड़ी बीमारी का सफल इलाज किया जा सकेगा। वहीं 2027 तक एनीमिया की बीमारी को जड़ से खत्म करने का जो प्रण किया गया है उससे अनेक लोगों की जान बचाई जा सकेगी।"

-डॉ पी.एन अरोड़ा
सीएमडी, यशोदा हॉस्पिटल

"केंद्र सरकार ने बजट में फार्मा सेक्टर पर अधिक पूंजी आंवटन स्वागत किया जाना चाहिए। इससे लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध होगी। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज और स्वास्थ्य सेवा में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा से मरीजों को लाभ मिलेगा।"

-डॉ. कनिका सूद, कैंसर रोग विशेषज्ञ, धर्मशिला अस्पताल

"केंद्र सरकार ने यह बजट वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया है। सरकार ने किसी बड़े सुधार की घोषणा नहीं की है। जिससे देश की अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार का नीतिगत प्रयास नहीं किया गया है। मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास नहीं किया गया है।"

-तब्बसुम हक जैन, उद्यमी

"केंद्र सरकार ने इस बजट में नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते आयकर में अधिक छूट देकर राहत देने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। अच्छे बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई।"

-अंजू मेहरा, शिक्षिका व गृहणी

"केंद्रीय बजट में सरकार ने यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखकर बनाया है, कर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख करने से लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार ने इस बजट में सभी का ख्याल रखते हुए एक अच्छा बजट पेश किया है।"

-रितु कुमारी, शिक्षिका

"वित्त मंत्री ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने से मध्यमवर्गीय परिवार को लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार से निवेदन है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कमी करने के बजाय बढ़ाना चाहिए था। कोविड महामारी के बाद आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक जरूरत है।"

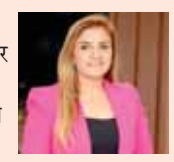

- नीना सिंह, मेकअप आर्टिस्ट

"केंद्र सरकार ने इस बजट में खेती और किसानों के हित में कई दूरगामी अच्छे परिणाम वाले कदम उठायें है फिर भी किसानों की अपेक्षा और अधिक थी। हाल ही में किसानों ने कोविड के दौरान कोई मुनाफा नहीं कमाते हुए देश की और जनता की सेवा की थी। उसके बाद कृषि सामानों में वृद्धि के कारण परेशानी झोल रहा है। इसी का निदान बजट में ढूंढ रहा था जो नहीं मिला, जैसे किसान सम्मान निधि में वृद्धि और कृषि सामानों की खरीद पर जीएसटी में कमी"

-मोहिनी मोहन मिश्रा,
राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान संघ

"वित्त मंत्री ने आयकर की छूट को 7 लाख की बजाय 15 लाख करना चाहिए था। इससे नौकरी पेशा और मध्यमवर्ग के लोगों को तो लाभ मिलेगा लेकिन व्यापारी वर्ग अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। सरकार को नौकरी पेशा लोगों के पेंशन बहाली पर ध्यान देना चाहिए।"

-ताराचंद जैन, व्यापारी, सदर बाजार

"फर्नीचर का काम मझौले व्यापार की रीढ़ है। कई दशक से लगातार इसमें लागत बढ़ रही है। कच्चे माल पर जहां सरकार ने 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया, जो आज के दौर में काफी महंगा है। मौजूदा बजट में सरकार व्यापारियों पर पूरी चुप्पी साधे हुए है।"

-जुहैर सैफी, फर्नीचर व्यापारी

"चमड़े का जूता उद्योग संकट में है। बड़ी कंपनियां चीनी से कच्चा माल मांगा रही है। इससे भारतीय व्यापारियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी को कम करने की मांग सरकार पूरी कर चुकी है लेकिन अब जरूरत मझौले कारखानों को प्रत्साहित करने की है ताकि भारतीय जूता उद्योग एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सके।"

रवींद्र कुमार, व्यापारी

गुरुग्राम में इजराइली तकनीक से तैयार की जा रही सब्जियों की पौध

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

गुरुग्राम में इजराइली तकनीक से सब्जियों की पौध तैयारी की जा रही है। यह तकनीक किसानों को अच्छी गुणवत्ता की पौध देने के उद्देश्य से एक हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस के माध्यम से तैयार की गई है। उद्यान विभाग हरियाणा की तरफ से गुरुग्राम में किसानों के लिए यह अच्छी शुरुआत है। अपनी पसंद से संबंधित फसल का बीज देकर उसकी पौध तैयार करवा सकते हैं।

पांच लाख पौधों के तैयार करने की क्षमता रखने वाली इस हाईटेक नर्सरी में किसानों से बेल वाली सब्जियों के पौध उत्पादन के लिए उस पर लगने वाली लागत एक रुपये बीस पैसा प्रति पौधा व अन्य

नर्सरी में तैयार पौध पर किसानों को दिया जा रहा अनुदान योजना का लाभ

सब्जियों के लिए एक रुपया चालीस पैसा उत्पादन खर्च लिया जाएगा। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मुताबिक पौध तैयार होने के उपरांत खुले खेत में फसल तैयार करने वाले किसानों को प्रति पौधा एक रुपया व संरक्षित संरचना में खेती करने वाले किसान को चार रुपये पच्चीस पैसा प्रति पौध की दर से अनुदान दिया जाएगा। अनुदान योजना का लाभ केवल हरियाणा के किसानों को ही दिया जाएगा।

अगेती व पछेती फसल के रूप में कर

गुरुग्राम के उद्यान विभाग की नर्सरी में तैयार पौधों की देखरेख करती कर्मचारी।

सकते हैं रोपण : इस योजना के माध्यम से किसान इस पौधे को खेत में रोपित कर अगेती व पछेती फसल का लाभ उठा सकते हैं। नर्सरी में तैयार पौधे में खासियत यह है कि इसमें रोग लगने की संभावना कम रहती है और पौधा समय से अच्छी फसल देने लगता है। डॉ. नेहा ने कहा कि सब्जी व फल की खेती में बाजार भाव ही किसानों की आय का निर्धारण करता है। अच्छा भाव मिल जाने पर किसान की आय में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। यह तभी संभव है कि जब फसल पहले व बाद में मिले। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम सहित साथ लगते अन्य जिलों के किसान भी इस हाईटेक नर्सरी में तैयार पौध का लाभ उठाकर संरक्षित संरचना के माध्यम से मनचाहे समय पर फसल हासिल कर सकते हैं।

हाईटेक नर्सरी में बिना मिट्टी के पौध होती है तैयार

जिला बागवानी अधिकारी डॉ. नेहा यादव ने बताया कि ये पौध हाईटेक नर्सरी में बिना मिट्टी के पौध तैयार की जाती है, जिससे मिट्टी से आने वाली बीमारियों का खतरा नहीं रहता। वहीं कम समय में पौध तैयार होने के चलते किसानों का समय भी बचता है। इस नर्सरी के माध्यम से किसान अपनी फसल की पौध का सर्दी, गर्मी व वर्षा से बचाव करते हुए ऑफ सीजन की पौध भी तैयार करवा सकते हैं। किसान के खेत में अगर फसल खड़ी है तो किसान यहां से पौध तैयार करवाकर अपना समय भी बचा सकते हैं। डॉ. नेहा ने बताया कि नर्सरी में पौध तैयार करवाने के इच्छुक किसान पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र व बीज खरीद का ओरिजिनल बिल सहित जिला बागवानी अधिकारी गुरुग्राम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।

बच्चे के जन्म वाले दिन ही जन्म प्रमाणपत्र पाकर परिजन हुए खुश

सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में बुधवार को जन्मे बच्चे की मां को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सौंपते सिविल सर्जन डा. विरेंद्र यादव

सिविल सर्जन ने इस सुविधा की शुरुआत के साथ मिठाई भी बांटी

फिलहाल सरकारी डिलीवरी हट में पैदा होने वाले बच्चों के बनेंगे सर्टिफिकेट

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को एक नई शुरुआत की गई। अब नागरिक अस्पताल में जन्म लेने वाले हर बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र उसी दिन ही जारी होगा। बुधवार को जन्में सभी बच्चों की माताओं को सिविल सर्जन डा. विरेंद्र यादव ने जन्म प्रमाणपत्र देकर इसकी शुरुआत की। साथ ही इन माओं को मिठाई भी वितरित की गई।

इस कार्य को सिरे चढ़ाने की योजना कई दिन से तैयार की जा रही थी। गणतंत्र दिवस पर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में सिविल सर्जन डा. विरेंद्र यादव ने कहा था कि बच्चे के जन्म वाले दिन ही उसका जन्म प्रमाणपत्र एक फरवरी से जारी करने की शुरुआत होगी। बुधवार को विधिवत रूप से इसकी शुरुआत सिविल सर्जन की ओर से की गई। उन्होंने इस कार्य के लिए अस्पताल के अधिकारियों, स्टाफ के काम को भी सराहा। उन्होंने कहा कि यह सबके प्रयासों से अच्छी शुरुआत है। भविष्य में कभी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में समय न लगे। जिस दिन बच्चे का जन्म हो, उसी दिन यह तैयार करके दे दिया जाए।

फिलहाल सरकारी अस्पतालों, डिलीवरी हट में सुविधा : डिप्टी सिविल सर्जन एवं एडिशनल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण डा. नीलिमा ने बताया कि जन्म के दिन ही जन्म प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के डिलीवरी हट पर ही शुरू की गई है। जिले में छह स्थानों गुरुग्राम नागरिक अस्पताल सेक्टर-10, पटौदी अस्पताल, सोहना अस्पताल के अलावा बोहड़ाकलां डिलीवरी हट, मंदपुरा डिलीवरी हट और घंघोला डिलीवरी हट में जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म के दिन ही प्रमाणपत्र बनाने की सुविधा होगी। काफी एरिया नगर निगम गुरुग्राम, नगर निगम मानेसर में आता है। इसके लिए नगर निगमों को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों की ओर से डेटा निगमों को जल्दी भेजा जाएगा तो वहां भी यह सुविधा शुरू हो सकती है।

सांध्यकालीन ओपीडी की भी शुरुआत : बुधवार से ही अस्पताल में सांध्यकालीन ओपीडी की भी शुरुआत की गई। सांय की ओपीडी में ड्यूटी देने वाले स्टाफ का पूरा खाका तैयार करके अस्पताल में जगह-जगह पर चस्पा दिया गया, ताकि सभी को अपनी ड्यूटी के बारे में जानकारी रहे। सिविल सर्जन डा. विरेंद्र यादव ने कहा कि पुराने ढर्रे पर काम करने की बजाय हमें समय के साथ चलते हुए काम में कुछ बदलाव चाहिए। मरीजों को अच्छी, समय पर सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए।

सरकार हर वर्ष सभी संत-महात्माओं की जयंती मनाएगी

सोहना के अंबेडकर भवन में बुधवार को पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता शुक्रवार को मनाई जाने वाली गुरुग्राम में संत गुरु रविदास की जयंती में शामिल होने का न्यौता देते हुए।

सोहना। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने प्रदेश में सभी संत व महात्माओं की जयंती मनाने का फैसला लिया है। इस क्रम में संत गुरु रविदास की जयंती प्रदेश में शुक्रवार को तीन स्थानों पर मनाई जाएगी।

सत्यप्रकाश जरावता बुधवार को सोहना के अंबेडकर भवन में पहुंचे थे। यहां उन्होंने लोगों को शुक्रवार को गुरुग्राम में मनाई जा रही संत गुरु रविदास जयंती में भारी संख्या में पहुंचने का न्यौता दिया। जरावता ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने फैसला लिया है कि महापुरुषों की तरह से संत व महात्माओं की जयंती भी मनाई जाएगी। इसके माध्यम से नवयुवकों को संत महात्माहों के जीवन से ज्ञान प्राप्त होगा। मनोहर लाल सरकार सभी वर्ग के लोगों को समान सम्मान देने और जनकल्याणकारी योजनाओं में एक समान लाभ दे रही है। चिरायु योजना से आज राज्य में सवा करोड़ नागरिकों को लाभ दिया जा रहा है। जबकि हरियाणा की कुल आबादी-सत्ताइस करोड़ है। इतना लाभ चिरायु के माध्यम से देश के किसी अन्य राज्य के नागरिकों को नहीं मिला है। सामाजिक संगठन और संस्थाओं को राज्य सरकार की जनकल्याणाकारी नीतियों को जानने के बाद उन्हे जनजन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। जिससे सरकार की योजनाओं से अंजान व गरीब नागरिकों तक उनका लाभ पहुंच से। गुरुग्राम में संत रविदास जयंती के अवसर पर राजस्थान से सांसद अर्जुनराम मेघवाल होंगे। इस मौके पर उनके साथ बीरसिंह नंबरदार, मूलचंद नंबरदार, सुभाष कोहली, भारत भीमवाल, नगर परिषद पार्षद टेकचंद, ओमप्रकाश, बलबीर, सुशील रोहिल्ला व योगेश तवंर आदि मौजूद रहे।

विधायक जरावता ने संत रविदास की जयंती समारोह का दिया न्यौता

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में संत रविदास जी की जयंती समारोह के लिए गांव सिकन्दरपुर बढ़ा के अम्बेडकर भवन में पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता का गांव में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक ने बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष भी नमन किया।

विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने गांव में लोगों को जयंती समारोह में शामिल होने का न्यौता दिया। गांव की तरफ से रामानन्द, गोकल सूबेदार, धर्म सिंह, हरकेश नंबरदार, मनोहर लाल, जगदीश, कुलदीप, ब्लाक मेम्बर राजीव, मेम्बर प्रवीन सहित गांव के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। गांव की तरफ से विधायक को भरोसा दिलाया गया कि रविदास जी की जयंती समारोह में बड़ी संख्या में गांव से समाज के लोग शामिल होंगे। विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि महापुरुषों की बदौलत हर समाज का विकास हुआ है। समाज मुख्यधारा में आया है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलकर हम समाज

संत रविदास जयंती समारोह के लिए गांव सिकदंरपुर में लोगों को न्यौता देने के दौरान बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष नमन करते विधायक सत्यप्रकाश जरावता।

में बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर महापुरुष ने आपसी भाईचारे, एकता से रहने का संदेश दिया है।

हमें उनके संदेशों, दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में भाईचारा कायम करके रहना चाहिए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महापुरुषों की यह अच्छी सोच है कि उन्होंने हर महापुरुष की जयंती मनाने का निर्णय लिया। आज प्रदेश में महापुरुषों की जयंती धूमधाम से सरकार मना रही है। सरकार का सबका साथ सबका विकास का यह नारा भी यहां साकार हो रहा है।

नगर परिषद के सभी वार्ड 21 फरवरी तक स्ट्रीट लाइट से जगमग होंगे

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

नगर परिषद सीमा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के कार्य पर उठ रहे सवालों को लेकर विधायक संजय सिंह ने ठेकेदार को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पर ठेकेदार ने 21 फरवरी तक सभी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने के लिए तीन टीमों का गठन किया है। सभी टीम एक दिन में एक ही वार्ड की सभी खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करेंगी।

शहर में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की कवायाद 10 जनवरी से शुरु की गई थी। लेकिन स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने का कार्य धीमी गति से चलने के कारण परिषद की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगने लगे थे। फॉरचून एजेंसी के

नगर परिषद सीमा क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करते हुए एजेंसी कर्मचारी।

कर्मचारी एक दिन में 25 से 30 स्ट्रीट लाइटों को ही ठीक कर रहे थे। उक्त समस्या को स्थानीय नागरिकों ने सोशल मिडिया पर वायरल करके परिषद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कार्य धीमा कराने का आरोप लगाया था। अब विधायक संजय सिंह ने जल्द ही और गति देने के लिए ठेकेदार को दिशा निर्देश जारी कर दिए है।

इतना ही नहीं विधायक संजय सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्ट्रीट लाइटों को ठीक कर रही एजेंसी के कर्मचारियों लेकर निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के मोबाइल नंबर तक सोशल मीडिया पर डाल दिए है। जिसके लिए 31 जनवरी से 21 फरवरी तक परिषद के सभी 21 वार्ड के आम रास्तों लेकर चौक-चौराहे और सड़के स्ट्रीट लाइट से जगमग होंगे। सोशल मीडिया पर स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाली टीम का दिन और तारीख डाल दिया है। विधायक संजय सिंह ने ठीक करने वाली एजेंसी के मालिक को कड़े और सख्त दिशा निर्देश दे दिए है।

दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक व्यवस्था बना भारत : ओमप्रकाश धनखड़

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

अमृत काल के पहले बजट में देश के समग्र विकास की गति बढ़ाने और समाज के हर वर्ग के उत्थान का ध्यान रखा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा भविष्य लक्षित बजट पेश करने पर धन्यवाद करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरे पायदान की ओर अग्रसर होगा।

धनखड़ ने कहा कि बजट में देश के 80 करोड़ लोगों के लिए निशुल्क राशन की अवधि एक वर्ष और बढ़ाना, आयकर सीमा सात लाख रुपये करना, रेलवे के लिए अब तक सर्वाधिक बजट दो लाख चालीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देना, एक जिला-एक उत्पाद, सीवरेज मैनहोल की सफाई मशीनों से करवाना, किसानों के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रूपये, कारीगरों व शिल्पकारों के

ओमप्रकाश धनखड़।

देश के समग्र विकास की गति बढ़ाएगा अमृत काल का पहला बजट

वंचितों को वरीयता, सहकार से समृद्धि और सभी के हितों का रखा ध्यान

उत्पादों को एमएसएमई की मूल्य श्रृखंला से जोड़ते हुए गुणवत्ता में सुधार करना, 740 नये एकलव्य स्कूल व 157 नर्सिंग कॉलेज खोलना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाने की तैयारी, गरीबों को मकान देने के लिए पीएम आवास योजना के खर्च में 66 फीसदी बढ़ोतरी, पूंजीगत निवेश बढ़कर दस लाख करोड़ और ढांचागत विकास पर खर्च बढ़कर दस लाख करोड़ रूपये होना तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की ओर शुभ संकेत हैं। ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि अमृत काल के प्रथम बजट में देश के समग्र विकास, किसानों, महिलाओं, युवाओं, ओबीसी, एससीएसटी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को बढ़ावा दिया गया है। बजट में वंचितों को वरीयता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाते हुए फसल, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, एग्रीटेक उद्योग और स्टार्टअप से जोड़ा जाएगा।

बजट से आम जनता के मुद्दे गायब, सिर्फ दिखावे का बजट

प्रवीन शर्मा। गुरुग्राम

राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष एवं हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अशोक बुवानीवाला ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये आम बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे देशहित में कहा जा सके। बजट में आम जनता के मुद्दों को गायब करके सिर्फ गुमराह ही किया गया है।

बजट में नौकरीपेशा के लिए कुछ नहीं, युवाओं को कुछ नहीं, किसानों को कुछ नहीं और उद्योगों को कुछ नहीं दिया गया। छलावे जैसा यह बजट पेश किया गया है। रक्षा क्षेत्र को लेकर बजट में कुछ नहीं कहा गया। महंगाई से देश की जनता पिस रही है, लेकिन महंगाई का 'म' बोलने से भी वित्त मंत्री ने परहेज किया। जिस दौर में बजट पेश किया गया है, उस दौर में देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। इसके बावजूद सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया।

आज जनता के लिए टैक्स स्लैब में कोई राहत ना देकर फिर से जनता को सरकार ने ठगा है। यह बजट

अशोक बुवानीवाला।

सिर्फ उन उद्योगपतियों की जेबें भरने वाला है, जिनके पास देश का 80 प्रतिशत राजस्व है।

उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास तक नहीं किया गया। जबकि मध्यम वर्ग ही सबसे अधिक टैक्स देता है। बजट में अर्थव्यवस्था में सुधार और रोजगार जैसे अहम पहलुओं से तो दूरी ही बनाई गई है। किसानों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की भी सीधे अनदेखी की गई है। इनकम टैक्स की बात करें तो मात्र तीन लाख रुपये सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं होना जनता पर कोई मेहरबानी नहीं कही जा सकती।

वी-लॉजिस ने गाजियाबाद में नई वेयरहाउस सुविधा का उद्घाटन किया

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

वी-ट्रांस (इंडिया) लिमिटेड के एक प्रभाग और भूतल परिवहन से संबंधित मल्टीमॉडल एक्सप्रेस कार्गो मूवमेंट, वेयरहाउसिंग, थ्री पीएल, और ईकामर्स समाधान देने वाली कंपनी वी-लॉजिस ने गाजियाबाद में अपना फुली कम्प्लाइन्स ए-ग्रेड वेयरहाउस लॉन्च किया। 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में नवनिर्मित, यह हब लगभग 15 प्रत्यक्ष और 200 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार देगा। इस नए लॉन्च के साथ, वी-लॉजिस की अब पूरे उत्तरी भारत में 10 से अधिक शाखाएं और 11 हब सेंटर्स हैं।

यह सुविधा रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर स्थापित की गई है, जो बुलंदशहर वाया गाजियाबाद-कानपुर राजमार्ग के रूप में भी जाना जाता है, और आसपास के शहरों से से सीधा जुड़ा हुआ है। पिछले 63 वर्षों से उद्योग में होने के नाते, वी-लॉजिस एक मजबूत और तेज प्रबंधन टीम के साथ के सबसे बड़े उद्योग क्षेत्र में से एक को सेवाएं दे रहा है। प्रतिबद्ध और कुशल टीम के साथ वी-लॉजिस विभिन्न उद्योग आधारित निर्माता ग्राहकों को सेवा दे रहा है। उनके पास उत्तम और प्रभावी देखभाल के साथ विभिन्न उद्योगों के लिए कार्गो हैंडलिंग की विशेषज्ञता है और ग्राहकों की आवश्यकतानुसार समाधान देते हैं। उत्तम तकनीक से संचालन, विस्तृत नेटवर्क, उन्नत कार्यदल और चुस्त मैनेजमेंट प्रेक्टिस के जरिए वी-लॉजिस, माल का पूरी पारदर्शिता के साथ तेज और नुकसान मुक्त परिवहन सुनिश्चित करते हैं।

शहर में संचालित कई बड़े उद्योगों और छोटे उद्यमों के साथ यह सुविधा एक प्रमुख औद्योगिक हब है। गाजियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांस-हिंडन औद्योगिक क्षेत्र और हिंडन विहार औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। गाजियाबाद सबसे पुराने और सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, जहां छोटे और मध्यम आकार के इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स उद्यम संचालित हैं। ट्रांस-हिंडन औद्योगिक क्षेत्र और साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने के कपड़ा, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग हैं।

महेंद्र शाह, ग्रुप चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, वी-ट्रांस (इंडिया) लिमिटेड ने कहा कि हम भारत के ऑइल इंजन उद्योग के सबसे प्रसिद्ध केंद्रों में से एक, गाजियाबाद में अपने कारोबार का विस्तार करके बहुत खुश हैं। वी-लॉजिस औद्योगिक हब का हमारी विकास रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सीमा दिल्ली से सटी हुई है और यह उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। वी-ट्रांस भारत के साथ-साथ सार्क देशों के व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र जैसे प्रौद्योगिकी से लेकर टीम के निर्माण तक, ब्रांड इमेज को बढ़ावा देने से तकनीकी विकास और बुनियादी ढांचे तक में काम करने वाली एक विकासशील लॉजिस्टिक समाधान प्रदाता कम्पनी है ।

संक्षिप्त समाचार

देश के हर नागरिक के हितों की रक्षा वाला आम बजट

गुरुग्राम। गुरुग्राम में विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट देश के हर नागरिक के हितों की रक्षा वाला है। हर नागरिकों को इस बजट में शामिल करके राहत देने का काम किया गया है। रोजगार की बात करें तो पीएम 4.0 पीएम कौशल विकास योजना देश के युवाओं को राहत देगी। विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग दिलवाकर उनका भविष्य संवारा जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए 2027 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। साल 2047 तक बच्चों में खून की कमी को दूर किया जाएगा। भविष्य में मैनहोल साफ करने के लिए उसके अंदर आदमी नहीं उतरेंगे। इसके लिए अलग से सफाई योजना तैयार होगी। यह सारा काम मशीनों से ही किया जाएगा। हालांकि पहले से इस कार्य को किया भी जा रहा है। रोजगार सृजित करने और छोटे उद्योगों को मजबूत करने के लिए सरकार काफी कदम उठा रही है। महिलाओं के प्रोडक्ट को बाजार में पहुंचाने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। हरित तकनीक और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं से एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को काफी मजबूती मिल रही है। विधायक सुधीर सिंगला ने बताया कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज केंद्र सरकार दे रही है। वसुधैव कटुंबमकम थीम पर आम लोगों के लिए एजेंडा तय करके स्थायी विकास की कोशिश की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। पिछले 9 साल में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह बड़ी उपलब्धि है।

विधायक सुधीर सिंगला।

आम बजट में पर्यावरण, स्वास्थ्य की चिंता क्रांतिकारी शुरुआत

गुरुग्राम। पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारत के आम बजट में इस बार देश के हर नागरिक की सेहत की चिंता करते हुए पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बेहतर शुरुआत की गई है। यह एक क्रांतिकारी शुरुआत है। खेती को और अधिक लाभप्रद तथा पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा महत्वपूर्ण है। नवीन गोयल ने कहा कि पर्यावरण में सुधार के लिए ई-वाहनों पर बजट में सरकार ने जोर दिया है। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों को ई-वाहनों की खरीद पर विशेष छूट मिलेगी। ई-वाहनों का चलन ही हमारे देश के स्वास्थ्य को सुधारेगा। उन्होंने कहा कि खेती, प्राकृतिक खेती, शून्य जैविक खेती और कृषि की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी इन विषयों को शामिल करना एक नया बदलाव लाएगी। सरकार पहले से पर्यावरण को सुधारने के लिए ई-वाहनों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसे में बिजली चालित वाहनों के क्षेत्र में इस तरह की पहल देश का वातावरण सुधारने में कारगर साबित होगी। इसे व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को और भी मजबूत बनाने, नये व्यापार मॉडल विकसित करने की योजना लाना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे अधिक शहरी क्षेत्रों में फैलता है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों विशेषकर महानगरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को ई-वाहनों के रूप में बदलना बड़ा बदलाव लाएगा। वायु प्रदूषण हमारे देश में बड़ी समस्या है। काफी हद तक इस निर्णय से सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बजट में ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बाजार से उधार के रूप में सावरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाने की भी घोषणा सराहनीय है। इससे हरित परियोजनाओं को साकार करने के साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में मदद मिलेगी। यह बजट समर्थ और सक्षम भारत का नया प्रयोग कहा जा सकता है।

नवीन गोयल।

यह देश की उम्मीदों का बजट: जीएल शर्मा

गुरुग्राम। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किए गए बजट को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने सभी तबके के लोगों के लिए सौगात भरा करार दिया है। शर्मा ने कहा कि भाजपा-2 के कार्यकाल में देश के दूरदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत काल का लोक कल्याणकारी बजट पेश कर देश के साथ वैश्विक आकांक्षाओं पर खरा उतरने की प्रतिबद्धता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग के सपने पूरे करने वाला होगा। यह गरीब किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला है। यह बजट न केवल देश की जनता के लिए, बल्कि विश्व की उम्मीदों को भी पूरा करने वाला बजट है। ये गरीबों का बजट है। इस बजट में नए भारत का संकल्प साफ दिखाई देता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है।

जीएल शर्मा।

खुदाई के दौरान गैस लीकेज से हो रहीं से आग की घटनाएं

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

सड़क बनाने के दौरान जेसीबी से की गई खुदाई में गैस लीक होने से लगी आग

कभी सीवरेज लाइन की खुदाई, तो कभी अन्य कामों के लिए होने वाली खुदाई के दौरान शहर में जगह-जगह पीएनजी पाइप लाइन फटने से आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी गैस कंपनियों के व्यक्तियों को मौके पर बुलाकर काम नहीं किया जाता है। ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता है।

बुधवार को भी भारत कालोनी में एक सड़क निर्माण कार्य के दौरान गैस की पाईप लाइनों पर ध्यान नहीं दिया गया। पाईप लाइन जेसीबी से खुदाई के दौरान फटने से आग लग गई। घटना में मौके पर मौजूद एक खाद्य पदार्थ विक्रेता की रेहड़ी में आग लग गई। जिससे उसकी रोजी-रोटी का सहारा छिन गया। शहर में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पाईप लाईन फटने से गैस लीकेज के कारण लगी आग का दृश्य।

पहले भी फटी लाइनें : बुधवार को नहरपार स्थित भारत कालोनी में सड़क की खुदाई के दौरान पाईप लाइन फटने से आग लग गई। करीब आधे घंटे बाद फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक रेहड़ी जलकर खाक हो गई। इससे पहले 14 दिसंबर 2020 को बल्लभगढ़ के सेक्टर-दो व 64 की डिवाईडिंग रोड पर सीवर की खुदाई के दौरान पाइप लाइन फटने से दो हजार घरों में चार घंटे गैस सप्लाई बंद हो गई थी।

तीन अप्रैल 2021 को डीएलएफ इलाके में एक कम्पनी के निकट जेसीबी से खुदाई के दौरान पीएनजी पाइप फटने से कंपनी के बाहर खड़ी कई बाइके और कार आग की चपेट में आग गई थी। 23 अक्टूबर 2021 को सारन चौक के समीप खुदाई के दौरान गैस की पाइप लाइन धमाके के साथ फट गई थी। जिससे करीब एक घंटे तक गैस लीक होती रही थी। 25 मार्च 2022 को भी बाईपास रोड पर खुदाई के दौरान गैस की पाइप लाइन फट गई थी।

लोगों का कथन : बुधवार को भारत कालोनी में आग लगने की घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि अगर जमीन की खुदाई की जाती है, तो सबसे पहले गैस पाइप लाइन वालों को बुलाना चाहिए। ताकि किसी तरह की कोई घटना घटित न हो। ऐसे में कभी बड़ी घटना भी घटित हो सकती है।

उपराष्ट्रपति करेंगे 36 वें सुरजकुंड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ

पिछली बार से दोगुनी होगी विदेशी मेहमानों की संख्या, 45 देशों के विदेशी कलाकारों सहित पूर्वोत्तर के आठ राज्य थीम स्टेट, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल भी आएंगे मेले में

पर्यटन विभाग के सचिव एमडी सिन्हा, सीपी विकास अरोडा तथा डीसी विक्रम सिंह व अन्य अधिकारी गण मेले की तैयारियों की जानकारी देते हुए।

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

भारत के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ 36 वें सुरजकुंड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को सूरजकुंड के राजहंस होटल में वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये सूरजकुंड मेला की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। पर्यटन विभाग के सचिव एमडी सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार से दोगुनी विदेशी मेहमानों की संख्या होगी,वहीं 45 देशों के विदेशी कलाकारों सहित पूर्वोत्तर के आठ राज्य थीम स्टेट, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल भी मेले में आएंगे। पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव एमडी सिन्हा ने कहा कि तीन फरवरी से शुरू होने वाला अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला इस बार अन्य वर्षों की अपेक्षा ज्यादा भव्य व विशाल होगा। उन्होंने बताया कि जी-20 समिट के चलते इस बार मेले में विदेशी मेहमानों की संख्या दोगुनी होगी। ऐसे में एंबेसेडर मीट दो दिन होगी। जी-20 से संबंधित देशों के राजदूत 9 फरवरी को आएंगे और एससीओ से संबंधित देशों के राजदूतों भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेला हमारे देश की मजबूत सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ऐसे में हमें मेले में किसी भी तरह की तैयारियों को लेकर कमी नहीं रखी गई है। उन्होंने कहा कि मेले में इस बार 45 देशों के विदेशी कलाकार हिस्सा लेंगे जिससे विदेशी कलाकारों की संख्या भी पिछले वर्षों की अपेक्षा दोगुनी रहेगी। उन्होंने बताया कि नॉर्थईस्ट के आठ स्टेट हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में इन सभी राज्यों से कलाकार आएंगे। इसके साथ ही वीआईपी भी ज्यादा संख्या में रहेंगे। इनमें नॉर्थईस्ट के आठ राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल भी आएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक दिन विदेशी पत्रकारों का एक दल भी सूरजकुंड मेला परिसर का भ्रमण करेगा। उन्होंने मेले के दौरान पार्किंग व्यवस्था अतिरिक्त करने के निर्देश दिए गए हैं ।

विडियो कान्फ्रेंस में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, उपायुक्त विक्रम सिंह, एचएसवीपी के स्टेट आफिसर कम मेला नोडल अधिकारी अमित कुमार, डीसीपी नितीश अग्रवाल, एसडीएम परमजीत चहल, एसडीएम पंकज सेतिया, सीटीएम अमित मान, पर्यटन विभाग के जीएम यूएस भारद्वाज, एजीएम हरविंद्र सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगी सूरजकुंड मेले की हर शाम

प्रवीन शर्मा। फरीदाबाद

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि 36 वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगी। टूरिज्म विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चार फरवरी से पूर्वोत्तर राज्यों का मेले में प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक मुख्य चौपाल व छोटी चौपाल पर देश के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार, थीम स्टेट पूर्वोत्तर राज्यों और पार्टनर कंट्री एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं अलग से भी प्रतिदिन विशेष कलाकार सांस्कृतिक संध्या को सुरों से सजाएंगे। मेले के सहायक नोडल अधिकारी हरिवंद्र यादव ने बताया कि उद्घाटन वाले दिन तीन फरवरी को स्पेशल क्लासिकल कोरियोग्राफी से इसकी शुरुआत होगी। हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से की गई तैयारी के अनुसार मेले में पंजाबी के साथ ही भोजपुरी गीतों की भी धूम रहेगी। चौपाल पर सूफियाना रंग भी जमेगा। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 3 फरवरी शुक्रवार को कोरियोग्राफी का रंगारंग सास्कृतिक कार्यक्रम होगा। जबकि चार फरवरी को मेजर मिनिगं के साथ पूर्वोत्तर शो टटसो बहने की रंगा रंग सास्कृतिक प्रस्तुति होगी। पांच फरवरी को गायिका मालिनी अवस्थी की प्रस्तुति होगी।

कौशल विकास की दिशा में एक और कदम

कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए प्रिंसीपल डॉ. कृष्णकांत गुप्ता।

फरीदाबाद। अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में स्किल हब इनीशिएटिव पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे सर्टिफिकेट कोर्स रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट तथा हाउसकीपिंग अटेंडेंट (मैनुअल क्लीनिंग) के सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती माता के समक्ष दीपशिखा प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. कृष्णकांत गुप्ता ने सफल छात्रों को शुभ आशीष दी, कहा कि दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम तथा जुझारू ही सफल होता है। जो विद्यार्थी किसी कारणवश पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके थे स्किल हब इनीशिएटिव के यह सर्टिफिकेट कोर्स कर मुख्यधारा में फिर से जुड़ते हैं। उन्होंने अन्य छात्रों को भी महाविद्यालय में चल रहे अलग-अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज से जुड़ने की अपील की। नोडल ऑफिसर डॉ. के.एल. कौशिक ने सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बताया। कहा कि महाविद्यालय ने सुनहरा अवसर प्रदान किया है जिसका अधिक से अधिक बच्चों को लाभ उठाना चाहिए। रोजगार पूरा के सर्टिफिकेट कोर्स सभी सरकारी तथा निजी संस्थानों में मान्य है। कार्यक्रम में कमल टंडन, ट्रेनर डॉ. डिंपल सिंघल, डॉ. पूनम रौतेला, डॉ. विनीत नागपाल, उप-अधीक्षक श्री मनमोहन सिंगला, लिपिक श्री सौरभ गुप्ता और श्री महेंद्र कुमार तथा विभिन्न कोर्स के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। सफल विद्यार्थी प्रमाण पत्र पाने को अति उत्सुक थे। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के और अतिथियों तथा छात्रों के जलपान के साथ हुआ।

मेधावी छात्र योजना के लिए करें आवेदन : उपायुक्त

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

डीसी विक्रम सिंह।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतू व टपरीवास जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिसके चलते डा. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत वित्त वर्ष 01-12 2022 से 31-01-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है।

जिला कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डा. बी.आर. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए 10 फरवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपए से अधिक न हो। इस योजना के तहत लाभार्थि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सरल हरियाणा डॉट कॉम पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि अनुसूचित जाति के दसवीं पास आवेदक को शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8000 रूपये की धनराशि, 12वीं पास विद्यार्थी को शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8 से 1 0000 रूपये की धनराशि, ग्रेजुएट विद्यार्थी को शहरी क्षेत्र में 65 परसेंट और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 9000 से ?12000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग ए के आवेदकों के लिए 10वीं पास को शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक वाले को8000 रूपये की धनराशि, पिछड़ा वर्ग बी को दसवीं पास को शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8000 रूपये की धनराशि दी जाएगी। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के दसवीं पास को शहर 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ?8000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।

आवेदक को बीआर अंबेडकर योजना के लिए विद्यार्थी द्वारा पास की गई कक्षा की मार्कशीट, हरियाणा का स्थाई निवासी हो का जाति प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी व आधार कार्ड, बैंक खाता, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड तथा माता-पिता और अभिभावक की 400000 रूपये की धनराशि से कम आय का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार कार्यालय कमरा नंबर 408 व 409 चौथी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर 12 में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन को पूर्ण रूप से भरे अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने में मिलेगी मदद

फरीदाबाद। ओमेक्स लिमिटेड के डायरेक्टर फाइनैन्स अतुल बंसल ने कहा कि महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था में चमक बरकरार रही। इसे और मजबूत करने के लिए सरकार ने इस बजट में अन्य प्रमुख विकास क्षेत्रों के साथ इंफ्रा डेवलपमेंट और युवा शक्ति को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया है। नई कर व्यवस्था से वेतनभोगी वर्ग के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। महत्वाकांक्षी मध्यवर्गीय उपभोक्ता आधार को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा यह एक उत्साहजनक कदम है। यह संभावित होमबॉयर्स को अपने घर के सपने को साकार करने और आने वाले वर्ष में संपत्ति निवेश में मदद करेगा। बजट में बड़ी बात पूंजी निवेश पर जोर और इसके आवंटन में 33 प्रतिशत की वृद्धि है। इंफ्रा अपग्रेडेशन और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अर्बन इंफ्रा फंड की स्थापना की जाएगी। यह विशेष रूप से टियर 2 और 3 शहरों में रियल्टी बाजारों को आगे बढ़ाने की संभावना है।

संक्षिप्त समाचार

सीजेएम किया जिला जेल का औचक निरीक्षण

फरीदाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यशवीर सिंह राठौर के दिशा-निर्देश पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकिर्ती गोयल ने बुधवार को जिला जेल नीमका फरीदाबाद का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने वहां रह रहे विचाराधीन बंदियों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर उनका समाधान किया। साथ वहां पर बन्दियो से अपील करते हुए कहा कि यदि आपका कोई वकील नहीं है तो वह प्राधिकरण फरीदाबाद से मुफ्त कानूनी सहायता ले सकता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान जिला जेल नीमका में स्थित अस्पताल का लंगर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कानूनी समस्या है या कोई अलग में अपनी शिकायत या समस्या बताना चाहता है तो वह भी कर सकता है। परंतु किसी बन्दी की कोई शिकायत मौके पर ना पाई गई। इस अवसर पर जेल विभाग अधिकारियो के साथ पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, राजेंद्र गौतम, रामवीर तंवर उपस्थित रहे।

महिलाओं को गुड़, चना एवं सैनिटरी नैपकिन किए वितरित

बल्लबगढ़। भारत विकास परिषद की संस्कार शाखा द्वारा 'एनीमिया मुक्त भारत' अभियान के अंतर्गत पिछले 2 साल से हर महीने 75 महिलाओं और बेटियों को सैनिटरी नैपकिन और गुड़ चना वितरित किया जाता रहा है। उसी क्रम में आज भी सैनिटरी नैपकिन एवं गुड़ और चना वितरण का कार्यक्रम अग्रवाल समिति बल्लभगढ़ की लेडीज़ विंग द्वारा किया गया। परिषद की महिला संयोजिका सुनीता रानी ने उपस्थित अतिथियों एवं महिलाओं का स्वागत किया। ऑटो पिन बस्ती स्थित, शाखा द्वारा संचालित संत कबीर स्कूल में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया। समिति की लेडीज़ विंग से राजबाला द्वारा गाए गए माता रानी के भजन का सबने आनंद लिया। उन्होंने सभी को रोजाना योग करने के लिए भी प्रेरित किया। हेमा जैन द्वारा बेटियों और महिलाओं को आत्मरक्षा कैसे करें और खुद को मजबूत कैसे बनाएं, इस विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई।

रूमेटाइड अर्थराइटिस हड्डियों से जुडी बीमारी: डॉ. अनुराग

डॉ. अनुराग अग्रवाल।

फरीदाबाद। रूमेटाइड अर्थराइटिस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 2 फरवरी को रूमेटाइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस हड्डियों से जुडी एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में दर्द, सूजन का कारण बनती है और कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती है। यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी स्वस्थ कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाती है। यह बीमारी आमतौर पर युवावस्था में शुरू होती है और 30 साल से कम उम्र की महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। यह बीमारी अनुवांशिक होती है। यह बात मैरिंगो क्यूआरजी हॉस्पिटल केआर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट के डायरेक्टर एवं एचओडी डॉ. अनुराग अग्रवाल ने बताई। उन्होंने कहा कि यह बीमारी खासकर हाथ, पैरों के जॉइंट्स को प्रभावित करती है। शुरुआत में इस रोग में दर्द शुरू होता है, फिर बाद में यह कई अन्य जॉइंट्स को प्रभावित करने लगता है। इलाज न कराने पर हड्डी, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। धीरे-धीरे जॉइंट्स में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। बॉडी का खराब पोस्चर इस समस्या को ज्यादा बढ़ा सकता है। मरीज को चलने-फिरने में काफी तकलीफ होती है। सर्दी के मौसम में यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। एक महीने में ओपीडी में लगभग 8-10 मरीज रूमेटाइड अर्थराइटिस के आते हैं जिनमें ज्यादातर 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं होती है। ऐसे मरीज ज्यादा होते हैं जिनके माता-पिता इस बीमारी से ग्रस्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासकर हाथ या मल्टीप्ल जॉइंट्स में लगातार दर्द और सूजन को नज़रंदाज न करें। अगर कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है और अचानक से जॉइंट्स में दर्द है तो इसे गंभीर से लेना चाहिए।

अमृत काल का एक समावेशी बजट

फरीदाबाद। बजट 2023 पर मानव रचना शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत भल्ला की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट 2023 उद्योग-अकादमिक सहयोग पर ध्यान देने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर निर्भरता के साथ अमृत काल का एक समावेशी बजट है। बजट में सप्तर्षि के रूप में युवा शक्ति और शिक्षा के लिए बढ़ा हुआ परिव्यय 1.12 लाख करोड़ निस्संदेह लक्ष्य का समर्थन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिजिटलीकरण और उन्नत तकनीक और उद्योग 4.0 के लिए नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल कौशल विकास के लिए माननीय प्रधान मंत्री के सपने को बढ़ावा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कुशल बनाने से भारतीयों को जिम्मेदार और प्रासंगिक वैश्विक नागरिक बनने में मदद मिलेगी। संक्षेप में, बजट 2023 अमृत काल में युवाओं के लिए एक भविष्योन्मुखी बजट है। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए एक संबल के रूप में अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है।

सूरजकुंड मेले में स्मार्ट पार्किंग की शुरुआत

बुकमाईशो ने पार्क+ ऐप के साथ सूरजकुंड मेला मैदान में शुरू की स्मार्ट पार्किंग की सुविधा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

मेले में लगा स्मार्ट पार्किंग सिस्टम।

36वें सूरजकुंड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के दौरान विज़िटर्स को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई तकनीकी सुविधा लाते हुए, हरियाणा पर्यटन और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट पार्किंग सुविधा शुरू की गई है।

हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक डॉ. नीरज कुमार ने कहा, परेशानी मुक्त अनुभव के लिए स्मार्ट पार्किंग की शुरुआत के साथ सूरजकुंड मेला में पार्किंग सुविधा में क्रांतिकारी बदलाव किया जा रहा है। बुकमाईशो ने पार्क+ ऐप के साथ मिलकर सूरजकुंड मेला मैदान में स्मार्ट पार्किंग समाधान उपलब्ध कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आसान भुगतान के लिए फ़ास्टैग सक्षम होगी और विजिटर अब मेला के पास, सरकार द्वारा अनुमोदित पार्किंग क्षेत्रों में पार्किंग स्थल की खोज, बुकिंग और पूर्व भुगतान के लिए पार्क+ ऐप का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा, %यह देश में पहली बार है कि ऐसे आयोजन के लिए इस तरह की उन्नत पार्किंग और ऑनलाइन टिकट बुकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा पर्यटन और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण का यह निरंतर प्रयास है कि हर साल नई तकनीकी सुविधाएं पेश की जाएं और विज़िटर्स को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सूरजकुंड मेला पार्टनर नेशन के रूप में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और थीम स्टेट के रूप में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भागीदारी होगी। ऐप-आधारित पार्किंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए, विज़िटर्स को पार्क+ ऐप (आईओएस और एंड्रॉइड पर उपलब्ध) डाउनलोड करना होगा, वाहन पार्क करने के लिए स्थान दर्ज करना होगा, पार्किंग स्थल का चयन करना होगा और इसके माध्यम से भुगतान करके निर्धारित समय अवधि के लिए इसे बुक करना होगा।

फोटोजर्नलिस्ट के 10 हजार रुपये लेकर फरार हुआ बदमाश

सीसीटीवी कैमरे में कैद स्कूटी सवार बदमाश की फोटो।

फरीदाबाद। शहर के वरिष्ठ फोटोजर्नलिस्ट से एक स्कूटी सवार बदमाश धोखे से 10 हजार रुपये लूटकर फरार हो गया। पीड़ित फोटोग्राफर ने पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है।

भूदत्त कालोनी, बल्लभगढ़ के रहने वाले संजय कुमार एक अखबार में फोटोजर्नलिस्ट के पद पर तैनात है। उन्होंने बताया कि बुधवार को करीब 12 बजे वे एक असाइनमेंट पर सेक्टर तीन गए हुए थे। जब वे सेक्टर तीन में टैगोर स्कूल के पास थे, तभी एक स्कूटी पर सवार युवक उनके पास आया। उसने कहा कि उसे सामने खड़े लोगों से गाड़ी की किस्त लेनी है। उसके पास दो हजार रुपये के नोट हैं। उसने संजय कुमार से 10 हजार के छुट्टे रुपये मांगे। संजय ने बातों में आकर जेब में रखे 10 हजार रुपये उस व्यक्ति को दे दिए। उस व्यक्ति ने कहा कि सामने वाले घर से किस्त के रुपये लेने है, आपको रुपये अभी दे देता हूं। इसके बाद वह स्कूटी लेकर धीरे-धीरे चलने लगा। संजय भी उसके साथ पैदल ही चलने लगे। थोड़ी दूर चलकर उसने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी और रुपये लेकर फरार हो गया। संजय ने शोर मचाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आस-पास के लोगों ने बताया कि यह बदमाश इस क्षेत्र में कई लोगों के साथ इस तरह ठगी कर चुका है। सेक्टर तीन चौकी प्रभारी सीमा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। रुपये लेकर भाग रहा बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है।

अनुसंधान क्रियाविधि पर कार्यशाला का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

कार्यशाला में बच्चों को संबोधित करती डॉ. सुमन गर्ग।

अग्रवाल महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।अग्रवाल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. कृष्ण कांत गुप्ता की अगुवाई में हुई कार्यशाला का विषय-अनुसंधान क्रियाविधि रहा।

मुख्य वक्ता डॉ. सुमन गर्ग, सहायक प्रोफेसर (डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद) ने कहा कि शोध पत्र लेखन के क्रम में तथ्य एवं विचारों के अन्तर को ध्यान में रखना होता है। तथ्य को हम सत्य की तरह स्वीकार कर लेते हैं, इन्हें सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शोध प्रपत्र में अनेक विचारधाराओं तथा निरीक्षणों को प्रस्तुत किया जाता है, इसमें किसी प्रकार की आशंका होने पर पुष्टि की जा सकती है। शोध पत्र लिखने के छह सरल चरण बताते हुए कहा कि सर्वप्रथम शोध लेख विषय पर शोध कीजिये। विषय का विशेषज्ञ बनने के लिए इंटरनेट, शैक्षिक डेटाबेस और पुस्तकालय का उपयोग करके तथ्यों को जुटाइये और शॉर्ट नोट्स लीजिये। विद्यार्थियों ने अनेक प्रश्न पूछे मुख्य वक्ता ने उनका जवाब दिया। पूजा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुई। कार्यशाला में वाणिज्य विभाग केशिक्षकडॉ. शोभना गोयल, डॉ. डिंपल, प्रीति अग्रवाल, पंकज, नेहा एवं प्रियंका भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में कुल 112 स्नातकोत्तर व स्नातक विद्यार्थियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अध्यापकों ने भाग लिया।

इंटर डिपार्टमेंटल प्रतियोगिता आयोजित: अग्रवाल महाविद्यालय में इंटर डिपार्टमेंटल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से इन खेलों रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, कैरम एंड चैस, बेसबॉल, बॉक्सिंग और बैडमिंटन का आयोजन किया जा चुका है। फरवरी माह में इन खेलों का बैडमिंटन, सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, योगा, क्रिकेट, टेबल टेनिस, टाई कमांडो, वॉलीबॉल, खो-खो और शूटिंग का आयोजन किया जाएगा।

प्राचार्य डॉ. कृष्ण कांत गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य कामना की द्य प्राचार्य जी ने कहा कि केवल मेहनत, लगन, धैर्य ही सफलता का मूल मंत्र है जो जीत का दृढ़ संकल्प मन में रख कर परिश्रम करता है उसे लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस अवसर पर खेल संयोजक डॉ. के.एल. कौशिक रविंदर जैन, डॉ. देवेंदर, डॉ. रेखा सैन, पूजा, शारीरिक शिक्षक डॉ. जगबीर सिंह व मोहित हुड्डा मौजूद रहे।

भारतीय अर्थव्यवस्था
भविष्य की उम्मीद

वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण ने उज्जवल भविष्य के बारे में बहुत उम्मीद जताई है और उसकी ये उम्मीदें यथार्थ पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि आज सारी दुनिया की नजरें भारत की अर्थव्यवस्था पर टिकी हैं। हालांकि, 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी की वृद्धि दर वर्तमान वित्त वर्ष से थोड़ी कम होने की आशंका है, पर भविष्य में अच्छे दिन आने वाले हैं। 400 से अधिक पेजों में फैले आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का यही संदेश है। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में सर्वेक्षण की रिपोर्ट पटल पर रखी। इसमें भविष्य के प्रति आशा के अनेक संकेत हैं। हालांकि, सर्वेक्षण ने 2023-24 के लिए वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है, जबकि यह 2022-23 में 7 प्रतिशत तथा पिछले वित्त वर्ष में 8.7 प्रतिशत थी। लेकिन सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि महामारी से भारत तुलनात्मक रूप से तेजी से उबरा है तथा आने वाले वर्ष में वृद्धि ठोस रूप से घरेलू मांग तथा पूंजी निवेश के कारण होगी। उसका यह कहना ठीक है कि वर्तमान समय में वृद्धि दर को अनेक ढांचागत परिवर्तनों से सहायता मिल रही है जिनका क्रियान्वयन पिछले सालों में, खासतौर से 2014 के बाद किया गया है। सर्वेक्षण में संकेत किया गया है कि 'वित्तीय व्यवस्था पर दबाव' 2014 के पहले दिए गए भारी कर्ज के कारण था जिनकी अभिव्यक्ति गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, कर्ज में कम वृद्धि तथा पूंजी सृजन की कम वृद्धि दर के रूप में सामने आई। अब महामारी के कारण पैदा

सुस्ती से बहाली वाले समय की तरह दबाव के वे साल पीछे छूट गए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन ने पिछले कुछ वर्षों की स्थितियों पर भी नजर डाली है जिनमें 1998-2002 के वर्ष शामिल हैं। लगभग दो दशक पहले सरकार ने परिवर्तनकारी सुधार किए थे, पर अर्थव्यवस्था को लगे अस्थाई झटकों के कारण आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुई। जब ये झटके कमजोर पड़े तो 2003 से ढांचागत सुधारों ने अच्छा लाभ दिखाया।

वैंकटरमन का आशावाद न केवल इतिहास, बल्कि यथार्थ पर भी आधारित है। आमतौर पर उन्होंने सर्वेक्षण में एक गुलाबी तस्वीर पेश की है। वित्त वर्ष 15 के बाद 2022-23 की पहली छमाही में निजी उपभोग सर्वाधिक था तथा केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाए पूंजीगत खर्च के कारण निजी निवेश में तेजी आई है जिससे निगमों की बैलेंसशीटों में मजबूती आई है। इसके साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में कर्ज की वृद्धि अच्छी है, अप्रैल-दिसंबर 2022 में अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय रुपये ने बेहतर प्रदर्शन किया है, शहरी बेरोजगारी दर घटी है, खुदरा मुद्रास्फीति पर लगाम लगी है, अप्रैल-नवंबर 2022 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है तथा बेहतर व स्वस्थ होती बैलेंसशीटों से नए कर्ज का चक्र शुरू हुआ है। पिछले महीनों में बैंक कर्जों में दो अंक का उछाल आया है। लेकिन सर्वाधिक रोजगार का सृजन करने वाले विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति इतनी अच्छी नहीं रही है। सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 'वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में थोड़ा घटा है'। लेकिन आशा प्रकट की गई है कि 'विदेशी मुद्रा का प्रवाह पूर्व-महामारी स्तरों से काफी ऊपर बना हुआ है जिसका कारण सरकार द्वारा बिजनेस सुगमता के लिए उठाए गए ढांचागत सुधार हैं।' भारत की तेज होती आर्थिक प्रगति के बावजूद बदलती हुई विश्व परिस्थितियों के कारण समस्यायें बनी हुई हैं। इनके चलते जनवरी-नवंबर 2022 में 2021 के इसी कालखंड की तुलना में औद्योगिक निवेश में कमी आई है। इसका एक कारण अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों द्वारा पैसे को आकर्षित करने के लिए अपनाई नीतियां भी हैं। वैसे कुल मिला कर आर्थिक सर्वेक्षण ने यथार्थवादी तस्वीर सामने रख कर भविष्य के प्रति पूरी उम्मीद जताई है।

तेजी से प्रगति करती अर्थव्यवस्था

भारत सरकार ने सबकी उम्मीदों पर ध्यान देते हुए बजट में सभी क्षेत्रों के लिए समुचित आबंटन किए हैं। इनसे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।

रवि कुमार गुप्ता
रोहन गुप्ता
(लेखक, पेशे से अध्यापक हैं)

वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने अन्य मंत्रियों के साथ मिल कर बजट तैयार किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए 'प्राप्तियों व खर्च की सूची सरकार को संसद के पटल पर रखनी चाहिए।' भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के रास्ते पर है। हाल में इसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और अब यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बजटीय आबंटनों से अर्थव्यवस्था की गति और तेज होगी। उम्मीद की जाती है कि भारत 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके लिए सभी क्षेत्रों में बजट आबंटन बढ़ना चाहिए। अनेक अर्थशास्त्रियों व विशेषज्ञों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि बजट 2023-24 संतुलित होगा। आर्थिक वृद्धि के लिए हर आयाम पर बुद्धिमानी से जोर देना जरूरी है। इनमें ढांचागत संरचना, शिक्षा, कर, प्रावीडेंट फंड, कर स्लैबों, सब्सिडी, उत्पादन से जुड़ी योजनाओं को प्रोत्साहन, विनिर्माण व सेवा क्षेत्र को बढ़ावा, सेमीकंडक्टर-आधारित औद्योगिक अवस्थापनायें, स्वास्थ्य, बैंकिंग, आवास, रक्षा तथा ग्रामीण आवश्यकतायें व मांगें शामिल हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा रूस-यूक्रेन युद्ध ने वर्ष 2020-2022 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर गहरा प्रभाव डाला है। भारत पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है। विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में सुस्ती के कारण रोजगारों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। हालांकि, सभी क्षेत्रों समुचित बजटीय आबंटनों से इन प्रभावों से निपटने में काफी सहायता मिलेगी।

शिक्षा समग्र विकास का महत्वपूर्ण औजार है। शिक्षा के अवसर सारी जनता को मिलने चाहिए। शिक्षा का कौशल व सीखने के प्रति उन्मुखीकरण बढ़ाने के लिए अच्छी किताबों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं व ढांचागत संरचना की जरूरत है। पिछले साल शिक्षा बजट में 11 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर इसे कुल जीडीपी का 3.1 प्रतिशत कर दिया गया था। अनेक शिक्षाशास्त्री इसे नाकाफी बताते हैं और वे इसे जीडीपी के 6 प्रतिशत तक ले जाने की आवश्यकता बताते रहे हैं। टैक्स भारत में समेकित निधि को मजबूत करने वाली प्राप्तियों में सर्व प्रमुख हैं। कर प्रत्यक्ष कर हो सकते हैं जिनको व्यक्तियों से आयकर, कार्पोरेट कर, संपत्ति कर, आदि के माध्यम से एकत्र किया जाता है। इसके साथ ही जीएसटी, स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी, आदि के माध्यम से करों का परोक्ष संग्रह होता है। वित्त वर्ष 2022 में कर राजस्व व जीडीपी का अनुपात लगभग 17.11 प्रतिशत था। इस वित्त वर्ष में इसके बढ़ने का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था। अक्टूबर, 2022 में जीएसटी संग्रह रिकार्ड 1.52 लाख करोड़ दर्ज हुआ जो एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन अनेक लोग अब भी कर नियमों में कमियों का अनुचित लाभ उठाते हुए कर देने से बचते हैं। अच्छी कर व्यवस्था के पांच प्रमुख आयाम हैं-न्यायोचित होना, सरलता, पारदर्शिता, सटीकता तथा प्रशासनिक सुगमता। पूंजी बाजार में निवेश भी ढांचागत संरचना में निवेश की तरह महत्वपूर्ण है इससे विनिर्माण, रोजगार, पर्यटन व बाजार में तेजी आने की संभावना तेज होती है। पूंजी बाजार का आधार मुख्यत: प्रावीडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, एलआईसी प्रीमियम, एनएससी, बांड व अन्य सरकार द्वारा अधिकृत निवेश हैं जिनसे एक निश्चित समय में लाभ सुनिश्चित होता है। आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत हमें कर कटौती में रियायत मिलती है। वर्तमान समय में यह सीमा 1.5 लाख थी जिसे कम से कम 50,000 रुपये बढ़ाने की विशेषज्ञों ने संस्तुति की थी। 2014 के बाद से इसमें संशोधन नहीं किया गया था। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रास्फीति को देखते हुए इसमें परिवर्तन अच्छा रहेगा।

पिछले वर्षों में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान घटा है। वित्त वर्ष 2012 में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जीवीए में 17.4 प्रतिशत था जो वित्त वर्ष 2021 में घट कर 14.5 प्रतिशत रह गया। सरकार ने इस क्षेत्र में पूंजीगत खर्च बढ़ाया है। इससे रोजगार सृजन तथा निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। विभिन्न एलेक्ट्रानिक उपकरणों, जैसे वाहनों, मोबाइल फोनों व अन्य उपकरणों में चिप्स के प्रयोग से सेमीकंडक्टर चिपों की मांग में कई गुना वृद्धि हुई है। चिपों की पूर्ति मुख्यत: जापान, ताइवान व चीन से आयात द्वारा होती है। सरकार ने इनकी स्वदेशी आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग से चिपों के उत्पादन में सहायता मिल सकती है। विनिवेश का अर्थ निवेशित परिसंपत्तियों की बिक्री है। सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों-पीएसयू व पीएसयू के शेयरों को बेचती है। पिछले तीन साल में सरकार ने अनेक विनिवेशों की घोषणा की थी, लेकिन वह यह लक्ष्य पूरा करने में सफल नहीं हुई। बीपीसीएल, ओआईएल, आदि पीएसयू मुनाफे वाली कंपनियां हैं। अर्थशास्त्रियों के विचार से इनका विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो भी इसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। उच्च विनिवेश से राजस्व प्राप्त होता है, जबकि कम विनिवेश से सरकार को भावी निवेश से मुक्ति मिलती है। अत: विनिवेश में सावधानी बरती जानी चाहिए।

हमारा देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन सरकार द्वारा सब्सिडी पर भारी धनराशि खर्च करना आश्चर्यजनक है। खाद्य व उर्वरक सब्सिडी का जीडीपी में आठवां या 12 प्रतिशत हिस्सा है। उर्वरक सब्सिडी पर 2.3 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है जिसे घटा कर 1.4 लाख किया जा सकता है। इसी प्रकार खाद्य सब्सिडी को भी 2.7 लाख करोड़ से घटा कर 2.3 लाख करोड़ किया जा सकता है। यदि सरकार राजकोषीय घाटा कम करना चाहती है तो उसे सब्सिडी अवश्य घटानी चाहिए। उसे निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे के मामले में संतुलन बरतना चाहिए तथा इसे वर्तमान वित्त वर्ष में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर लाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में भारत में 83,000 से अधिक स्टार्टअप व 100 से अधिक यूनीकार्न हैं। दुनिया भर में कोरोनावायरस वैश्विक महामारी तथा मंदी के प्रभाव के कारण स्टार्टअप को पैसा मिलना कठिन हुआ है। इसलिए भारत सरकार शुरू से ही स्टार्टअप को समर्थन देने की नीति पर चल रही है। अनेक अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि सरकार स्टार्टअप के बिजनेस क्षेत्र में विस्तार कर इनका बिजनेस और सुगम बनाएगी। उल्लेखनीय है कि स्टार्टअप कुशल उद्यमियों व नौजवानों को रोजगार प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही स्टार्टअप का मूल्य 500 बिलियन डालर का आंकड़ा पार कर जाएगा। सरकार को स्टार्टअप का काम आसान बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा विनियमों की घोषणा करनी चाहिए।

'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य रक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत कर प्राप्त किया जा सकता है। स्टाकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार हिंद-प्रशांत देशों में हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मामले में भारत का चौथा स्थान है, पर भारत हथियारों व रक्षा उपकरणों के आयात के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने 14,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात किया है और 2025 तक इसके 25,000 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। राजकोषीय नीति व बजट का उद्देश्य आय व बचत बढ़ाना, निवेश दर में वृद्धि करना, उत्पादक क्षेत्रों में खर्च बढ़ाना, मूल्य स्थिरीकरण तथा असमानता घटाना है। यदि असमानता में कमी नहीं आती है तो इससे जनता में टकराव बढ़ सकते हैं जिसका असर अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक हो सकता है और इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है। जीएसटी लागू करने से कर संग्रह में सुगमता व तेजी आई है। किसी भी देश का बजट संतुलित होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अर्थव्यवस्था के सभी आयामों पर गौर करे तथा बजट सारी जनता की उम्मीदें पूरी करने का प्रयास करे। संभवत: वर्तमान बजट इन कसौटियों पर खरा उतरता है।

अव्यवस्थाओं का शिकार विमानन उद्योग

वीवी सुंदर
(लेखक संप्रेषण विशेषज्ञ हैं)

भारतीय विमानन उद्योग अब एक तमाशा है। हाल ही में एअर इंडिया पर एक अनियंत्रित यात्री की शर्मनाक कथित घटना, यात्रियों से भरी एक बस को छोड़ कर उड़ान भरने वाली एक एयरलाइन, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (डायल) पर व्यवस्थित अराजकता, और अन्य हवाईअड्डों पर बार-बार होने वाली और असूचित घटनाएं एक चिंता पैदा करती हैं। सवाल। उद्योग किस दिशा में जा रहा है? यात्री टर्मिनल शुल्क का भुगतान करने के बदले इन हवाई अड्डों से एक यात्री को वास्तव में क्या मिलता है? एयरलाइंस अपने दायित्वों को कैसे संभालती हैं? यात्रा को सुरक्षित और कम तनावपूर्ण बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? भारत में हवाई अड्डे और एयरलाइंस स्पष्ट रूप से उस स्तर की सेवा प्रदान नहीं करते हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। यात्रा का तनाव शुरू होता है और जारी रहता है क्योंकि हवाईअड्डे जमीनी परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। दुनिया के व्यस्ततम या सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे होने के उदात्त उपाधियों और ख्याति की आवश्यकता किसे है? यात्री अधिक कुशल हवाई अड्डे को पसंद करेंगे! व्यस्ततम हवाई अड्डे से केवल ऑपरेटर को लाभ होता है, ग्राहक को नहीं।

हमारे वैभवशाली हवाईअड्डों पर विचार करें, जो उल्टे भले ही एक क्रांति का सूत्रपात करते प्रतीत होते हैं। कई आधुनिक हवाई अड्डों की भव्य प्रकृति के बावजूद, अक्षमता व्यापक प्रतीत होती है। लोगों को यात्रा करने के तरीके को बदलने के लिए विमानन बनाया गया था, जिससे उन्हें अन्य तरीकों से कम समय में लंबी दूरी की यात्रा करने की अनुमति मिल सके। हवाई अड्डे इस सिद्धांत में सेंध लगाते दिखाई देते हैं। वे अधिकांश यात्रियों का बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। घरेलू यात्रा के लिए भी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ने 2-3 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम तय किया है। यह एक अस्वीकार्य कदम है। क्या यह अजीब नहीं है कि इतने समय में कोई विदेशी तट पर उतर सकता है? ग्राहक को केंद्र में रखे बिना एयरलाइंस और हवाई अड्डे के संचालकों द्वारा

स्थापित किए गए पैमाने केवल स्वयं-सेवा कर रहे हैं। विडंबना और समान रूप से आकर्षक यह है कि कैसे तकनीक उस बिंदु तक उन्नत हो गई है जहां यह पता लगा सकती है कि क्या किसी के दिल के वाल्व की मरम्मत की जरूरत है, जबकि हवाई अड्डे की एक्स-रे मशीनें अभी भी बैग के माध्यम से नहीं देख सकती हैं और हमें इसके बजाय पुरानी प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करती हैं। केबिन सामान के साथ-साथ हमारे जैकेट, बेल्ट, जूते और मोजे से सामान निकालना। इस तरह की नासमझ जांच किसी भी सभ्य प्रक्रिया का अपमान है। यह सार्वजनिक अपमान का एक रूप है जिसे हम सभी आवश्यक रूप से स्वीकार करने लगे हैं। क्या हम यह कह रहे हैं कि तैनात आदमी और मशीन एक-दूसरे के प्रति इतने शंकालु हैं कि वे इस बात की दोबारा जांच करना चाहते हैं कि यात्री किसी मिशन पर अपराधी तो नहीं है? यह पुरुषों और मशीनों दोनों की क्षमताओं पर सवाल उठाता है। एक्स-रे मशीनों के संचालक उन वस्तुओं या इलेक्ट्रॉनिक्स से अपरिचित हैं जिन्हें ठीक से संभाला जाना चाहिए। हम में से कई लोगों ने हाल के वर्षों में हवाईअड्डे के सामान्य वातावरण को बिगड़ते देखा है। टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं और तंग क्वार्टर आपको सिरदर्द देते हैं, लेकिन हवा के संचलन की कमी स्थिति को बढ़ा देती है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में, लाइनों को नेविगेट करते समय कोई भी आसानी से अपनी जैकेट में पसीना बहा सकता है। यात्रियों के लिए इससे क्या फायदे हैं?

व्यावहारिक समाधान, जैसे चेक-इन और सुरक्षा क्षेत्रों के अंदर यात्रियों या भीड़ के आकार को साफ करने में लगने वाले अनुमानित समय को प्रदर्शित करना फायदेमंद हो सकता है। यात्रियों के तनाव के स्तर को कम किया जा सकता है यदि वे वास्तविक समय में एयरलाइन या गंतव्य प्रस्थान के क्रम में साफ हो जाते हैं। बोर्डिंग के अंत तक यात्री पूरी तरह से अपने दम पर है। इसके बजाय, यह एयरलाइन और हवाईअड्डा संचालकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे हवाईअड्डे के अंदर आने के बाद ग्राहक को अपना लें और टिकट की कीमत और उसके द्वारा भुगतान किए गए करों के बदले में अपनी यात्रा को सुरक्षित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त बनाएं। किसी भी सेवा प्रदाता से न्यूनतम यही अपेक्षा की जाती है।

एक यात्री को कष्ट क्यों दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक विशिष्ट एयरलाइन उड़ा रहा है और अन्य एयरलाइनों के साथ सार्डिन की तरह बंच है जिसकी उस समय अधिकतम क्षमता है? अनिवार्य रूप से, प्रत्येक एयरलाइन यात्री को एक ही खरगोश छेद से क्यों गुजरना चाहिए? ये पैसे बचाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ एक अलग युग के लिए डिज़ाइन की गई प्रणालियां हैं। यह उन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का समय है जो घर्षण और तनाव पैदा करते हैं और उन्हें समाप्त करते हैं। हम खामोश हवाई अड्डे नहीं चाहते; हम उत्साहित हवाईअड्डे चाहते हैं। हवाईअड्डे जो ग्राहकों की जरूरतों के प्रति सचेत हैं और जो व्यावहारिक हैं। हम ऐसे हवाईअड्डे चाहते हैं जो यात्री के टर्मिनल में प्रवेश करने से लेकर प्रस्थान करने तक गति, दक्षता और देखभाल प्रदान करें।

काश, एयरपोर्ट संचालक और एयरलाइंस इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे होते। लापरवाही और हवाई रोष हवाईअड्डे, एयरलाइंस और हितधारकों के टूटे, लापरवाह और हाथों से दूर रहने वाले रवैये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम है।

आप की बात

खेलो इंडिया

प्रदेश में खेलो इंडिया का शुभारंभ हो गया है । भारत सरकार की पहल पर सन 2017 में खेलो इंडिया खेल का श्री गणेश हुआ था। अब इन खेलों में जमीन से जुड़े हुए खेलों की संख्या 30 से अधिक हो गई है। जिसमें स्कूली व यूनिवर्सिटी के बच्चे खेलों में भाग लेकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार के खेलों से ऐसी कई प्रतिभाएं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना प्रदर्शन करेगी जो निश्चित ही एशियाड ओलंपिक व अन्य स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन करेगी व इनसे एशियाड और ओलंपिक जैसे खेलों में पदकों की संख्या बढ़ेगी । 2017 से पहले जो खेल हाशिए पर जा रहे थेए अब खेलो इंडिया स्पर्धा के बाद वे पुनर्जीवित हो चुके हैं। यह भारत सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है कि आज खेलो इंडिया खेलों की धूम प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो भविष्य में देश के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की नई-नई पौध को प्रोत्साहित करेगा । खेलों को प्रोत्साहन देने से युवाओं व किशोरों में नशाखोरी व नेट के अत्यधिक उपयोग जैसी बुराइयों से मुक्ति पाने में सहायता मिलेगी तथा समाज व देश की समस्यायें हल करने की टीम भावना जाग्रत होगी।

हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

फिलिस्तीन समस्या

अमेरिकी विदेश मंत्री ऐंटनी ब्लिंकन जब तेलअवीव पहुंचे तो लगा शायद वे फिलिस्तीन व इस्राइल के बीच तनाव घटाने आए होंगे। वे येरुसलेम,पश्चिमी तट और रामल्ला गए। बेंजामिन नेतन्याहू से शांति बरतने की अपील की। महमूद अब्बास से इस्राइली बस्ती बसाये जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने वही पुराना राग दोहराया कि समस्या का समाधान दो राज्यों की नीति में है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे समस्या का एकमात्र समाधान बताया था। मगर इसराइल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। क्योंकि इसका अर्थ हथियाई भूमि खाली करना होगा। लेकिन यह संभव नहीं लगता है। 13 सितंबर 1993 को इजरायल के प्रधान मंत्री यित्जाक राबिन और पीएलओ के वार्ताकार महमूद अब्बास ने व्हाइट हाउस में आमतौर पर ओस्लो समझौते के रूप में संदर्भित अंतरिम स्वशासन व्यवस्था पर सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। नेतन्याहू ने 1996 में सत्ता संभालते ही इस समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इस्राइल में पुन: प्रधानमंत्री बनने के बाद नेतन्याहू शायद और कट्टर हो गए हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी समस्या का समाधान अब और जटिल हो गया है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

लाभदायक कड़कनाथ

अभी हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी महेन्द्र सिंह धोनी कड़कनाथ प्रजाति की और आकर्षित हुए। मुर्गे की कड़कनाथ प्रजाति को जीआई टेग मिल चूका है। इस प्रजाति के रोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कड़कनाथ में भरपूर प्रोटीन के साथ ही फैट व कोलेस्ट्रॉल कम होता है। एक जानकारी के मुताबिक यह मुर्गा अन्य प्रजातियों के मुर्गों से बेहतर और महंगा होता है तथा इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए इसका सेवन ठंड में लाभकारी होता है। इसमें कोलेस्ट्रोल की मात्रा बहुत कम होती है तथा यह विटामिनों से भरपूर रक्त, हड्डियों व गहरे काले रंग का होता है। वैसे इसकी संकर प्रजातियों के रंग अलग हो सकते हैं। मध्यप्रदेश के झाबुआ और आलीराजपुर आदि जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ की जलवायु इसके लिए हितकारी है। कड़कनाथ मुर्गा पालन केंद्र अन्य जिलों के क्षेत्रो में स्थापित कर एवं ऐप के जरिए कड़कनाथ क्षेत्र को रोजगार हेतु बढ़ाने हेतु प्रयत्न करना होगा। कड़कनाथ के प्रोत्साहन से इस क्षेत्र के आदिवासियों को बेहतर रोजगार मिलेगा व उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

संजय वर्मा, धार

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

फरमाया

कांग्रेस कहीं नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केवल अपने उद्देश्य के बारे में भ्रम पैदा करती है।
- **राकेश सिन्हा**
भाजपा नेता

मैंने यह यात्रा अपने या कांग्रेस के लिए नहीं की है। यह देश की जनता के लिए है।
- **राहुल गांधी**
कांग्रेस नेता

मैं आपको विशाखापट्टनम में आमंत्रित करता हूं जो आने वाले दिनों में हमारी राजधानी होगी।
- **वाई.एस. जगन रेड्डी**
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

देश के सर्वांगीण विकास को शक्तिशाली करने वाला है बजट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आज संसद में प्रस्तुत आम बजट 2023.24 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल का यह पहला बजट देश के सर्वांगीण विकास को शक्तिशाली करने वाला बजट है। इस बजट में ध्यान रखा गया है कि गरीब, मध्यम वर्ग, किसान आगे बढ़ने का हौंसला रखने वाला समाज अपने सपनो को पूरा कर सकें। देश का मेहनतकश जो भारत के निर्माण की नीव है, ये बजट उनके हौंसलों को साकार करने वाला है। उन्होंने कहा बजट में महिलाओंए श्रमिकों, नौकरीपेशा लोगो, शिक्षा सुविधाओं में बढ़ोतरी जैसे कई आवश्यक क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है जो विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। यह एक दूरगामी और सबको समाहित करने वाला बजट है। बजट का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।

गरीब कल्याण को समर्पितः पाठक

लखनऊ। केंद्र की भाजपा सरकार ने शानदार बजट प्रस्तुत किया है। अमृतकाल का यह पहला बजट गरीब कल्याण को समर्पित है। विकसित भारत के संकल्प को यह बजट पूरा करेगा। बजट में हर वर्ग को लाभ प्रदान किया गया है। नौकरी पेशे से लेकर बिजनेस क्लास को फायदा मिलेगा। किसानों को भी आशातीत फायदा मिलेगा। छूट भी प्रदान की गई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार बेहतर काम कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्ग व समूहों का खयाल रखते हुए आम आदमी का बजट प्रस्तुत किया है। अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन भागीदारी सबका साथ सबका विकास पर जोर किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओंए बुजुर्ग छात्रों और किसानों को विशेष छूट प्रदान की गई है। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में तब्दीली की गई है। सात लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन की लंबे समय से देश व प्रदेश की जनता राह देख रही थी। इससे आम आदमी को सीधे फायदा होगा।

आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने वालाः खन्ना

लखनऊ। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को सर्वहितकारी एवं सर्वसमावेशी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रस्तुत इस बजट ने हिंदुस्तान की जनता का दिल जीता है। बजट में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीब, नौकरीपेशा, व्यापारी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग एवं वेतन भोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। इससे लोगों की क्रयशक्ति बढ़ेगी और मांग सृजित होगी जिससे उद्योगों को गति मिलेगी और रोजगार सृजन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। श्री खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में राज्यांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 146498.76 करोड रुपए मिलने का अनुमान था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित आंकड़ों के अनुसार अनुमानतः 169745.30 करोड़ रुपए मिलेगा जो मूल अनुमान से 23246.54 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में 183237.59 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार से मिलने का अनुमान है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुमान से 37000 करोड़ रुपए अधिक है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राज्यों को पूंजीगत कार्य में सहायता के लिए 50 वर्षीय ब्याज रहित ऋण दिए जाने की घोषणा की गई थी तथा इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए का प्राविधान केंद्रीय बजट में किया गया था। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 14351 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे जिसके सापेक्ष अब तक 7654.57 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं।

विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सशक्तीकरण को समर्पित एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला भारत को विश्व में नंबर एक अर्थ व्यवस्था बनाने को अग्रसर करने वाला बजट है। मौर्य ने कहा है कि डिजिटल इंडिया वाला मेक इन इंडिया को आकर्षित करने वाले बजट में ग़रीबों के साथ मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है । प्रधानमंत्री आवास योजना और रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी व जलमार्ग के साथ पर्यटन उद्योग व कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66फीसदी बढ़ोतरी की गयी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सामाजिक न्याय, समानता और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। गरीबों को मजबूत व शक्तिशाली बनाने वाला बजट है।कहा कि बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। बजट में वैकल्पिक उर्वरकों को प्रोत्साहन देने के लिए पी एम प्रणाम योजना की शुरुआत की गयी है। बजट की बात प्राथमिकताएं हैं जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल के दौरान हम सबका मार्गदर्शन करेगी।

कुछ नया नहीं, पार्टी से ज्यादा देश के लिए होता तो बेहतरः मायावती

लखनऊ। देश के आम बजट को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा कि इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फि र से झड़ी लगा देती है जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दाव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? बसपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केन्द्र सरकार के बजट आते-जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही किन्तु वे सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोवर मिडिल क्लास बन गया। जो अति अति-दुखद है। मायावती ने कहा कि सरकार की संकीर्ण नीतियों व गलत सोच का सर्वाधिक दुष्प्रभाव उन करोड़ों गरीबों किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के जीवन पर पड़ता है जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं और असली भारत कहलाते हैं। सरकार उनके आत्म-सम्मान व आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे ताकि आमजन की जेब भरे व देश विकसित हो। मायावती ने कहा कि केन्द्र जब भी योजना लाभार्थियों के आँकड़ों की बात करे तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि भारत लगभग 130 करोड़ गरीबों, मजदूरों, वंचितों, किसानों आदि का विशाल देश है जो अपने अमृतकाल को तरस रहे हैं। उनके लिए बातें ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए होता तो बेहतर।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सस्टेनेबल ग्रोथ का मार्ग प्रशस्त करेगाः नन्दी

लखनऊ। प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि आम बजट 2023 सर्वस्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट है। यह बजट देश के 130 करोड़ लोगों का बजट है। उनकी सहूलियत, रोजमर्रा की जरूरतों और सुरक्षित भविष्य का मजबूत खाका इस बजट में मौजूद है। खासकर कि मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर्स का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट देश के औद्योगिक विकास, सुरक्षित निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सस्टेनेबल ग्रोथ का मार्ग प्रशस्त करेगा, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, किसानों की चिंता, महिलाओं के सशक्तिकरण की स्पष्ट झलक इस बजट में समाहित है।

किसानों, महिलाओं, देश की गरीब जनता के लिए कल्याणकारीः जयवीर सिंह

लखनऊ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बजट को किसानों, महिलाओं, देश की गरीब जनता के लिए कल्याणकारी बताते हुए कहा है कि यह बजट उभरते भारत की नई तस्वीर है। बजट में महिलाओं, श्रमिकों, नौकरीपेशा के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही रेल बजट में वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में 9 गुना बढ़ोत्तरी की गयी है। इससे असेवित क्षेत्रों तक रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इस बजट में सभी सेक्टरों को काफी तरजीह दी गई है। जयवीर सिंह ने कहा है कि इस बजट के प्राविधानों से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही कृषि एवं औद्योगिक सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है।

देश की अर्थव्यवस्था और गतिशील व विकासोन्मुखी होगीः धर्मपाल सिंह

लखनऊ। पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बजट को सर्वस्पर्शी एवं जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था और अधिक गतिशील व विकासोन्मुखी होगी। बजट में किसानों, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक तथा अवस्थापना विकास पर विशेष बल दिया गया है। जिससे रोजगारसृजन के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न साकार होगा। पशुधन मंत्री ने डेयरी सेक्टर पर विशेष ध्यान दिये जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक बधाई दी।

ओडीओपी योजना को पूरे देश में होगा विस्तार देने के लिएः राकेश सचान

लखनऊ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि महिला, गांव, गरीब और किसानों को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में खासतौर से श्रमिकों एवं मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बजट में किये गये प्राविधान से प्रदेश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। सचान ने एक जिला.एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को पूरे देश में विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इस योजना को पूरे देश में लागू करने से व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन होगा और देश व प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद थी जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बजट बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी एवं आर्थिक मंदी के दौर में आम जनमानस के लिए निराशाजनक है। इस बजट से देश के लोगों को बहुत उम्मीद थी, रोजगार के ठोस अवसर परिलक्षित नहीं हो रहे, सरकारी सेवकों को इस बजट में पुरानी पेंशन बहाली की केंद्र सरकार से उम्मीद थी जिस पर सरकार का किसी भी प्रकार का कोई ध्यान ना देना अत्यंत निराशाजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स में किए गए संशोधन, कुछ हद तक संतोषजनक है किंतु सरकार इसमें और बेहतर कर सकती थी। अंततः यही कहा जा सकता है कि चाहे सरकारी कर्मचारियों का मामला हो अथवा आम जनमानस का किसी भी दृष्टिकोण से उत्साह जनक नहीं कहा जा सकता है।

केन्द्रीय बजट में सशक्त-समृद्ध नए भारत के निर्माण का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है

लखनऊ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने आजादी के अमृतकाल के आम बजट 2023-24 को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के हितों को पूरा करने वाला बजट बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आजादी के अमृतकाल में प्रस्तुत नवभारत के संकल्प को समर्पित, लोकहित एवं जनकल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2023-24 में सशक्त-समृद्ध नए भारत के निर्माण का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। केन्द्रीय बजट की सात प्राथमिकताएं है जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल में भी नए भारत की समृद्धि एवं देश को आर्थिक मोर्चे पर महाशक्ति बनाने में हमारा मागदर्शन करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बजट को सशक्त व समृद्ध भारत की तस्वीर बताते हुए कहा कि इसमें 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और हितों को ध्यान में रखा गया है। मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट 2023 में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

आम जनता के लिए श्रेष्ठ बजटः अनिल राजभर

लखनऊ। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह आम जनता के लिए श्रेष्ठ बजट है। इसमें सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है और आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं, किसानों, युवाओं सभी की चिंता की गई है। श्रम मंत्री ने सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर देश के स्थाई विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नागरिकों की सुविधाओं को और बेहतर किए जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बहुत.बहुत आभार व्यक्त किया है।

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाएगा

अपना दल एस के प्रस्ताव को बजट में किया गया शामिल

लखनऊ। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि वर्ष 2023-24 का आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुफ्त राशन योजना को अगले एक वर्ष तक बढ़ाने की सराहनीय पहल की गई है। अब यह योजना जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। अपना दल एस गरीबों, वंचितों व पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की मांग करता रहा है। पार्टी का यह भी कहती रही है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वंचित व पिछड़ा समाज के लोग वर्षों तक जेल में पड़े रहते हैं, उनकी जमानत नहीं हो पाती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना दल एस के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए गरीबों की जमानत का पैसा खुद सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों को एक साल तक लोन में छूट देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की है, इसके तहत पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि यह बजट ऐतिहासिक, संपूर्ण समावेशी, हर एक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव का बजट है। देश में एयर सर्विस को बढ़ावा देने के लिए 50 नए एयरपोर्ट और हेलिपैड भी बनाए जाएंगे।

यह चुनावी बजट, इसमें कोई जनकल्याण की योजना नहीं

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह चुनावी बजट है, इसमें कोई जनकल्याण की योजना नहीं। ये सिर्फइम्पोर्ट को बढ़ावा देकर पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का बजट है। अखिलेश ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगाघ् जब उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कहां से देंगे, स्मार्ट सिटी का कोई जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेस वे के लिए कोई बजट नहीं दिया। नए पॉवर प्लांट लगाने की कोई घोषणा नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि ओडीओपी की बात सरकार ने फिर इस बजट में की लेकिन पहले ही ये योजना कितना जमीन पर उतरी इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। किसानों के लिए कोई नई मंडी बनाने, एमएसपी आदि के लिए घोषणा नहीं की गयी। पूरे बजट में वित्त मंत्री ने जीएसटी पर कोई चर्चा नहीं कीए जिससे व्यापारी वर्ग सबसे अधिक परेशान है। मेडिकल क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था ही बर्बाद है। यूपी में गोरखपुर जैसे जिलों में बने एम्स बंद पड़े हैं। अखिलेश ने कहा कि सरकार नई एम्बुलेंस की बात कर रही लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर, इलाज ही नहीं तो एम्बुलेंस का क्या करेंगे। ऊपर से इन लोगों ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा को भी बर्बाद किया। अखिलेश ने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय इतनी ही बेहतर हुई तो किसानों की आत्महत्या क्यूं बढ़ रही है।

आम जनता की सारी उम्मीदें हुईं धूल धुसरितः खाबरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि यह बजट पूरी तरह मध्यम वर्ग, श्रमिक, किसान, युवा, महिला तथा छात्र विरोधी है। भाजपा के पूर्व के जुमलों पर एक बार फिर बजट के माध्यम से पर्दा डालने का मात्र प्रयास है। बजट पूरी तरह आम जनता के हितों पर कुठाराघात और छलावा है।

उन्होंने कहा कि यह चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की है। रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। आधे से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। टैक्स स्लैब में बदलाव अच्छा है लेकिन सरकार बताए कि गरीब, किसान, बेरोजगारों को क्या दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हर गरीब को आवास, किसानों की आमदनी दुगनी, बुलेट ट्रेन, युवाओं को सालाना दो करोड़ रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे बड़े-बड़े वादों पर वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट एक तरफ जहां कुछ बड़े पूंजीपतियों केंद्रित है वहीं दूसरी तरफ बजट पूरी तरह निराशावादी और देश के विकास को रसातल में ले जाने वाला है। इस बजट से आम जनता की जो उम्मीदे थीं वह धूल धूसरित हो गई हैं। महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों की समस्याएं जस की तस हैं बजट में कुछ भी उनके लिए नहीं रखा गया है। कुल मिलाकर यह बजट युवा, महिलाएं, बेरोजगार, किसानां एवं मध्यम व निर्धन वर्ग को महज एक दिवास्वप्न दिखाने जैसा है। बजट पूरी तरह खोखला और आम जनता के साथ धोखा है। प्रधानमंत्री एक तरफ पैर में हवाई चप्पल पहनने वाले गरीब को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाने की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 24 प्रतिशत रोडवेज का किराया बढ़ाकर गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है।

एमएसएमई के भगुतान के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकताः आईआईए

लखनऊ। केंद्रीय बजट को लेकर आईआईए के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में बजट परिचर्चा के दौरान एमएसएमई के लिए उठाए गए कदम की सराहना की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष आईआई अशोक अग्रवाल ने कहा कि आईआईए द्वारा अपने बजट प्रस्ताव में जो मांगे वित्त मंत्री से रखी थी उनका आंशिक समाधान इस बजट में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि आईआईए इन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए कुछ और बड़े कदमों की अपेक्षा रखता है। जिसमें खासतौर पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जो लंबित भुगतान बहुत समय तक पड़े रहते है उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आईआईए ने बजट पूर्व प्रस्ताव में वित्त मंत्री को एमएसएमई सेक्टर को ऋ ण की अनुपलब्धता तथा ऊँची ब्याज दरो की समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया था। अतः एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9000 करोड़ रूपए का प्रावधान करने का आईआईए स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि कोलैटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट की कास्ट में 1 प्रतिशत की कमी भी स्वागत योग्य है। टैक्सेशन स्कीम की सीमा को 2 करोड़ रूपए से 3 करोड़ तक बढ़ाने से लाखों सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को रहत मिलेगी। नीरज सिंघल वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईआईए ने कहा कि बजट में जिन 7 प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया है उससे एमएसएमई के लिए अनेक व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे। कुछ नए व्यावसायिक अवसर ग्रीन ग्रोथ, टूरिज्म, एजुकेशन एवं स्किलिंग, लैब ग्रेड डायमंड्स इत्यादि में सर्जित होंगे। दिनेश गोयल महासचिव आईआईए ने बताया कि व्यक्तिगत इनकम टैक्स में 7 लाख रूपए तक की रिबेट देने और नयी टैक्स प्रणाली में 15 लाख रूपए तक की आय पर 20 प्रतिशत इनकम टैक्स लागु करने से मध्यम वर्ग को अवश्य राहत मिलेगी जिससे एमएएमई के एवं अन्य उत्पादों की खपत बढ़ेगी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आईआईए आलोक अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक्स एवं आईटी में बजट प्रावधान में जो लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है उससे ऑनलाइन प्रक्रिया को बल मिलेगा, फलस्वरूप पारदर्शिता बढ़ेगी।

यूपी के एमएसएमई व ओडीओपी सेक्टर को मिली बूस्टर डोज

उप्र की 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को मिलेगी राहत

अभिषेक रंजन। लखनऊ

केंद्र सरकार ने अपने बजट में एमएसएमई और ओडीओपी सेक्टर को लेकर जो घोषणाएं की है, उसका सबसे अधिक लाभ यूपी को मिलेगा। इन सेक्टर से जहां एक तरफ सर्वाधिक रोजगार पनप रहे हैं तो वहीं समाज के हर वर्ग को काम भी मिल रहा है। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडीओपी उत्पादों की बिक्री के लिए सभी राज्यों में यूनिटी मॉल खोलने की घोषणा कर प्रदेश के लाखों ओडीओपी कारीगरों, शिल्पियों और निर्यातकों को खुश कर दिया। यूनिटी मॉल राज्यों की राजधानियों के साथ ही अन्य बड़े शहरों में खुलेंगे। माना जा रहा है कि यूनिटी मालों के बन जाने पर देश के अंदर हर राज्य में ओडीओपी उत्पादों के लिए बड़ा बाजार तैयार होगा। ओडीओपी में मिट्टी के बर्तन से लेकर कांच के समान का निर्माण हो या फिर सहारनपुर में बनने वाले लकड़ी के खिलौने की बात हो इन छोटी स्टार्टअप इकाईयों के गांव देहात और शहरी नगरीय क्षेत्र के छोटे परिवार अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। बजट में मोदी ने ओडीओपी को और प्रमोशन देते हुए हर राज्य में यूनिटी माल खोले जाने की घोषणा की है। इसके लिए ओडीओपी उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिलेगा तो वहीं इस उद्योग के जरिए काम करने वाले हाथ भी वर्तमान में प्रदेश के कुल निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन उत्पादों की ही है। इससे इतर अगर बात करें एमएसएमई सेक्टर की तो कोविड के दौरान पूरे देश में एमएसएमई सेक्टर में काफी गिरावट आई थी लेकिन अब केंद्र सरकार की इस डोज से एमएसएमई सेक्टर को काफी राहत मिलेगी। यूपी में 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाईयां हैं जिनसे करीब करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तीन साल बाद अब प्रदेश में कोविड के बाद एमएसएमई सेक्टर पनपने लगा है। कोविड के समय एमएसएमई इकाईयों परफार्मेंस बैंक गारंटी पर जो संकट आया था वह अब दूर हो जाएगा। सरकार ऐसी एमएसएमई इकाईयों परफार्मेंस बैंक गारंटी वापस कर देगी जो कि बड़ी राहत इस सेक्टर के लिए साबित होगी। दरअसल कोविड के दौरान जो एमएसएमई इकाईयां सरकार को विभिन्न उत्पाद उलब्ध करा रही थी लेकिन लाकडाउन की वजह से उत्पादन बंद होने के कारण टेंडर की निर्धारित शर्तो के अनुरूप एमएसएमई इकाईयों की परफार्मेंस बैंक गारंटी सरकार ने रख ली थी। इस दौरान सबसे अधिक नुकसान निर्माण करने वाली इकाईयों को हुआ था। मगर अब सरकार की इस घोषणा के बाद कंपनियों की फसी हुई बैंक गारंटी के वापस मिलने का रास्ता साफ हुआ है। वापस मिलने वाली बैंक गारंटी को कंपनियां कही और लगा पाएंगी।

एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर

निदेशक एवं चैयरमैन लखनऊ इंडो अमेरिकन चेम्बर मुकेश सिंह ने कहा कि 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जिनका सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत हिस्सा है और लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। बजट ने लचीलेपन की इस भावना का प्रदर्शन किया है। एमएसएमई क्षेत्र के कई उद्योगों में बिक्री पूर्व महामारी के स्तर के 90 प्रतिशत तक पहुंचने के साथ भारत के छोटे व्यवसाय एक बदलाव की पटकथा लिख रहे हैं। एमएसएमई को संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9000 करोड़ रुपये का कोष मिला है यह संशोधित योजना 22 अप्रैल से 9000 करोड़ रुपये के कोष में डालने के माध्यम से प्रभावी होगी। इस बाउंसबैक का बहुत सारा श्रेय सरकार को उसके सक्रिय हस्तक्षेपों के लिए जाता है जैसे कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार करना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की मरम्मत करना और स्वयं को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को शुरू करना है। उन्होंने कहा कि हमारे एमएसएमई की बड़े पैमाने पर असंगठित प्रकृति, बढ़ती ब्याज दरें और बिगड़ते बाहरी वातावरण ने उनके दर्द बिंदुओं को निरंतर आधार पर संबोधित करना अनिवार्य बना दिया है। सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए जीएसटी दरों को कम करके, सरकार न केवल उनके वित्त को मजबूत करेगी बल्कि उनकी डिजिटलीकरण यात्रा को भी आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि एक दूरदर्शी सरकार के साथ देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करने के साथ उम्मीद है कि बजट एमएसएमई के लिए उपरोक्त चुनौतियों को पूरा करेगा और हमें एक आत्मनिर्भर भारत के सपने के करीब ले जाएगा।

देश आर्थिक महाशक्ति की ओर अग्रसरः कपिल

लखनऊ। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अमृत काल मे आने वाले पच्चीस वर्ष को ध्यान मे रखते हुए भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं मध्यम वर्ग सहित समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े गुजर बसर करने वाले अन्त्योदय की भावना को, गांव, गरीब, किसान व्यापारी सभी की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए उनके विकास के सपनों को चरितार्थ करता हुआ यह वार्षिक बजट निश्चित रूप से देश के सर्वांगीण विकास के सन्दर्भ मे मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरुआत की जाएगी और इसके उद्योग जगत 4 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।

जनमानस के साथ विश्वासघात

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि जैसे सरकार ने 9 वर्षों के बजट में देश के जनमानस के साथ विश्वासघात किया ठीक वैसे ही इस दसवें बजट में भी किया है। दुबे ने कहा कि इस बजट में भी घोषणाओं, वादों और आश्वासनों कि भरमार है। इस बजट में किसानों, नौजवानों व मध्यम वर्ग के लोगों की पूरी तरह से अनदेखी की गयी है और ये बजट बेरोजगारी व महंगाई को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के बजट में किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का का वादा किया जाता था लेकिन इस बजट में ये नहीं बताया गया कि आमदनी दोगुनी होने कि लिए किसान को और कितने वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा।

अपराध से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क

संवाददाता। सीतापुर

योगी सरकार में अपराधियों के सफाए और क्राइम कंट्रोल करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सीतापुर की पुलिस ने एक और गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीतापुर के पिसावां पुलिस ने गो-तस्करी में शामिल आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने के बाद बुधवार को करीब 20 लाख से अधिक की संपत्ति पर सरकारी ताला लगा दिया है। गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से अपराधियों के होश उड़े हैं। आइये आपको पिसावां पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से रूबरू कराते है।

- गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद डीएम के आदेश पर सीज हुई संपत्ति
- गो तस्करी के मामले में शामिल था आरोपी तालिब हरदोई का है निवासी

एएसपी साउथ एनपी सिंह की माने तो हरदोई जिले के थाना पिहानी इलाके के मोहल्ला नागर पश्चिम का निवासी तालिब शातिर अपराधी है, वह गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था, जिसमें गो-वंशीय पशुओं की तस्करी उसका पेशा था। उसके खिलाफ पूर्व में डीएम के आदेश पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उसकी संपत्ति के बारे में पता लगाया जा रहा था, पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि आरोपी के पास आय का स्रोत नहीं है, वह गो-तस्करी के जरिए पैसे कमाकर संपत्ति बना रहा था। इसके बाद डीएम अनुज सिंह के आदेश पर बुधवार को मोहल्ला नागर पश्चिम कस्बे में उसके मकान और हरदोई में एक मंजिला मकान को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई है। एएसपी की माने तो जब्त की गई संपत्ति की कीमत 20 लाख 30 हजार रूपए है। सीतापुर के एएसपी साउथ एनपी सिंह के अनुसार इस तरह का अपराध करने वाले अन्य अपराधियों के बारे में पुलिस लगातार जानकारियां जुटा रही है। अन्यकई गैंगस्टर भी पुलिस के रडार पर है, उनके खिलाफ भी जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा।

कांग्रेसियों ने चलाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान

बरेली। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत सुबह 11 बजे ब्लाक रामनगर के ग्राम महमूदपुर से हुई मजरा दौलतपुर, तिगरा खानपुर होते हुए समापन शाम को 6 बजे ग्राम मऊ चनदपुर में हुआ । आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के यात्री लगभग 20 किलोमीटर तक चले । हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के ग्राम मऊ चनदपुर पर समापन पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने की। संचालन जिला महासचिव सूर्य गांधी ने किया।

बैठक में उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पहलू हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, जिसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी जी का संदेश पत्र लोगों को दे रहे हैं।

राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरू

संवाददाता। सीतापुर

कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन यूपी के सीतापुर में बुधवार से राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरूआत की है। इस यात्रा के जरिए संगठन की मंशा है कि सनातन धर्म के लोगों से संपर्क बढ़ा कर हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। अब यह यात्रा अपने मकसद में कितना कामयाब होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

दरअसल मंगलवार को सामाजिक संगठन राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की ओर से प्रस्तावित हिंदू जोड़ो यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष

- नैमिषारण्य से शुरू हुई यात्रा, गांव, कस्बे से शहर तक जाएगी
- यात्रा के जरिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की कही बात

विकास हिंदू के नेतृत्व में नैमिषारण्य से हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व और राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू, जिला अध्यक्ष देश दीपक हिन्दू के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने चक्रतीर्थ पर पूजन अर्चन किया। इसके बाद पूरा दल मां ललिता देवी के मंदिर में पहुंचा। यहां से सभी लोग हनुमानगढ़ी गए, फिर नैमिषारण्य कस्बे में पैदल भ्रमण करते हुए लोगों से मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की अपील की। नैमिषारण्य से यात्रा लक्ष्मण नगर, ठाकुरनगर गांव पहुंची। जहां सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के बारे में अवगत कराया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने कहा कि यह यात्रा अनवरत चलती रहेगी। गांव-गांव जाकर के हिंदुत्व और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का। कांग्रेस की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं।

एसबीएम-नगरीय 2.0 : खीरी में हुआ 10 तक डोर-टू-डोर अभियान का आगाज

संवाददाता। लखीमपुर खीरी

नगरीय सुविधाओं के स्तरोन्नयन, नगरों के सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बुधवार को स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के तहत जनपद खीरी में नगरीय निकायों में 10 तक डोर टू डोर अभियान का आगाज हुआ। विधायक योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एडीएम संजय सिंह के साथ नगर पालिका परिषद लखीमपुर द्वारा आयोजित अभियान का शुभारंभ करते हुए कलेक्ट्रेट में जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय 2.0 के तहत सूखे, गीले कचरे को अलग-अलग कराकर शत प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए 01 फरवरी से 31 मार्च तक 03 चरणों में '10तक- डोर टू डोर' अभियान प्रार्थना, सहमत, चालान की दृष्टि से चलाया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण 01 से 15 फरवरी तक, द्वितीय चरण 16 फरवरी से 03 मार्च तक और तीसरा चरण 04 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जाएगा।

विधायक सदर योगेश वर्मा ने कहा कि नगरों को 'गुड टू ग्रेट' तथा वैश्विक मापदंडों के अनुरुप बनाने के लिए सबसे पहले कूड़े का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करना जरूरी है। इसके लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कूड़े का सोर्स सेग्रीगेशन किया जाना जरूरी है।

मौर्य को महासचिव बनाकर सपा ने असली चेहरा किया उजागर

फतेहपुर। अखिल भारत हिंदू महासभा की मासिक बैठक में जहां संगठन मजबूती पर चर्चा की गई वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा अनवरत सनातन धर्म व रामचरितमानस पर की जा रही अशोभनीय टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री मनोज त्रिवेदी ने कहा कि रामायण के प्रति स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उनको पुरस्कार देकर उनकी रामायण के प्रति की गई टिप्पणी का समर्थन करके सनातन धर्म के प्रति अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है, जबकि कट्टर समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया सदैव भगवान श्रीराम व रामायण के प्रति श्रद्धा प्रेम रखते थे। बैठक में वर्तमान समय में गरीबों के नये राशन कार्ड आनलाइन करने के बाद न बनने तथा कोटेदारों द्वारा राशन की घटतौली किए जाने का मुद्दा भी उठा। निर्णय लिया गया कि पंद्रह फरवरी को जिला पूर्ति कार्यालय का घेराव करके समस्याओं का निदान कराया जायेगा। बैठक में जिला प्रवक्ता स्वामी राम आसरे आर्य, करन सिंह पटेल, शशीकांत मिश्र, एसके गुप्ता, श्रवण कुमार राजपूत, प्रमोद पांडेय, अंजली मिश्रा, शकुंतला देवी मौजूद रहे।

वाणिज्य कर विभाग की टीम ने की छापेमारी, मचा हड़कंप

संवाददाता। मौदहा (हमीरपुर)

बांदा से आई वाणिज्य कर विभाग की टीम ने अचानक कस्बा स्थित सप्लायरों की दुकान में छापेमारी कर दी, जिससे जहां उनमें हड़कंप मच गया तो वहीं कुछ दुकानदार आनन-फानन में अपनी-अपनी दुकानों का शटर गिराकर रफूचक्कर हो गए।

वाणिज्य कर विभाग की टीम नगर में व्यापार कर रहे व्यापारियों के ऊपर अभी भी अपनी नजरें तिरछी किए हुए है, जिस पर अधिकांश दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं आज दोपहर बाद अचानक बांदा से आई वाणिज्य कर विभाग की मंडलीय टीम ने कस्बा स्थित रश्मि पेट्रोल पंप के बगल में मौजूद तिवारी ट्रेडर्स की दुकान में छापेमारी कर दी जहां भारी मात्रा में गिट्टी, सीमेंट, मोरम, डस्ट तथा लोहा मौजूद था, हालांकि वाणिज्य कर विभाग की टीम द्वारा मौके का सर्वे शुरू कर दिया था। हालांकि टीम द्वारा की गई छापेमारी को देखकर अगल बगल स्थित दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों का शटर गिरा कर वहां से रफू चक्कर हो गए, वहीं इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एसआईबी के डिप्टी कमिश्नर वीपी सिंह ने बताया कि अभी जांच चल रही है जिसमें कुछ कहना मुश्किल है लेकिन जांच में उचित कार्यवाही ही की जाएगी।

डीएम की सख्ती का असर, 21 लाख बकाया होने पर मकान सीज

मऊ/चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द की सख्ती का असर अधिकारियों पर नजर आ रहा है। मऊ तहसील क्षेत्र के बड़े बकायेदारों के खिलाफ जारी अभियान में तहसीलदार राजेश कुमार यादव की अगुवाई में राजस्व कर्मियों ने क्षेत्र के बकायेदार का मकान सीज कर दिया है।

बुधवार को मऊ तहसील के एसडीएम नवदीप शुक्ला के निर्देश पर राजस्व कर्मियों ने दस बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान के तहत कमल नारायण मिश्रा पुत्र संगमलाल मिश्रा निवासी बरियारीकला पर 21 लाख के बकाया होने पर उनका मऊ स्थित मकान सीज कर दिया है। तहसीलदार राजेश कुमार यादव की अगुवाई में चले अभियान में दो अन्य बकायेदार जगपत पुत्र मंगू निवासी धवाडा व दीपक पुत्र श्यामलाल निवासी सिकरो के धनराशि न जमा करने पर तहसील में कैद किया गया।

एसडीएम शुक्ला ने बताया कि ये कार्यवाही तहसील क्षेत्र के बकायेदारों के खिलाफ की जा रही है। बकायेदार तुरन्त धनराशि अमीनों के पास जमा कर दें। बकायेदार की रिकवरी तत्काल प्रभाव से सम्पर्क कर अमीन जमा करा दें। ऐसा न करने पर बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

पेज एक का शेष

आयकर मोर्चे पर...

यह वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले तीन गुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से सड़कों और ऊर्जा सहित पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत ऐट 100 के लिए खींची गई रेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान है जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक नरमी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है। बजट में कुल व्यय 7.4 प्रतिशत बढ़कर 45 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान रखा गया है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है। यह चालू वित्त वर्ष के 6.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है। इसका मतलब है कि सरकार को कुल 15.43 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ेगा। सीतारमण ने कहा कि 2023-24 के बजट में सात प्राथमिकताएं रखी गई हैं। ये हैं समावेशी विकास, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित वृद्धि, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र। बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन पर जोर के साथ कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। मझोले और छोटे उद्यमों के लिए कर्ज गारंटी को लेकर 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छोटे और मझोले शहरों (टियर दो और टियर तीन) में ढांचागत सुविधाएं तैयार करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूआईडीआईएफ) बनाया जाएगा। बजट में ऊर्जा बदलाव यानी स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाने और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 4,000 मेगावॉट घंटा (एमडब्ल्यूएच) क्षमता की बैटरी भंडारण प्रणाली को व्यावहारिक बनाने के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। लद्दाख से 13,000 मेगावॉट बिजली के पारेषण के लिए व्यवस्था तैयार करने को लेकर 20,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सस्ते मकान उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यय को 66 प्रतिशत बढ़कर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे के तहत 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जलीय हवाईअड्डों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने बजट के बारे में कहा, उच्च महंगाई और वैश्विक चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कम राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सरकार की वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को बताता है।

देशभर में खुलेंगे...

यह नर्सिंग कॉलेज 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ होंगे। वहीं स्वायत्त निकायों में, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए आवंटन 4,400.24 करोड़ रुपये से घटाकर 4,134.67 करोड़ रुपये किया गया है। जबकि आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 28 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए बताया कि बजट में 2047 तक अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। यह जागरूकता निर्माण, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0-40 वर्ष आयु वर्ग के सात करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच, और केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के माध्यम से परामर्श प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सहयोगी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों तथा निजी क्षेत्र की अनुसंधान और विकास टीम को अनुसंधान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,845.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,647.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट में आवंटित 89,155 करोड़ रुपये में से 86,175 करोड़ रुपए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आवंटित किए गए हैं, जबकि 2,980 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आवंटित किए गए हैं। नए वित्त वर्ष से, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को दो उप-योजनाओं में विभाजित किया गया है। इसमें पहली खुद पीएमएसएसवाई है और दूसरी योजना 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने से संबंधित व्यय की है, जिसके लिए 6,835 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2023-2024 के वास्ते प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए बजट आवंटन 3,365 करोड़ रुपए है। केंद्रीय क्षेत्र की इन योजनाओं में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट आवंटन 2022-23 के 28,974.29 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 29,085.26 करोड़ रुपये किया गया है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के लिए यह 6,412 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन-एनएचएम के लिए आवंटन 140 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 341.02 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन 121 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 133.73 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्वायत्त निकायों के लिए बजट आवंटन 2022-23 के 10,348.17 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 17,322.55 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आईसीएमआर के लिए आवंटन 2,116.73 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,359.58 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एकलव्य स्कूलों में...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। आम चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रमुख उद्योग घराने अंत:विषय अनुसंधान करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और कृषि, स्वास्थ्य, टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में भागीदार होंगे। सीतारमण ने कहा कि 5-जी सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यवसायों के सहयोग से इंजीनियरिंग संस्थानों में कुल 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा, 'अवसरों की नई श्रृंखला, व्यापार मॉडल और रोजगार क्षमता के लिए, प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, कुशल परिवहन प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल जैसे अनुप्रयोगों को कवर करेंगी।' मंत्री ने बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की घोषणा की ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें, अलग-अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने बताया कि राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अलगे तीन वर्षो में 740 मॉडल आवासीय एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और अन्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी जिसका 3.5 लाख जनजातीय छात्रों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाना देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्एतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुन:पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि हमारे युवाओं को सशक्त बनाने और अमृत पीढ़ी के सपने साकार करने में मदद करने हेतु, हमने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति निरूपित की है, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है।

गरीब-मध्य वर्ग के...

संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किए जाने के बाद एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट वंचितों को वरीयता देता है, यह आज के आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। बजट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (पीएम-विकास) के प्रावधान का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार ऐसे मेहनत और सृजन करने वालों के लिए बजट में पहली बार योजना लेकर आई है जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला स्व:सहायता समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में की गई पहल उन्हें एक नया आयाम देगी। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना अब जन धन खातों के बाद एक विशेष बचत योजना के रूप में आई है और यह सामान्य परिवार की महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी सहकारिता बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ-साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा, किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट टिकाऊ भविष्य के लिए हरित वृद्धि, हरित अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, हरित अवसंरचना और हरित नौकरी को अभूतपूर्व विस्तार देगा। इसमें प्रौद्योगिकी और नई इकनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है।उन्होंने कहा कि आकांक्षी भारत आज सड़क, रेल, मेट्रो, बंदरगाह, जलमार्ग हर क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना चाहता है, इसलिए 2014 की तुलना में अवसंरचना में निवेश पर 400 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई है।

कृषि ऋण के लिए...

वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सरकार इस उद्देश्य के लिए एक करोड़ किसानों को सुविधा प्रदान करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण संजाल बनाने के लिए 10,000 जैव-लागत संसाधन केंद्र भी स्थापित करेगी। सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक कृषि त्वरित कोष (एएएफ) स्थापित करेगी। समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के मकसद से कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को मोटे अनाज, जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है, का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, हैदराबाद स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम व्यवहार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। देश में ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा जैसे कई प्रकार के मोटे अनाज उगाए जाते हैं। वित्त मंत्री ने कहा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है। सरकार हर साल कृषि क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य बढ़ा रही है। आमतौर पर, कृषि ऋण पर नौ प्रतिशत की ब्याज दर लगती है। हालांकि, सरकार सस्ती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। किसानों को सात प्रतिशत सालाना की प्रभावी दर पर तीन लाख रुपये तक का अल्पावधि कृषि ऋण सुनिश्चित करने के लिए सरकार दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है। औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों के दायरे को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने गारंटी-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का फैसला किया है।

रेल के सफर को...

रेलवे की पुरानी पटरियों को बदलने के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए जाने की संभावना है, क्योंकि रेलवे, ट्रेनों को गति देने तथा अधिक स्थानों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरूआत करने की योजना बना रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रेलवे 100 और विस्टाडोम कोच बनाने का प्रस्ताव कर रहा है। इस बजट में सरकार ने हाइड्रोजन ईंधन आधारित 35 ट्रेन, साइड एंट्री के साथ 4,500 नए डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल वाहक कोच, पांच हजार एलएचबी कोच और 58,000 वैगन के निर्माण का का प्रस्ताव दिया है। बजट दस्तावेज के अनुसार, वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में रेलवे का सकल राजस्व व्यय 2,65,000 करोड़ रूपया रहा जो वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में 2,42,892.77 करोड़ रुपया रहा था। बजट अनुमान 2023-24 में पूंजीगत व्यय के लिए 2,60,200 करोड़ रुपये प्रदान किए गए जिसमें 2,40,000 करोड़ रुपये सामान्य राजस्व से, 200 करोड़ रुपया निर्भया कोष से, 3000 करोड़ रुपये आंतरिक संसाधन से और 17,000 करोड़ रुपये आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन से जुटाए गए।

रक्षा क्षेत्र के लिए...

2023-24 के बजट में, रक्षा मंत्रालय (सिविल) के लिए पूंजीगत परिव्यय 8,774 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि पूंजीगत परिव्यय के तहत 13,837 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। पेंशन परिव्यय सहित कुल राजस्व व्यय 4,22,162 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, रक्षा बजट का कुल आकार 5,93,537.64 करोड़ रुपये है।

भाजपा ने सराहा, विपक्ष बोला...

रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है और असमानता दूर करने का कोई इरादा नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान नहीं किया गया। इसी प्रकार बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए हो तो बेहतर होता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई बजट महंगाई एवं बेरोज़गारी दोनों को और बढ़ाता है। भाजपा सरकार ने जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। राज्यसभा सदस्य और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त आवंटन नहीं करने का आरोप लगाया है। बीआरएस सांसद के केशव राव ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र को तेलंगाना से सौतेली मां जैसा भी प्यार नहीं है। उन्होंने कहा कि आम जनता जो कुछ चाहती है, वैसा कुछ भी नहीं है। तेलंगाना टेक्सटाइल पार्क के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता है, लेकिन बजट में इस योजना के लिए एक रुपया भी नहीं दिया गया। बीआरएस सांसद नमा नागेश्वर राव ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कोई योजना का प्रावधान नहीं किया गया है।

अमृत काल की...

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आधारभूत ढांचे के विकास को गति देने के लिए बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन में सुधार लाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट को समावेशी, विकासोन्मुख और दूरदर्शी बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की। नड्डा ने कहा कि अमृत काल का पहला केंद्रीय बजट प्रधान मंत्री मोदी की दूरदर्शिता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, हाशिए पर पड़े वर्गों एवं मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने की प्राथमिकता के साथ विकास एवं कल्याण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इससे देश को कुछ वर्षों के भीतर ही पांच ट्रिलियन (पांच हजार अरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था और विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। सिंह ने कहा कि कृषि, आवास, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्रों में खर्च बढ़ाने के साथ ही बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं में निवेश से नौकरियों के अवसर सृजित होंगे एवं आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि आम बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन को गति देकर भारत को प्रौद्योगिकी से प्रेरित एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने का ठोस आधार तैयार किया गया है।

समावेशी, हर वर्ग को...

मोदी सरकार के पिछले बजटों के प्रावधानों से ही आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ सबसे ज्यादा विकास दर से आगे बढ़ने वाला देश बना है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ आजादी के अमृत काल यानी 75वें वर्ष से लेकर आजादी के 100वें वर्ष तक विकसित भारत का खाका भी प्रस्तुत करता है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के पंच प्रण से प्रेरित इस बजट के सात आधार सप्तऋषि अर्थात समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, नए भारत-आत्मनिर्भर भारत निर्माण की बुनियाद बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की युवाशक्ति का इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना, एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के दो लाख करोड़ रुपये तक के क्रेडिट जैसे प्रस्ताव युवाओं के सपनों को नई उड़ान देंगे।

राकेश सचान ने आम बजट को महिला, गांव, गरीब और किसानों का बजट बताया

संवाददाता। कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहर कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किये गये वर्ष 2023-24 के आम बजट में महिला, गांव, गरीब और किसानों को प्राथमिकता दी गई है।

इस बजट में खासतौर से श्रमिकों एवं मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बजट में किये गये प्राविधान से प्रदेश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। सचान ने एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को पूरे देश में विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री जी व वित्तमंत्री जी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरे देश में लागू करने से व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन होगा और देश व प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओडीओपी योजना के तहत यूनिटी मॉल खोलने, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना तथा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से हस्तशिल्पियों, पारंपरिक कारीगरों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने प्रदेश में इनक्यूबेशन केन्द्र की मंजूरी को उद्यमियों का हितैशी बताया और कहा कि इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से नये उद्यमियों पर फोकस किया गया है। इससे उद्योगों तथा उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी।

परिचय पत्रों का लोकतंत्र सेनानियों ने नवीनीकरण कराने की मांग की

उरई (जालौन)। भारतीय लोकतंत्र रक्षक सेनानी समिति उप्र के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम व्यास व जिलाध्यक्ष अवध शर्मा बब्बा ने जिलाधिकारी को संबोधित एक मांग पत्र सदर उप जिलाधिकारी राजेश सिंह को सौंपा जिसमें जनपद के सभी लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के परिचय पत्रों को नवीनीकरण कराने की मांग की। बुधवार को लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी सदर से भेंट कर उन्हें जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया कि जनपद के लोकतंत्र सेनानियों के परिचय पत्रों की समयावधि कालातीत होने के सन्निकट है। ऐसी स्थिति में परिचय पत्रों की समयाविध समाप्त होने के कारण परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने में लोकतंत्र सेनानियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सेंसेक्स चढ़ा लेकिन निफ्टी फिसला

भाषा। मुंबई

संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने के दिन बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में खासा उतार-चढ़ाव देखा गया। बाजार के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद मुनाफावसूली हावी होने से दोनों प्रमुख सूचकांक मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 158.18 अंक यानी 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,708.08 अंक पर बंद हुआ। बजट भाषण के समय बाजार के उत्साहित होने से सेंसेक्स 1,223.54 अंक तक उछल गया था लेकिन बाद में बिकवाली का सिलसिला चलने से इसने अपनी अधिकांश बढ़त गंवा दी।

इसके उलट एनएसई के सूचकांक निफ्टी में 45.85 अंक यानी 0.26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 17,616.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में आईटीसी ने सर्वाधिक 2.61 प्रतिशत की बढ़त हासिल की। टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी लाभ की स्थिति में रहे। दूसरी तरफ बजाज

फिनसर्व, भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 5.65 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, बजट में खपत और पूंजीगत व्यय पर खासा जोर दिया गया है। इससे बाजार में उम्मीदों को बल मिला लेकिन अपराह्न कारोबार में निवेशकों का ध्यान अडाणी प्रकरण और फेडरल रिजर्व की बैठक पर चले जाने से उठापटक का दौर शुरू हो गया।

नायर ने कहा कि सरकार की तरफ से नई कर प्रणाली को बढ़ावा देने से जीवन बीमा कंपनियों के कर-बचत के लिहाज से कम आकर्षक रह जाने की आशंका में जमकर बिकवाली हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धीरज रेली ने बजट को व्यावहारिक बताते हुए कहा कि इसमें कोई बड़ी नकारात्मक घोषणा न होने से बाजार ने अच्छी प्रतिक्रिया दी लेकिन अब निवेशकों की नजर फेडरल रिजर्व की मौद्रिक घोषणा पर टिकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने और लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहन देने के साथ ही सरकार के पूंजीगत व्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की। सैमको सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक संजय मूरजानी ने कहा, व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर सरकार की तरफ से दी गई राहतों ने बाजार को खासी तेजी दी। इसके अलावा पूंजीगत लाभकर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना भी बाजार को रास आया। हालांकि दोपहर के बाद के कारोबार में अडाणी समूह को लेकर चिंता हावी होने और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की आसन्न मौद्रिक घोषणा को लेकर दबाव देखा गया।

इसके असर में व्यापक बाजार में बीएसई स्मॉलकैप 1.10 प्रतिशत गिर गया जबकि मिडकैप में 0.96 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, वैश्विक बाजारों में कुल मिलाकर सकारात्मक रुझान रहने से निवेशकों को बल मिला। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग मजबूती के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार भी मंगलवार को लाभ में रहे थे। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85.42 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से निकासी जारी रखी है। शेयर बाजारों के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 5,439.64 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे।

नई कर व्यवस्था में बदलाव से आयकरदाताओं को होगा लाभ

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में नई कर व्यवस्था में बदलाव से करदाताओं को लाभ होगा। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय नौ लाख रुपए है तो उन्हें अब 45,000 रुपए की ही कर देने होंगे, जो पहले 60,000 रुपए बनता था।

इसी प्रकार, किसी व्यक्ति की आय अगर 15 लाख रुपए सालाना है, उसे केवल 1.5 लाख रुपए या अपनी आय का केवल 10 प्रतिशत ही कर देना होगा। यह नई कर व्यवस्था के मौजूदा स्वरूप के तहत बनने वाले 1,87,500 रुपए से करीब 20 प्रतिशत कम है। वित्त मंत्री ने कहा, यह नई कर व्यवस्था सभी करदाताओं को बड़ी राहत देगा। नई कर व्यवस्था में जिस बदलाव का प्रस्ताव किया गया है, उसके तहत सात लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि, निवेश और आवास भत्ता जैसी छूट वाली पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही पुरानी कर व्यवस्था में मानक कटौती के रूप में 50,000 रुपए का लाभ अब नई कर व्यवस्था में भी मिलेगा। इसके अलावा, बजट में गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के एवज में किए जाने वाले भुगतान पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

सीमा शुल्क में कटौती से 3,000 तक सस्ता हो सकता है टीवी सेट

भाषा। नई दिल्ली

स्थानीय स्तर पर विनिर्मित टीवी सेट के दाम 3,000 रुपए तक घट सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयात किए जाने वाले कलपुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को पांच प्रतिशत से घटाकर आधा यानी 2.5 फीसदी कर दिया है।

उद्योग की कुछ कंपनियों का कहना है कि ओपन सेल के घटकों पर सीमा-शुल्क में कटौती से टीवी के दाम करीब पांच प्रतिशत कम हो सकते हैं। एलईडी टीवी सेट की विनिर्माण लागत में 60 से 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ओपन सेल पैनल का होती है। ज्यादातर टीवी विनिर्माता इन पैनलों का आयात करते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पैनल के ओपन सेल के हिस्सों पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया जाता है।

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संघ (सीईएएमए) के अध्यक्ष एरिक ब्रेगेंजा ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र की वृद्धि होगी और घरेलू स्तर पर मूल्यवर्द्धन होगा। उन्होंने कहा कि यह उद्योग के लिए एक अच्छा कदम है और इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय बाजार में थॉमसन, कोडक और व्हाइट-वेस्टिंगहाउस जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के लिए लाइसेंस रखने वाली सुपर प्लास्ट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं संस्थापक अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि इस कदम से टीवी सेट के दाम पांच फीसदी तक कम हो जाएंगे।

सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नैय्यर ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से टेलीविजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के चेयरमैन मनीष शर्मा ने कहा कि मध्यम और उच्च वर्ग दोनों के लिए कर में कटौती की गई है जिससे करदाता के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और इसके परिणामस्वरूप मांग और खपत बढ़ेगी।

हायर अप्लाइंसेस इंडिया के अध्यक्ष सतीश एन एस ने कहा कि सीमा शुल्क में कटौती से विनिर्माताओं को तो लाभ होगा ही, कई उपभोक्ताओं किफायती दर पर टेलीविजन खरीद पाएंगे जिससे उनकी जीवनशैली बदलेगी।

दूरसंचार, डाक परियोजनाओं के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने डाक और दूरसंचार परियोजनाओं के लिए आम बजट में 1.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसमें से 52,937 करोड़ रुपए की पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल में डाली जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि कुल आवंटन में 97,579.05 करोड़ रुपए दूरसंचार विभाग के लिए और 25,814 करोड़ रुपए डाक परियोजनाओं के लिए हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार बीएसएनएल में 52,937 करोड़ रुपए लगाएगी। इसके अलावा रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क के लिए सरकार ने 2,158 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में दूरसंचार परियोजनाओं के लिए 715.8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डाक विभाग के लिए कुल 25,814 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसमें से 250 करोड़ रुपए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डाले जाएंगे।

दूरसंचार क्षेत्र से गैर-कर राजस्व संग्रह का लक्ष्य 30 प्रतिशत बढ़ाया गया

नई दिल्ली। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए गैर-कर राजस्व संग्रह का अनुमान 30 प्रतिशत बढ़ाकर 89,469.17 करोड़ रुपए कर दिया है। बुधवार को संसद में पेश आम बजट में यह जानकारी दी गई। सरकार ने दूरसंचार विभाग में चालू वित्त वर्ष के लिए भी गैर-कर राजस्व संग्रह लक्ष्य संशोधित कर 68,784 करोड़ रुपए कर दिया है जबकि पहले यह 52,806 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में दूरसंचार क्षेत्र का वास्तविक राजस्व 85,828 करोड़ रुपए रहा।

दूरसंचार क्षेत्र से गैर-कर राजस्व का संबंध मुख्यत: दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से मिलने वाले लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की प्राप्तियों से होता है।

एनएचएआई के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ की गई

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार अवसंरचना पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। एनएचएआई को आवंटित चालू वित्त वर्ष में संशोधित राशि 1.42 लाख करोड़ रुपए थी।

आम बजट 2023-24 में राजमार्ग क्षेत्र के लिए परिव्यय बढ़ाकर 2.70 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजमार्ग क्षेत्र के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में संशोधित कर 2.17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। एनएचएआई और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिम्मा देखती हैं।

सहकारी क्षेत्र के लिए कर राहत

भाषा। नई दिल्ली

सहकारिता मंत्रालय के बजट आवंटन में कटौती

सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बुधवार को कई उपायों की घोषणा की जिसमें विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वालीं नई सोसायटी पर 15 प्रतिशत की रियायती दर से कर लगाने तथा नकद निकासी पर टीडीएस के लिए तीन करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा तय करना भी शामिल है।

सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 1,150.38 करोड़ रुपए का कुल बजट परिव्यय निर्धारित किया है। हालांकि यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान 1,624.74 करोड़ रुपए से कम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नकद जमा और नकद में ऋण के लिए प्रति सदस्य दो लाख रुपए की उच्च सीमा तय करने की घोषणा की। सरकार ने चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का मौका भी दे दिया है। इससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार की यह घोषणा छोटे एवं सीमांत किसानों और अन्य कमजोर तबकों के लिए सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच की गई है।

सीतारमण ने कहा कि सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 पैक्स समितियों का कम्प्यूटरीकरण पहले ही शुरू कर चुकी है। सभी हितधारकों और राज्यों के परामर्श से पैक्स समितियों के लिए मॉडल नियम बनाए गए थे ताकि इन्हें बहुउद्देशीय समिति बनाया जा सके। सहकारी समितियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

चालू वित्त वर्ष में खाद्य, उवर्क, पेट्रोलियम सब्सिडी 5.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान

भाषा। नई दिल्ली

खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर सरकार की सब्सिडी चालू वित्त वर्ष में 17 प्रतिशत बढ़कर 5.21 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 2023-24 में इसके 28 प्रतिशत कम होकर करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

बजट दस्तावेज के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने संशोधित अनुमान (आरई) में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर कुल सब्सिडी 5,21,584.71 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है। पिछले वित्त वर्ष में इसका वास्तविक बजट 4,46,149.24 करोड़ रुपए था।

इन तीन मदों पर कुल सब्सिडी में से चालू वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी मामूली रूप से घटकर 2,87,194.05 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2021-22 में 2,88,968.54 करोड़ रुपए थी। हालांकि, इस वित्त वर्ष के दौरान उर्वरक सब्सिडी बढ़कर

2,25,220.16 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,53,758.10 करोड़ रुपए थी। इस दौरान यूरिया पर सब्सिडी 1,00,988.13 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,54,097.93 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी 52,769.97 करोड़ रुपए से बढ़कर 71,122.23 करोड़ रुपए हो गई है। पेट्रोलियम सब्सिडी भी उक्त अवधि में 3,422.60 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,170.50 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए यूरिया के साथ-साथ फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को कम कीमत पर उर्वरक मिलते रहें। अगले वित्त वर्ष के लिए खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर कुल सब्सिडी 2022-23 में 5,21,584.71 करोड़ रुपए से 28 प्रतिशत घटकर 3,74,707.01 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

इसमें से उर्वरक सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के 2,25,220.16 करोड़ रुपए से घटकर 2023-24 में 1,75,099.92 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। पेट्रोलियम सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के 9,170.50 करोड़ रुपए से घटकर 2,257.09 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। खाद्य सब्सिडी, वित्त वर्ष 2022-23 के 2,87,194.05 करोड़ रुपए से घटकर अगले वित्तवर्ष में 1,97,350 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, क्योंकि सरकार ने महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त खाद्यान्न योजना को बंद कर दिया है।

बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33% बढ़ा, 10 लाख करोड़ करने की घोषणा

भाषा। नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत बैठता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि हाल में स्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय की मदद से और निजी निवेश आकर्षित किया जा सकेगा।

सीतारमण ने कहा, पूंजीगत निवेश की रूपरेखा लगातार तीसरे वर्ष उल्लेखनीय रूप से बढ़ाई गई है। इसे 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है जो जीडीपी का 3.3 फीसदी होगा। उन्होंने कहा कि यह 2019-20 की तुलना में लगभग तीन गुना होगा। उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति की भी स्थापना की जाएगी जो अवसंरचना वर्गीकरण और वित्तीय रूपरेखा को अमृत काल के लिए उपयुक्त बनाने का काम करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि बंदरगाह, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने के लिए सौ अहम परिवहन ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा, इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और इनमें 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें से 15,000 करोड़ रुपए निजी स्रोतों से आएंगे। पिछले साल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस बजट में समृद्ध एवं समावेशी भारत की संकल्पना की गई है जिसमें विकास का लाभ हर वर्ग तक, प्रत्एक नागरिक तक विशेषकर देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातिाअनुसूचित जनजाति के लोगों तक पहुंच सके।

ऑनलाइन खेलों में जीती गई शुद्ध राशि पर 30% टीडीएस का प्रस्ताव

नई दिल्ली। सरकार ने आम बजट में ऑनलाइन खेलों में जीती जाने वाली शुद्ध राशि पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। उसने 10,000 रुपए की मौजूदा कर सीमा को भी खत्म कर दिया है।

बजट 2023-24 में ऑनलाइन खेलों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए दो नए प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसमें वित्त वर्ष के दौरान जीती गई शुद्ध राशि के भुगतान पर 30 फीसदी कर लगाना और टीडीएस लगाने के लिए 10,000 रुपए की मौजूदा सीमा को खत्म करना शामिल है। यदि राशि उपयोगकर्ता के खाते से नहीं निकाली जाती है तो वित्त वर्ष के अंत में स्रोत पर कर काटा जाएगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बजट बाद संवाददाताओं से कहा कि कुल मूल्य में जीती गई शुद्ध राशि पर कर लगाया जाएगा।

विदेश यात्रा, बाहर रुपए भेजने पर टीसीएस को 20% करने का प्रस्ताव

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने बुधवार को विदेश यात्रा के टूर पैकेज और भारत से बाहर रुपए भेजने पर पर टीसीएस दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव बजट में रखा है। बुधवार को संसद में पेश बजट के जरिए प्रस्तावित वित्त विधेयक 2023-24 के माध्यम से विदेशी यात्रा कार्यक्रमों पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) वसूलते हुए आयकर अधिनियम की धारा 206सी में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भारत से बाहर सात लाख रुपए से ज्यादा राशि भेजने पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा। ए संशोधन एक जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगे। सलाहकार फर्म नांगिया एंडरसन के अमित अग्रवाल ने कहा कि टीसीएस को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना विदेशी मुद्रा भंडार की आरामदेह स्थिति को देखते हुए काफी आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि इस तरह सरकार विदेश दौरों पर बेतहाशा खर्च को हतोत्साहित करना चाहती है।

सार्वजनिक बिजली कंपनियां करेंगी 60,805 करोड़ रुपए का निवेश

नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बिजली कंपनियों की तरफ से किए जाने वाले कुल निवेश को वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 15 प्रतिशत बढ़ाकर 60,805.22 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। संसद में बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की गई।

इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक बिजली कंपनियों का निवेश अनुमान भी संशोधित कर 52,878.08 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान पहले 51,470.14 करोड़ रुपए का था।

बजट प्रस्तावों के मुताबिक, पनबिजली उत्पादक कंपनी एनएचपीसी के निवेश अनुमान को 7,128.95 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 10,857.22 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान 7,361.05 करोड़ रुपए का था। इसी तरह एसजेवीएन लिमिटेड का निवेश अनुमान अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पावरग्रिड के मामले में यह अनुमान 8,800 करोड़ रुपए पर स्थिर रखा गया है।

रिहायशी संपत्ति में पूंजीगत लाभ फिर से निवेश करने पर 10 करोड़ की छूट सीमा तय

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने बुधवार को एक संपत्ति बेचकर दूसरी रिहायशी संपत्ति खरीदने को लेकर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर पर कटौती को लेकर 10 करोड़ रुपए की सीमा लगाने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, कर रियायत और छूट को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54 एफ के तहत आवासीय मकान में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूं।

आयकर की दोनों धाराएं दीर्घकालीन संपत्तियों (आवासीय या अन्य पूंजीगत संपत्ति) की बिक्री से प्राप्त राशि के रिहायशी संपत्ति खरीदने के लिए फिर से निवेश से जुड़ा है। बजट दस्तावेज के अनुसार नए प्रावधान का उद्देश्य काफी महंगा रिहायशी मकान खरीदने के बाद उच्च नेटवर्थ करदाताओं की तरफ से बड़ी कटौती के दावे पर अंकुश लगाना है। आयकर कानून की धारा 54 और 54 एफ के तहत दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ पर कटौती का प्रावधान है। यह छूट उस स्थिति में मिलती है जब करदाता रिहायशी संपत्ति खरीदता या निर्माण करता है।

धारा 54 के तहत उस स्थिति में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कटौती उपलब्ध होती है जब रिहायशी मकान के हस्तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ को दोबारा से रिहायशी मकान में निवेश किया जाता है। वहीं 54 एफ के तहत कटौती का लाभ तब मिलता है जब रिहायशी मकान को छोड़कर दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ को रिहायशी मकान में निवेश किया जाता है। दस्तावेज में कहा गया है कि इन प्रावधानों का मकसद आवास की कमी को दूर करना तथा मकान निर्माण गतिविधियों में तेजी लाना था। लेकिन यह पाया गया कि उच्च नेटवर्थ वाले करदाता काफी महंगा मकान खरीदकर इन प्रावधानों के तहत बड़ी छूट का दावा करते हैं। इस तह इस प्रावधान का जो उद्देश्य था, वह पूरा नहीं हो रहा था। बजट दस्तावेज के मुताबिक इस पर रोक लगाने के लिए अधिकतम कटौती की सीमा लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका दावा करदाता धारा 54 और 54एफ के तहत कर सकते हैं। इसके तहत एक संपत्ति बेचकर दूसरी रिहायशी संपत्ति खरीदने को लेकर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर पर कटौती को लेकर 10 करोड़ रुपए की सीमा लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

आम बजट राष्ट्र निर्माण में मददगार, वृद्धि केंद्रित है : उद्योग मंडल

नई दिल्ली। भारतीय कंपनियों ने बुधवार को आम बजट 2023-24 पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे राष्ट्र निर्माण में मददगार, वृद्धि-केंद्रित और राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बजट में लगातार पूंजीगत व्यय और वित्तीय समावेश पर जोर दिया गया है। उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों ने कहा कि दृष्टि, संरचना और अनुशासन के साथ बजट भारत को विश्व गुरु बनने की राह पर ले जाता है। उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि बजट विकासोन्मुख है और इसमें पूंजीगत व्यय तथा समावेशन पर जोर दिया गया है। बजट में 2047 तक एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव रखी गई है। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा ने कहा कि बजट घोषणाओं ने अर्थव्यवस्था की नब्ज को समझा है, और साथ ही राजकोषीय समेकन की प्रतिबद्धता को भी निभाया गया है। उन्होंने कहा, वृद्धि चक्र की गति बनाए रखने के लिए निवेश और उपभोग को बढ़ावा देने की जरूरत थी। हमें यह जानकर खुशी हुई कि सरकार ने पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय पर जोर जारी रखा है। उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि 2023-24 का बजट राष्ट्र निर्माण के लिए एक मसौदा है, जिसमें बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने कहा, पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए करने का फैसला भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रखने के संकल्प को दर्शाता है।

चालू वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य घटाया

● 2023-24 में 51,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य को 65,000 करोड़ रुपए से घटाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। चालू वित्त वर्ष और साथ ही अगले वित्त वर्ष में सरकारी संपत्तियों के मौद्रीकरण से लगभग 10,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। पूंजीगत प्राप्तियों के बजट में विनिवेश से मिली रकम को विविध प्राप्तियों के तहत रखा जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट दस्तावेज़ के अनुसार चालू वित्त वर्ष में विविध पूंजीगत प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 60,000 करोड़ रुपए है। इस 60,000 करोड़ रुपए में 50,000 करोड़ रुपए विनिवेश से और 10,000 करोड़ रुपए संपत्ति के मौद्रीकरण से मिले हैं। अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 51,000 करोड़ रुपए सहित विविध पूंजीगत प्राप्तियां 61,000 करोड़ रुपए आंकी गई हैं। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट के अनुसार, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अबतक सीपीएसई में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 31,100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है, पूरे साल के बजट में इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक के अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, बीईएमएल, एचएलएल लाइफकेयर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विजाग स्टील जैसी कंपनियां का निजीकरण करना चाहती है।

नागर विमानन मंत्रालय को बजट में आवंटन आधे से ज्यादा घटाया, मिले 3113.36 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को पेश आम बजट 2023-24 में नागर विमानन मंत्रालय के लिए 3,113.36 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि की आधी से कम है। यह कमी विशेष रूप से एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के लिए निर्धारित राशि में भारी कमी के कारण हुई है। चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित आवंटन 9,363.7 करोड़ रुपए था, जो पूर्व में अनुमानित 10,667 करोड़ से कम था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश बजट 2023-24 में मंत्रालय के लिए 3,113.36 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आवंटित राशि में यह भारी गिरावट एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के लिए निर्धारित कम पैसे के कारण है। सरकार की विनिवेश प्रक्रिया के बीच पिछले साल जनवरी में टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था।

सरकार ने खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाकर सत्तर प्रतिशत किया

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को खिलौना और उसके कलपुर्जे तथा सामान पर आयात शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया। इस पहल का मकसद इन उत्पादों के आयात में कमी लाना तथा घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को गति देना है। बजट दस्तावेज के अनुसार इसी प्रकार, साइकिल के आयात पर भी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया है। खिलौनों और उसके कलपुर्जे तथा सामग्री पर आयात शुल्क में वृद्धि में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने शामिल नहीं है। स्थानीय स्तर पर खिलौना विनिर्माण को गति देने के लिए फरवरी, 2020 में खिलौनों पर मूल सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि देश में एक समय 2,960 करोड़ रुपए मूल्य के खिलौनों का आयात किया गया था। लेकिन सरकार के कदमों से 2021-22 में आयात घटकर 870 करोड़ रुपए रह गया। दूसरी तरफ, खिलौनों का निर्यात 2021-22 में 61 प्रतिशत बढ़कर 2,601 करोड़ रुपए रहा।

आयकर, कॉरपोरेट कर राजस्व 10.5% बढ़कर 18.23 लाख करोड़ रहने का अनुमान

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को अगले वित्त वर्ष में कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आय कर 10.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 18.23 लाख करोड़ रुपए रहने अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर राजस्व का संशोधित अनुमान 16.50 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि बजट अनुमान 14.20 लाख करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष (2022-23) में प्रत्यक्ष कर (आय और कॉरपोरेट कर) वित्त वर्ष 2021-22 में इन मदों से अर्जित राजस्व 14.08 लाख करोड़ रुपए से 17 प्रतिशत ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष में कॉरपोरेट कर से राजस्व 8.35 लाख करोड़ रुपए जबकि व्यक्तिगत आयकर 8.15 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

समाचार एजेंसियो के लिए आयकर छूट खत्म करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए समाचार एजेंसियों की आयकर छूट खत्म करने का प्रस्ताव प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक समाचार एजेंसी है और अगर इस बजट प्रस्ताव को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो उसपर भी इसका असर पड़ेगा। बजट के वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 22बी में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। अधिसूचित समाचार एजेंसियों को आयकर भुगतान से छूट प्राप्त है, बशर्ते संगठन अपनी आय केवल समाचारों के संग्रह एवं वितरण पर खर्च करता हो और उसे अपने सदस्यों के बीच वितरित नहीं करता हो। वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में कहा गया है कि समाचार एजेंसियों को मिली कर छूट को हटाने का कदम आयकर अधिनियम के तहत छूट और कटौती को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सरकार की घोषित नीति के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 10 के खंड 22बी के तहत समाचार एजेंसियों को मिली छूट को आकलन वर्ष 2024-25 से वापस लेने का प्रस्ताव है। कई समाचार पत्रों के साझा स्वामित्व वाली पीटीआई को इस खंड के तहत आकलन वर्ष 1994-95 से आयकर छूट मिलती रही है। इसकी वजह यह है कि पीटीआई अपने शेयरधारकों को कोई लाभांश नहीं देती है और यह एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में काम करती है। कंपनी की सभी आय का इस्तेमाल समाचार संग्रह के लिए ही किया जाता है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को भी आयकर छूट मिली हुई है क्योंकि यह समाचार एजेंसी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है।

कृषि उद्योग, किसान निकायों के बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

भाषा। नई दिल्ली

कृषि उद्योग से जुड़े लोगों और किसान संगठनों ने बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। बजट में खाद्य तेलों पर ध्यान नहीं दिया गया और कृषि उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने तथा पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग को अनसुना किया गया है। गोदरेज एग्रोवेट के प्रबंध निदेशक बलराम यादव ने बजट को भारतीय किसानों के लिए तकनीक केंद्रित और समावेशी करार दिया, सिंजेन्टा इंडिया के मुख्य सस्टेनिबिलिटी अधिकारी के सी रवि ने कहा कि यह कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के राघवेंद्र पटेल ने कहा, हालांकि सरकार ने इस बजट में कृषि और किसानों के हित में कई दूरगामी और अच्छे परिणाम देने वाले कदम उठाए हैं, फिर भी किसानों की उम्मीदें इस बजट से कहीं अधिक थीं। कोविड-19 के बाद, किसानों को कृषि लागतों की कीमतों में वृद्धि के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे पीएम-किसान के तहत वित्तीय सहायता में वृद्धि और विभिन्न लागतों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के रूप में समाधान की उम्मीद कर रहे थे। कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना से किसानों के शोषण पर अंकुश लगेगा, जबकि सहकारी समितियों के माध्यम से छोटे स्थानों पर कृषि उपज के भंडारण के अच्छे परिणाम मिलेंगे।

ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, एनसीडीईएक्स के प्रबंध निदेशक अरुण रास्ते ने कहा कि भंडारण क्षमता का विकेंद्रीकरण, जिसके बारे में वित्तमंत्री ने बात की है, एक प्रमुख निर्णय है और मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन को युक्तिसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एनसीडीईएक्स एफपीओ और छोटे व्यापारियों के साथ काम करता है जो विनियमित गोदामों का उपयोग करते हैं और मानक विकेंद्रीकृत भंडारण से देश को अत्यधिक बर्बादी को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसका अधिक प्रभाव होगा यदि वेयरहाउसिंग विकास एवं नियमन प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) विनियमन को जल्द ही संसदीय स्वीकृति मिल जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदें गोदाम रसीदों की जगह ले लेती हैं।

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसो. ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला के अनुसार, बजट अपेक्षित तर्ज पर था सिवाय इसके कि यह खाद्य तेलों के मोर्चे पर चुप था क्योंकि उद्योग निकाय खाद्य तेलों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने कहा कि हरित विकास को बढ़ावा देने की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि अरंडी खली और नीम बीज खली प्राकृतिक खेती के लिए सबसे अच्छे जैविक खाद हैं और जो उनकी खपत को बढ़ावा देंगे। इस तरह अरंडी के बीज उगाने वाले घरेलू किसानों और नीम के बीज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों का समर्थन करेंगे। झुनझुनवाला ने कहा कि कच्चे ग्लिसरीन पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना भी एक स्वागत योग्य कदम है जिससे घरेलू ग्लिसरीन शोधन उद्योग को मदद मिलेगी। सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया और सार्क के प्रबंध निदेशक (कृषि प्रभाग) नरिंदर मित्तल ने कहा कि बजट में टिकाऊकृषि और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। अनुपम रसायन के प्रबंध निदेशक आनंद देसाई ने कहा कि कुछ कच्चे माल – विकृत इथाइल अल्कोहल, एसिड ग्रेड फ्लोरस्पर और कच्चा ग्लिसरीन – पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट से भारतीय रासायनिक कंपनियों की समग्र उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।

छोटे किसानों को फायदा होगा : कृषि मंत्री

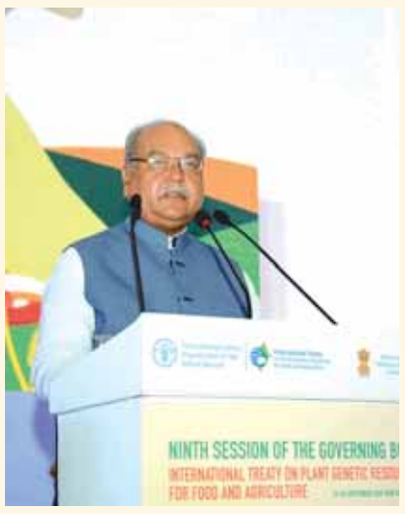

नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि बजट 2023-24 से देश भर के छोटे किसानों को फायदा होगा, जिसमें आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। तोमर ने कहा कि वित्तवर्ष 2023-24 के लिए उनके मंत्रालय के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर अनुमानित 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल हैं। मंत्री ने एक बयान में कहा, बजट से छोटे किसानों को लाभ होगा। इसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अगले वित्तवर्ष के लिए कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करना, मोटे अनाज और स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है। भारत में कुल कृषकों का 86 प्रतिशत हिस्सा, छोटे और सीमांत किसानों का है, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है।

सार्वजनिक सूचना- आइ० डी० कार्ड खो गया

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा वरुण गुप्ता को आई कार्ड जारी किया गया था जो दिनांक 6/1/2023 से लापता है जिनका क्रमांक 2225977 है। पाने वाला व्यक्ति इसे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एस डी टावर सेक्टर-8 रोहिनी दिल्ली-85 को वापस कर दे।

आईसीआईसीआई बैंक के सभी ग्राहकों को ये सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस आई कार्ड का प्रयोग कर आपसे भुगतान मांगता है तो वह अनाधिकृत होगा।

कृपया ये सुनिश्चित करें कि अगर कोई भी व्यक्ति इस आई कार्ड धारक को किसी भी प्रकार का भुगतान करता है तो वो अपने जोखिम पर करेगा तथा इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगा।

तिथि:01.02.2023 हस्ता. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
स्थान:दिल्ली Plot No.7, Community Centre, SD Tower Sector-8, Rohini, New Delhi-110085

PUBLIC NOTICE

To, be known to all that my client, **SMT. RAJ DHAWAN W/O SHRI MANMOHAN DHAWAN R/O FLAT NO.AN-51-C, SECOND FLOOR, SHALIMAR BAGH, DELHI-110088, is the owner of DDA MIG FLAT NO. 51-C, ON SECOND FLOOR, BLOCK-AN, SITUATED AT SHALIMAR BAGH, DELHI-110088, VIDE DDA FILE NO.M/15(278) 1981/GEN/SB, have applied for Conversion of leasehold from freehold of the aforesaid property in DDA. The original documents i.e. Original DEMAND LETTER, POSESSION LETTER, SITE POSSESSION SLIP and NOC FOR WATER & ELECTRICITY CONNECTION** of the above **said property** have been lost or misplaced by our client and is not traceable inspite of his best efforts. An F.I.R./NCR to this effect has been lodged in the Police Station, Crime Branch, Delhi (**LR No.**96392/2023) dated **30.01.2023**. Any person(s) claiming any rights, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No.. within **15 days** from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director (Housing) or Director (Housing), Vikas Sadan, New Delhi.
Naveen Aggarwal (Advocate)
Ch.No. M-7, Near SBI, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-54

सार्वजनिक सूचना

सर्वप्रिय महाजन कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड,202,वर्धमान एवन शॉपिंग प्लाजा,एल.एस.सी, सी-ब्लाक मार्केट,सरस्वती विहार,पीतमपुरा,दिल्ली-110034

डी.सी.एस. नियम 2007 के नियम 19(2) का अनुसरण करते हुए जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वप्रिय महाजन सी.जी.एच.एस. लिमिटेड (पंजि न० 1384) के निम्न सदस्य ने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है

1. श्री स्वतंत्र कुमार पारीक (सदस्य सं. 556) इनको इनकी सभी जमा राशी RTGS द्वारा लौटा दी गयी हैं,यदि किसी को भी कोई आपत्ति हो तो आर.सी.एस, संसद मार्ग, नई दिल्ली या सोसायटी आफिस 202,वर्धमान एवन शॉपिंग प्लाजा,एल.एस.सी, सी-ब्लाक मार्केट,सरस्वती विहार,पीतमपुरा,दिल्ली-110034 में इस नोटिस के छपने के 7 दिन के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कराए।

सचिव-सर्वप्रिय महाजन सी.जी.एच.एस लिमिटेड

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of **Mrs. Meenakshi** who is/are purchasing the Built Up Third Floor of Property bearing No. IV/520-523, area measuring 44 Sq. Yds., situated in the area of Village Chandrawali @ Shahdara, colony known as Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi; from Mr. Manoj Gulati and Mr. Jitender Gulati, who are owners/beneficiaries of the aforesaid property vide WILL dated 06.09.2011 registered on 07.09.2011, which was executed by their mother Mrs. Asha Rani Gulati and who was owner of the aforesaid property vide Relinquishment Deed dated 09.02.2010, which was registered vide Document No.2076, registered with the office of the Sub-Registrar-VIII, Delhi, on 09.02.2010; and intend to mortgage the same against the financial assistance from **Shubham Housing Development Finance Company Limited.** That, **1)** Surviving Member Certificate (SMC) of Late Mr. Sardari Lal Gulati & **2)** Probate Order (of WILL dated 06.09.2011 registered on 07.09.2011); are/is not available. To comply the requirements of BANK/NBFC, we give this public notice that if any person(s) having any objection regarding ownership and/ or creating mortgage of the said property is/are hereby requested to intimate in writing to the undersigned within 15 days at below address.
Lucem Legal LLP
Plot no.136, (Basement) Uday Park, New Delhi-110049; Contact # 011-40046316

नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन व अन्य नेता बजट सत्र के दौरान बजट बक्सा दिखाते हुए।

बजट को रियल एस्टेट ने सराहा

नई दिल्ली। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी करने वाले आम बजट को रियल्टी उद्योग की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। रियल्टी उद्योग का कहना है कि यह बजट आर्थिक वृद्धि को गति देगा और वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करने में मददगार होगा। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के वाइस चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया है। इस बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं जिनमें बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना शामिल है।

रियल एस्टेट क्षेत्र के निकाय क्रेडाई के अध्यक्ष (एनसीआर) और गौड़ समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ ने कहा, बजट 2023-24 विकासोन्मुखी है। इससे बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से बचाने में मददगार होगा। यह बजट राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, अनुपालन बोझ को कम करने पर केंद्रित है। कारोबारी सुगमता को बेहतर करने के लिए 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का कदम सराहनीय है।

आम बजट को रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए अच्छा बताते हुए एसकेए समूह के निदेशक संजय शर्मा ने कहा, बजट में समग्र विकास करने वाले कारकों पर जोर दिया गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय को 10 लाख करोड़ रुपए करना शामिल है। शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से रियल एस्टेट क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा, वहीं सात लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट की घोषणा रियल एस्टेट के लिए वरदान साबित हो सकती है क्योंकि इससे मध्यम वर्ग में मांग बढ़ेगी। सीआरसी समूह के निदेशक (विपणन एवं व्यवसाय प्रबंधन) सलिल कुमार ने कहा, सरकार ने इस बजट में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की जो व्यवस्था की है उससे व्यवस्थित विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ आवासीय और वाणिज्यिक दोनों ही क्षेत्रों को मिलेगा।

रहेजा डेवलपर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन एम रहेजा ने कहा, पीएम आवास योजना कोष में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च में वृद्धि के साथ, यह बजट आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा देने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे देश में रियल एस्टेट का योजनाबद्ध विकास होगा, शहरी जीवनस्तर में भी सुधार होगा और डेवलपर को बेहतर घर प्रदान करने का अवसर मिलेगा। क्रेडाई (पश्चिमी यू.पी.) के अध्यक्ष एवं काउंटी समूह के निदेशक अमित मोदी ने कहा, कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया, जो इस साल के बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रियल एस्टेट को इसका लाभ मिलेगा।

सीमा शुल्क दरों में बदलाव से निर्यात को मिलेगा प्रोत्साहनः गोयल

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बुधवार को पेश बजट में कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क दरों में बदलाव किए जाने से देश का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। गोयल ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात सम्मिलित रूप से करीब 14-15 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। स्वीकार किया कि मौजूदा आर्थिक हालात में विदेशों में वस्तुओं की मौजूदगी अधिक रहने और मुद्रास्फीति की वजह से वस्तु निर्यात थोड़ा कम रह सकता है। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के बाद अगले वित्त वर्ष में वस्तु निर्यात के मामले में भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई। वित्त मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लिए बजट आवंटन करने में सहृदय रही हैं। ऐसे में मुझे यकीन है कि इससे हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ उत्पादों के आयात पर शुल्क की दर में बदलाव के प्रस्तावों पर गोयल ने कहा कि वित्त मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी से शुल्क को ऊपर-नीचे किया है।

सरकार का अडाणी मुद्दे पर टिप्पणी से इनकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडाणी समूह पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर कोई टिप्पणी करने से बुधवार को इनकार कर दिया। अडाणी समूह को 90 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बजट के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हम सरकार में हैं और किसी निजी कंपनी से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने भी मंगलवार को इस संबंध में बयान देने से इनकार कर दिया था।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of **Mrs. Meenakshi** who is/are purchasing the Built Up Third Floor of Property bearing No. IV/520-523, area measuring 44 Sq. Yds., situated in the area of Village Chandrawali @ Shahdara, colony known as Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi; from Mr. Manoj Gulati and Mr. Jitender Gulati, who are owners/beneficiaries of the aforesaid property vide WILL dated 06.09.2011 registered on 07.09.2011, which was executed by their mother Mrs. Asha Rani Gulati and who was owner of the aforesaid property vide Relinquishment Deed dated 09.02.2010, which was registered vide Document No.2076, registered with the office of the Sub-Registrar-VIII, Delhi, on 09.02.2010; and intend to mortgage the same against the financial assistance from **Shubham Housing Development Finance Company Limited.** That, **1)** Surviving Member Certificate (SMC) of Late Mr. Sardari Lal Gulati & **2)** Probate Order (of WILL dated 06.09.2011 registered on 07.09.2011); are/is not available. To comply the requirements of BANK/NBFC, we give this public notice that if any person(s) having any objection regarding ownership and/ or creating mortgage of the said property is/are hereby requested to intimate in writing to the undersigned within 15 days at below address.
Lucem Legal LLP
Plot no.136, (Basement) Uday Park, New Delhi-110049; Contact # 011-40046316

वाहन उद्योग ने विकासोन्मुख बताया

नई दिल्ली। वाहन उद्योग ने बुधवार को पेश आम बजट 2023-24 को विकासोन्मुख बताते हुए कहा है कि प्रस्तावित कदमों से तेज गति से स्थाई लेकिन समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। वाहन उद्योग की संस्था भारतीय वाहन विनिर्माता सोसायटी के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा कि 13.7 लाख करोड़ रुपए के प्रभावी प्रस्ताव के साथ पूंजी परिव्यय में 33 प्रतिशत वृद्धि से अर्थव्यवस्था वृद्धि को गति मिलेगी, जिससे घरेलू वाहन उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ के अध्यक्ष संजय जे कपूर ने कहा कि यह बजट डिजिटल रूप से सक्षम आत्मनिर्भर भारत का खाका है, जिसमें ऐसे कदमों का समावेश किया गया है, जो अर्थव्यवस्था को तेज गति से स्थाई लेकिन समावेशी वृद्धि प्रदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा, निर्यात, विनिर्माण, स्थानीय मूल्यवर्द्धन पर केंद्रित और हरित ऊर्जा और परिवहन को बढ़ावा देने वाले कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत आयकर के प्रस्तावों से लोगों के हाथ में और ज्यादा पैसा आएगा, जिससे खपत बढ़ेगी और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

वाहन डीलरों के संगठन फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि अवसंरचना व्यय में 10 लाख करोड़ की पूंजी परिव्यय से वाहन बिक्री को मदद मिलेगी। इसके अलावा व्यक्तिगत कर स्लैब में कटौती से दोपहिया और यात्री वाहन उद्योग को लाभ होगा। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता सोसायटी के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन कलपुर्जों की कमी के मुश्किल दौर से निकलने के बाद स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला ने आकार लेना शुरू कर दिया है। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा कि सरकार वर्षों से अवसंरचना निर्माण पर व्यय बढ़ाकर कारोबारी सुगमता बढ़ाने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि अगले साल चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट होने के बावजूद सरकार लोकलुभावन वादों से दूर रही और विकासोन्मुख बजट पेश किया। टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने इस बजट को बेहतर तरीके से तैयार दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा, अवसंरचना पर बढ़ते व्यय पर जोर और लीथियन आयन बैटरी विनिर्माण को सहयोग से इस उद्योग को बहुत लाभ होगा।

कटौती, छूट 3.75 लाख से कम होने पर नई व्यवस्था फायदेमंद

नई दिल्ली। किसी करदाता का अगर सालाना कटौती और छूट दावा 3.75 लाख रुपए से कम है तो उसे नई कर व्यवस्था अपनाने से लाभ होगा और उसे पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले कम कर का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि आयकर विभाग करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने को लेकर सरल और कम कर दर वाली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे आकलन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश करते कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लाभ के लिए नई कर व्यवस्था के ढांचे में बदलाव के साथ करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाया है।

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, Vandana Singh W/o Manoj Kumar R/o N-627, Sector -25, Jalvayu Vihar Noida. (U.P) I have changed my name Bandana Singh to Vandana Singh all future purposes.

PD(90257)C

नई दिल्ली में लोकसभा में बजट सत्र में उपस्थित सोनिया गांधी राहुल गांधी व अन्य सांसद।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार
Website: http://pwd.uk.gov.in Fax/Phone No.: 01334-221407 E-mail: sepwdharidwar@gmail.com

पत्रांक–347/06सी0–सि0वृ0–/22 दिनांक 01/02/2023

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा
ई–प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.)

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि, हरिद्वार द्वारा निम्न कार्य हेतु ई–आर0एफ0पी0 गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (QCBS) के आधार पर आमंत्रित की जाती है। आर0एफ0पी0 (RFP) सम्बन्धित सभी सूचना **http://www.uktenders.gov.in** पर दिनांक **07.02.2023** से उपलब्ध होगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा की वैधता (दिन में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की समय (माह में)	कंसलटेन्टसी फर्म की पात्रता
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला हरिद्वार में विभिन्न राज्य राजमार्गो के उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व, भूमि नियंत्रण अधिनियम की आवश्यकता के आधार पर सर्वेक्षण करने एवं लैण्ड प्लान तैयार करने हेतु इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति	2.10	120	5000.00 + 18% GST	06	NH/NHAI/PSU/ राज्य सरकार के अधीन समान प्रकृति के विस्तृत सर्वेक्षण कार्य का अनुभव

नोट :– निविदादाता को निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं निर्धारित समय से पूर्व निम्नलिखित अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मूल में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिसके प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. निविदा प्रपत्र की लागत कॉलम 4 के अनुसार का डिमांड बैंक ड्राफ्ट, जो कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार के नाम देय हो। ₹ 5000.00 एवं GST ₹ 900.00 दोनों बैंक ड्राफ्ट अलग–अलग दिये जायें।
2. निविदा की वैधता हेतु अन्डरटेकिंग जो रू0 100.00 मात्र का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर ₹ 1.00 के रैवेन्यू स्टाम्प पर हस्ताक्षर सहित 120 दिन वैधता की अवधि इंगित करते हुये प्रमाण पत्र।
3. निर्धारित धरोहर धनराशि, जो कि अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो०नि०वि०, हरिद्वार के नाम बन्धक हो।
4. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
सिविल वृत्त, लो०नि०वि०, हरिद्वार

अमेरिकी उप रक्षामंत्री कैथलीन हिक्स ने एनएसए अजीत डोभाल से कहा

गठबंधन और साझेदारी सर्वोच्च प्राथमिकता

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी रणनीतिक माहौल और चीन के आक्रामक व्यवहार के बीच अहम मुलाकात

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका की उप रक्षा मंत्री डॉ. कैथलीन हिक्स ने यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल से मुलाकात में कहा कि उनके विभाग के लिए गठबंधन और साझेदारी का निर्माण करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी।हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी रणनीतिक माहौल और चीन के आक्रामक व्यवहार के बीच यह मुलाकात हुई। पेंटागन ने मंगलवार को कहा कि हिक्स ने यहां डोभाल के साथ बैठक के दौरान अमेरिका-भारत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पेंटागन के अनुसार, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नीतियों व उनके संचालन में समन्वय को गहरा करने और दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय दूतावास ने मंगलवार को ट्वीट किया, दोनों ने अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। पेंटागन के प्रवक्ता एरिक पाहोन ने बैठक के बाद एक बयान में कहा कि हिक्स ने दोहराया कि गठबंधन बनाना तथा साझेदारी करना उनके मंत्रालय की पहली प्राथमिकता है और अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का अभिन्न अंग भी है। पाहोन ने बताया कि उन्होंने (हिक्स ने) क्षेत्र में भारत के नेतृत्व के लिए डोभाल का शुक्रिया अदा किया और साथ ही अमेरिका तथा भारतीय सेनाओं के बीच समन्वय को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की ताकि क्षेत्र के तेजी से बढ़ते विवादित रणनीतिक माहौल से निपटा जा सके। उन्होंने कहा, दोनों ने अमेरिका और भारतीय कंपनियों के बीच अभिनव संयुक्त प्रयासों के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की जो भारत की विशिष्ट संचालन की जरूरतों के अनुरूप है। बैठक के रीडआउट (जानकारी) के अनुसार, हिक्स और डोभाल ने कहा कि वे अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए तत्पर हैं।

भारत, अमेरिका ने आईसीईटी की पहली बैठक की : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यहां अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के साथ मिलकर इनीशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (आईसीईटी) की पहली उच्च-स्तरीय बैठक की। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी।हाइट हाउस ने मंगलवार को डोभाल और सुलिवन के बीच आईसीईटी की पहली बैठक के समापन के बाद एक फैक्ट शीट (तथ्यात्मक जानकारी) में कहा, हम आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित एक मुक्त, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा। मई 2022 में तोक्यो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच बैठक के बाद पहली बार एक संयुक्त बयान में आईसीईटी का उल्लेख किया गया था। इसका मकसद दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना व विस्तारित करना है। व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका और भारत इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रौद्योगिकी को डिज़ाइन, विकसित, शासित और उपयोग करने के तरीकों में हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सार्वभौमिक मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। हम आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित एक मुक्त, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा। डोभाल और सुलिवन ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के प्रशासक, नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक, नेशनल स्पेस काउंसिल के कार्यकारी सचिव और विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका समूह की बैठक

वाशिंगटन। द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए भारत और अमेरिका के शीर्ष अंतरिक्ष अधिकारियों ने यहां मुलाकात की।अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने एक ट्वीट में कहा, भारत और अमेरिका द्विपक्षीय अंतरिक्ष साझेदारी को उच्च कक्षाओं (ऑर्बिट) में ले जाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैउ उनकी टिप्पणी मंगलवार को विदेश विभाग के फेडरल बॉटम मुख्यालय में नासा के प्रशासक बिल नेल्सन और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के साथ भारत-अमेरिका सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (सीएसजेडब्ल्यूजी) को संबोधित करने के बाद आई है। सीएसजेडब्ल्यूजी की आठवीं बैठक 30-31 जनवरी के बीच हुई।

भारत, अमेरिका प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में करीबी सहयोग के लिए तैयार

वाशिंगटन। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन द्वारा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (आईसीईटी) पर भारत-अमेरिका पहल की शुरुआत एक महत्वपूर्ण संकेत है कि दोनों देश बाधाओं को तोड़ने, प्रौद्योगिकी में संबंधों को बढ़ावा देने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और सुलिवन ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में अपने संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडलों के साथ पहले आईसीईटी संवाद के लिए मुलाकात की। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में हिंद-प्रशांत सुरक्षा कार्यक्रम की वरिष्ठ फेलो और निदेशक लीज़ा कर्टिस ने पीटीआई-भाषा को बताया, भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच पहली आईसीईटी बैठक का आयोजन संबंधों के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है और यह संकेत देता है कि दोनों पक्ष निकट प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के वास्ते बाधाओं को तोड़ने के लिए तैयार है।

मोदी को बाइडेन ने किया आमंत्रित

जी 20 बैठक से पहले जून में जा सकते हैं यूएस, अमेरिकी संसद में भाषण भी देंगे

भाषा। **वाशिंगटन**

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक माना जा रहा है कि बाइडन ने मोदी को देश की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। सूत्रों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इस निमंत्रण को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है और दोनों पक्षों के अधिकारी अब पारस्परिक रूप से यात्रा की संभावित तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अभी योजना पर चर्चा प्रारंभिक चरण में हैं।

भारत इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत इस साल जी-20 से संबंधित कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर रहा है, जिसके तहत सितंबर में एक शिखर सम्मेलन होगा जिसमें अन्य लोगों के साथ बाइडन की हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के अधिकारी जून और जुलाई में उपयुक्त तारीखों की तलाश कर रहे हैं। उस समय न केवल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सत्र चल रहे होंगे, बल्कि तब प्रधानमंत्री मोदी के भी कोई पूर्व निर्धारित घरेलू या अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं हैं। यह राजकीय यात्रा कम से कम कुछ दिनों की होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रिभोज शामिल होने की संभावना है। जी-20 के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी को साल के उत्तरार्ध में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। साथ ही इस वर्ष के अंत में कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार का जिम्मा भी उनपर होगा। सूत्रों ने हालांकि यह जानकारी नहीं दी कि यह निमंत्रण कब दिया गया और बाइडन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को यह व्यक्तिगत निमंत्रण किसने दिया। बाइडन ने पिछले साल दिसंबर में अपने पहले राजकीय रात्रिभोज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां की मेजबानी की थी।

राजद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को जमानत दी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने राजद्रोह के एक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को बुधवार को जमानत दे दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी 52 वर्षीय चौधरी को पिछले सप्ताह लाहौर में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के सचिव की शिकायत पर इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। निर्वाचन आयोग के सचिव ने चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर आयोग के सदस्यों और उनके परिवारों को धमकी देने का आरोप लगाया था। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को मामले में उनकी हिरासत के लिए पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश फैजान गिलानी ने बुधवार को राजद्रोह के मामले में बीस हजार रुपए के मुचलके पर चौधरी को जमानत दे दी। चौधरी पर निर्वाचन आयोग के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से धमकाने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर उनकी रिहाई की मांग की थी।

रूसी सेना का ध्यान पूर्वी यूक्रेन पर, नए सिरे से हमले की आशंका

कीव। रूस, यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यूक्रेन इसे आने वाले सप्ताहों में रूस का हमला शुरू होने के एक साल पूरा होने के मौके पर पूर्वी क्षेत्र में हमले की तैयारी के रूप में देख हा है। लुहांस्क के गवर्नर सेरही हैदई ने कहा कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले हिस्सों के पास घरों से स्थानीय लोगों को निकाल रही है ताकि वे यूक्रेन के आयुध भंडारों में रूसी सैनिकों की तैनाती के बारे में सूचना नहीं दे सकें। हैदई ने कहा, इस क्षेत्र में रूसी सैनिकों को सक्रियता के साथ भेजा जा रहा है और वे निश्चित रूप से फरवरी में पूर्वी भाग में किसी बड़ी तैयारी के साथ जा रहे हैं। आगामी 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमलों की शुरुआत को एक साल पूरा हो जाएगा।

पोप ने कॉन्गो और दक्षिण सूडान की छह दिवसीय यात्रा शुरू की

किंशासा (कॉन्गो)। पोप फ्रांसिस ने मंगलवार को अफ्रीकी देश कॉन्गो और दक्षिण सुडान की छह दिवसीय यात्रा शुरू की। पोप की इस यात्रा का मकसद इन दो देशों को शांति का संदेश देना है जो गरीबी व संघर्ष से जूझते रहे हैं। पोप के अनुसार ए देशैं उपनिवेशवादी मानसिकतौ का भी सामना कर रहे हैं। सहायता समूह उम्मीद कर रहे हैं कि फ्रांसिस की यात्रा दुनिया के इन दो संघर्षों पर प्रकाश डालेगी और अफ्रीका के सबसे खराब मानवीय संकटों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करेगी। पोप ने पिछले हफ्ते एसोसिएटिड प्रेस से कहा था, जी हां अफ्रीका में उथल-पुथल है और वह शोषकों के हमलों से जूझ रहा है। उनकी कॉन्गो की यात्रा पिछले साल जुलाई में होनी थी लेकिन उनकी घुटनों की तकलीफ की वजह से इसे टाल दिया गया था। वह कॉन्गो से दक्षिण सुडान जाएंगे।

पश्चिमी आस्ट्रेलिया में ट्रक से गिरा रेडियोधर्मी कैप्सूल खोजा गया

पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अधिकारियों ने बुधवार को उस छोटे खतरनाक रेडियोधर्मी कैप्सूल को तलाश लिया जो पिछले माह इस।,400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर ढुलाई के दौरान ट्रक से गिर गया था। अधिकारी ने कहा कि उक्त कैप्सूल को ढूंढना भूसे के ढेर से एक सूई खोजने जैसा था। अधिकारियों ने बताया कि मटर के आकार का यह कैप्सूल न्यूमैन के दक्षिण में ग्रेट नॉर्दर्न हाईवे पर मिला। अधिकारियों ने बताया कि इसका पता 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे एक खोजी वाहन द्वारा लगाया गया जब विशेषज्ञ उपकरण ने कैप्सूल से निकलने वाले विकिरण से इसकी पहचान की। आपातकालीन सेवा मंत्री स्टीफन डॉसन ने कहा, यह एक असाधारण परिणाम है ... उन्होंने वास्तव में भूसे के ढेर में सुई ढूंढ ली है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी एंडी रॉबर्टसन ने कहा कि कैप्सूल से किसी को किसी तरह की क्षति पहुंचने की सूचना नहीं है।

भारतीय अमेरिकी निक्की हेली बन सकती हैं कैंडिडेट

यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2024: ट्रम्प से जीतनी होगी बाजी

भाषा। वाशिंगटन

भारतीय मूल की अमेरिकी और रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की अपनी योजना की औपचारिक घोषणा 15 फरवरी को कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती पेश करने वाली पार्टी की पहली नेता होंगी। हेली (51) दो बार दक्षिण कैरोलाइना की गवर्नर रह चुकी हैं और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। अगर वह इस पद के लिए दावेदारी करती हैं तो हेली अपने पूर्व बॉस (ट्रंप) के खिलाफ मुकाबले में उतरने वाली पहली दावेदार होंगी। ट्रंप वर्तमान में अपनी पार्टी की तरफ से 2024 में राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए दावेदारी करने वाले एकमात्र रिपब्लिकन हैं। ट्रंप (76) ने पिछले साल व्हाइट हाउस के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, हेली इस हफ्ते जल्द से जल्द अपनी योजनाओं का संकेत देने वाला एक वीडियो जारी कर सकती हैं। द पोस्ट एंड कूरियर की खबर के मुताबिक पूर्व गवर्नर के समर्थकों को जल्द ही हेली की 15 फरवरी को होने वाली विशेष घोषणा का उल्लेख किए जाने से संबंधित एक निमंत्रण पत्र मिल सकता है। यह कार्यक्रम चार्ल्सटन विजिटर सेंटर के द शेड में होगा जिसमें उनके सैकड़ों समर्थकों के जुटने की संभावना है। दक्षिण कैरोलाइना स्थित एक दैनिक द चार्ल्सटन ने खबर दी, 31 जनवरी को हेली के करीबियों से इस बात की पुष्टि हुई कि वह इस दौड़ में शामिल हो रही हैं। हेली की पूर्व में कही गई यह बात काफी चर्चित रही थी कि अगर वह (ट्रंप) फिर से चुनाव लड़ेंगे तो वह उन्हें चुनौती नहीं देना चाहेंगी लेकिन हाल के दिनों में उनके रुख में बदलाव आया है क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक अलग दिशा की ओर देखने की जरूरत है।

एफबीआई ने बाइडन के घर की तलाशी ली

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी वकील ने कहा कि एफबीआई ने गोपनीय दस्तावेजों से संबंधित अपनी जांच के तहत बुधवार को जो. बाइडन के रेहोबोथ बीच, डेलवेयर स्थित घर की तलाशी ली। यह तलाशी 20 जनवरी को उनके विलमिंगटन, डेलवेयर आवास की 13 घंटे तक हुई छानबीन के बाद ली गई। पहले की तलाशी में राष्ट्रपति के आवास से कुछ अतिरिक्त गोपनीय दस्तावेज मिले थे। बाइडन के वकील बॉब बौएर ने कहा कि राष्ट्रपति ने जांच के तहत स्वेच्छा से न्याय विभाग को अपने आवासों की तलाशी लेने को कहा है। बाइडन के आवास और कार्यालय से कई गोपनीय दस्तावेज मिले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यह उस समय के हैं जब बाइडन उपराष्ट्रपति थे।

इमरान खान को आखिरी मौका : इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने प्रतिबंधित निधि मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान के वीडियो लिंक के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें 15 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आखिरी मौका दिया।

चीन हमले की तैयारी में ताइवान भी हुआ सचेत

सैन्य विमान और युद्धपोत की तैनाती के बीच ताइवान ने अपनी प्रतिरक्षा को सक्रिय किया

एजेंसी। ताइपे

ताइवान ने चीन के 34 सैन्य विमानों और नौ युद्धपोतों की तैनाती के बीच अपने लड़ाकू विमानों को उतारते हुए अपनी नौसेना को सचेत किया और मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर दिया। यह तैनाती ऐसे वक्त हुई है जब चीन ने ताइवान के खिलाफ संभावित नाकाबंदी या हमले की तैयारी बढ़ाई है, जिससे ताइवान के प्रमुख सहयोगी अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पिछले महीने एक पत्र में अमेरिकी वायु सेना के जनरल माइक मिनिहान ने अधिकारियों को 2025 में ताइवान को लेकर अमेरिका-चीन संघर्ष के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। एयर मोबिलिटी कमान के प्रमुख के रूप में, मिनिहान को चीनी सेना की गहरी समझ है और उनकी टिप्पणियां अमेरिका द्वारा तैयारी बढ़ाने के आह्वान के अनुरूप हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 20 चीनी विमानों ने मंगलवार को ताइवान जलडमरूमध्य में सेंट्रल लाइन को पार किया जो लंबे समय से अनौपचारिक बफर जोन रहा है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ताइवान के अधिकतर लोग चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में आने का विरोध करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ताइवान के सशस्त्र बलों ने इन गतिविधियों का जवाब देने के लिए स्थिति की निगरानी की। चीन ने लगभग दैनिक आधार पर ताइवान के पास हवाई क्षेत्र में युद्धपोत, बमवर्षक, लड़ाकू विमान भेजे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तत्कालीन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और यूरोपीय संघ के कई नेताओं के हाल के महीनों में ताइवान के दौरे के बीच दोनों पक्षों ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। पिछले साल अगस्त में पेलोसी की यात्रा पर आपत्ति जताते हुए चीन ने ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास किया था और मिसाइल दागी थी। ताइवान से करीबी संबंध रखने वाले देशों के खिलाफ चीन ने बदले की कार्वाई की चेतावनी दी है।

ब्रिटेन में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षकों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल: लंदन, । ब्रिटेन में बुधवार को शिक्षक, विश्वविद्यालय के व्याख्याता, ट्रेन और बस चालक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। देश में लगभग एक दशक में इस तरह की स्थिति पहली बार उत्पन्न हुई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के आधिकारिक प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि इस सामूहिक हड़ताल से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इंग्लैंड और वेल्स में शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया है, जिससे 23,000 स्कूल प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 85 प्रतिशत स्कूलों के पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहने का अनुमान जताया गया है। शिक्षा मंत्री गिलियन कीगन ने कहा, मैं इस बात से निराश हूं कि कर्मचारी संघों ने इस तरह का निर्णय लिया है।

पेशावर मस्जिद हमले में 17 संदिग्ध गिरफ्तार

पेशावर/इस्लामाबाद (भाषा)

पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने पेशावर में एक उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में स्थित मस्जिद में हुए आत्मघाती विस्फोट के सिलसिले में 17 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने आतंकवादी समूहों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने का संकल्प व्यक्त किया और सेना के अधिकारियों को आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का निर्देश दिया। पेशावर में हुए इस हमले में 97 पुलिसकर्मियों समेत 101 लोग मारे गए हैं। सोमवार को दोपहर की नमाज के दौरान आगे की कतार में मौजूद तालिबान के आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में पिछले कई सालों में सुरक्षाकर्मियों पर हुए इस सबसे भयावह हमले में शामिल होने के संदेह में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया कि पुलिस लाइन्स इलाके के नजदीकी क्षेत्रों से गिरफ्तारियां की गई हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक बयान में कहा कि आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पुलिस को अग्रिम मोर्चे का बल करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें और मजबूत किया जाएगा और आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या पाकिस्तानी तालिबान ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उनके कथित कमांडर उमर खालिद खुरासानी की पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में हुई मौत का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया।

यूक्रेनः हालात के साथ महिलाओं के प्रति बदल रहा है दृष्टिकोण

हजारों महिलाएं संभाल रहीं सेना में मोर्चा

एजेंसी। एब्रिस्विथ

(द कन्वरसेशन) क्रीमिया तथा पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों पर 2014 में रूस द्वारा कब्जा करने की शुरूआत के बाद से यूक्रेन की सेना में हजारों महिलाएं स्वेच्छा से शामिल हुई हैं। पिछले नौ साल से अधिक समय में यूक्रेन की सेना में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूरी ताकत के साथ हमला किए जाने के बाद यूक्रेन की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के बीच एक लहर चल पड़ी है। ऐसे तो सोवियत संघ से 1991 में आजाद होने के बाद से ही यूक्रेन के सशस्त्र बल में महिलाएं अपनी सेवा दे रही हैं, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका 2014 की लड़ाई की के बाद से शुरू हुई। महिलाओं ने 2016 में लड़ाकू भूमिकाओं में काम करना शुरू किया और 2022 में सभी सैन्य भूमिकाओं को महिलाओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि, गैर-लड़ाकू भूमिका में शामिल कई महिलाएं, जैसे कि मेडिक्स, भी संघर्षरत और युद्ध के मोर्चे पर डटे अपने पुरुष और महिला सहयोगियों के समान ही खतरों और कठिनाइयों में हैं।यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हन्ना मलियार के अनुसार, 2022 की गर्मियों तक 50 हजार से अधिक महिलाओं को सेना में विभिन्न भूमिकाओं में लिया गया है, इनमें से करीब 38 हजार महिलाएं वर्दीधारी हैं। उनके अनुसार महिलाएं अब अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में भी शामिल हैं।

सशस्त्र बलों में शामिल महिलाओं को रूसियों द्वारा युद्धबंदी बनाया जा रहा है। यूक्रेनी मेडिक्स यूलिया पेवेस्का को तीन महीने की कैद हुई थी। पेवेस्का ने बताया, हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वह बेहद कठिन और कठोर था। पितृसत्तात्मक सोच बदल रही है- यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां, पितृसत्तात्मक परंपरा बेहद मजबूत है, खास तौर से रक्षा क्षेत्र में। लेकिन यूक्रेन की महिला सैनिकों को यूक्रेन का समाज और देश का राजनीतिक नेतृत्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर स्वीकार कर रहे हैं। सेना और समाज में महिलाओं की उपस्थिति को पहचान का एक संकेत तब मिला जब 2021 में नेशनल डिफेंडर्स डे का नाम बदल कर डे ऑफ मेन एंड वूमन डिफेंडर्स ऑफ यूक्रेन कर दिया गया।

रक्षा मंत्रालय अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महिला सैनिकों की तस्वीर अब नियमित तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की महिला सैनिक भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और वह अपने सैन्य अनुभव के बारे में बातचीत करती रहती हैं।

भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर जीती श्रृंखला

शुभमन गिल का टी20 में पहला शतक

भाषा। अहमदाबाद

अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के विरुद्ध शतक लगाने के बाद उत्साहित शुभमन गिल

भारत ने शुभमन गिल के टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहले (नाबाद 126 रन) शतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बुधवार को यहां तीसरे और अंतिम मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर रनों के हिसाब से इस प्रारूप में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। भारत ने इससे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत आयरलैंड के खिलाफ (143 रन से) 2018 में डबलिन में हासिल की थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के दो पूर्णकालिक देशों के बीच रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। गिल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को चारों ओर पीटते हुए अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी।

उन्होंने महज 63 गेंद में 12 चौके और सात छक्के जमाए जिससे भारत ने चार विकेट पर 234 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। गिल का भारतीय बल्लेबाजों में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे बड़ा स्कोर भी है। गिल ने इस मामले में पूर्व कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ा। कोहली ने पिछले साल अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 रन की पारी खेली थी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में 66 रन ही बना सकी। उसके लिए डेरिल मिचेल 35 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। केवल एक अन्य बल्लेबाज मिचेल सैंटनर (13 रन) ही दोहरे अंक तक पहुंच सके।

भारत के लिए कप्तान और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (16 रन देकर चार विकेट) ने अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। उनके अलावा अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक और शिवम मावी ने दो दो विकेट झटके। गेंदबाजों का क्षेत्ररक्षकों ने भी पूरा साथ दिया और कैच करने के किसी भी मौके को बर्बाद नहीं किया जिसमें सूर्यकुमार यादव ने तीन कैच लपके। न्यूजीलैंड को शुरुआती झटका पहले ही ओवर में लगा जब सलामी बल्लेबाज फिन एलेन भारतीय कप्तान हार्दिक की गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने शानदार कैच लपक लिया। अर्शदीप सिंह ने दूसरे ओवर में डेवोन कॉनवे और मार्क चैपमैन को आउट कर न्यूजीलैंड को दो झटके दे दिए जिससे उसका स्कोर तीन विकेट पर पांच रन था। अब टीम की उम्मीदें ग्लेन फिलिप्स (02 रन) पर लगी थीं लेकिन वह भी टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके और तीसरे ओवर में हार्दिक का दूसरा शिकार हुए।

उमरान मलिक ने अपने पहले ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल (08) को बोल्ड कर दिया जिससे पांचवें ओवर में 21 रन पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। शिवम मावी के पहले ही ओवर में मिचेल सैंटनर (13) और ईश सोढ़ी को चलता किया। फिर हार्दिक ने लॉकी फर्ग्यूसन और ब्लेयर टिकनर को आउट कर अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। उमरान मलिक के ब्रेसवेल को आउट करते ही भारतीय टीम ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत इतनी अच्छी नहीं रही और मिचेल सैंटनर ने माइकल ब्रेसवेल को दूसरा ओवर देकर मास्टर स्ट्रोक खेला। इस ऑफ स्पिनर ने भी अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन को पगबाधा आउट कर दिया। फॉर्म में चल रहे गिल ने अगले ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन पर दो चौके जड़े। उन्होंने हिट, ड्राइव और पुल शॉट से दर्शकों के लिए मनोरंजन दोगुना कर दिया। गिल ने पांचवें ओवर में ब्लेयर टिकनर पर तीन चौके जड़े जिससे स्कोर एक विकेट पर 44 रन हो गया। युवा राहुल त्रिपाठी (22 गेंद में 44 रन) ने भी तेज लय जारी रखते हुए फर्ग्यूसन पर लगातार गेंदों पर एक चौके और एक छक्का लगाया। त्रिपाठी ने फिर सैंटनर पर शार्ट फाइन लेग पर चौका और सीधे एक छक्का जड़ा। वह आक्रामक दिख रहे थे और ईश सोढ़ी पर एक्स्ट्रा कवर पर अपनी पारी का तीसरा छक्का जड़ा। पर ऐसा ही बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर फर्ग्यूसन को कैच दे बैठे। गिल ने सैंटनर की गेंद पर एक रन बनाकर 35 गेंद में अपना पहला टी20 अर्धशतक जड़ा। गिल एक छोर पर डटे थे और सूर्यकुमार यादव (13 गेंद में 24 रन) उनके साथ क्रीज पर थे जिन्होंने भी तेजी से रन जोड़ने की लय बनाए रखी, पर 13वें ओवर में मिड ऑफ पर ब्रेसवेल को कैच देकर आउट हुए।

गिल ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर फर्ग्यूसन की गेंद पर मिड ऑफ में चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने स्वच्छंदता से बल्लेबाजी करते हुए इसी गेंदबाज की अगली गेंद को गगनदाई छक्के के लिए भेज दिया। कप्तान हार्दिक पंड्या (17 गेंद में 30 रन) ने भी रन गति को कम नहीं होने दिया। लेकिन गिल ने शतक के बाद अपनी आक्रामकता तेज कर दी और न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण लचर दिखाई दिया।

खेलों के लिए सरकार ने 700 करोड़ अधिक दिए

केंद्रीय बजट में 3,397.32 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया

भाषा। नई दिल्ली

इस साल होने वाले एशियाई खेलों और अगले साल के लिए प्रस्तावित पेरिस ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्रालय के लिए बुधवार को पेश केन्द्रीय बजट में 3,397.32 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जो पिछले साल के मुकाबले 723.97 करोड़ रुपए अधिक है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) के संशोधित बजट से अधिक है, जब मंत्रालय को 2,673.35 करोड़ रुपए मिले थे। पिछले साल हालांकि वास्तविक आवंटन 3,062.60 करोड़ रुपए था। साल 2022-23 के लिए संशोधित आवंटन में कटौती का एक मुख्य कारण चीन में प्रस्तावित एशियाई खेलों का स्थगन हो सकता है। इन खेलों का आयोजन इस साल होगा। मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम, खेलो इंडिया - खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है, इसे पिछले वित्त वर्ष के दौरान 606 करोड़ रुपए के संशोधित आवंटन के मुकाबले 1,045 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इसमें 439 करोड़ रुपए की वृद्धि कार्यक्रम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस आयोजन ने पिछले कुछ वर्षों में ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे प्रमुख वैश्विक आयोजनों के लिए एथलीट तैयार करने की क्षमता दिखाई है। खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन, शिविर का बुनियादी ढांचा और उपकरण प्रदान करने, प्रशिक्षकों की नियुक्ति और खेल के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए इस बजटीय आवंटन में 36.09 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष के संशोधित व्यय 749.43 करोड़ रुपए के मुकाबले साल 2023-24 के लिए उनका आवंटन 785.52 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को पिछले वर्ष के संशोधित बजट 280 करोड़ रुपए से 45 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ आवंटन प्राप्त हुआ है और अब उन्हें 325 करोड़ रुपए मिलेंगे।

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) से संबद्ध राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीएलटी) को पहले साइ के जरिए कोष मिलता था लेकिन अब ए संस्थाएं अपने रकम को सीधे प्राप्त करेगी। इस साल के बजट में नाडा को 21.73 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराने का प्रावधान है, जबकि डोप परीक्षण कराने वाले एनडीटीएल को 19.50 करोड़ रुपए मिलेंगे।

दुनिया भर के देश खेल उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर रहे हैं और खिलाड़ियों के खेल विज्ञान और वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में इस साल के बजट में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के लिए भी 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मध्यक्रम में अय्यर के स्थान के लिए गिल और सूर्यकुमार दावेदार

भाषा। नई दिल्ली

श्रेयस अय्यर के कमर की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट की श्रृंखला के पहले मैच से बाहर होने के बाद भारतीय टीम प्रबंधन मध्यक्रम में सूर्यकुमार यादव पर शुभमन गिल को तरजीह देते हुए उन्हें खिलाने पर विचार कर सकता है। अय्यर कमर में जकड़न से उबरने में नाकाम रहे हैं और उनके बाहर होने से भारतीय मध्यक्रम में एक स्थान बनेगा। इस स्थान के दावेदार सूर्यकुमार और

गिल हैं। सूर्यकुमार ने अपने करियर में मध्यक्रम में ही बल्लेबाजी की है जबकि गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अधिकतर राष्ट्रीय टीम के लिए पारी का आगाज किया है। अपने संक्षिप्त टेस्ट करियर में अब तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले अय्यर ने पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला में 2-0 की जीत के दौरान भी शानदार प्रदर्शन किया था।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, न्यूजीलैंड की टीम जब 2021 के अंत में भारत आई थी तो मध्यक्रम में शुभमन गिल के नाम पर विचार किया गया था क्योंकि लोकेश राहुल को मयंक अग्रवाल के साथ पारी का आगाज करना था। इसके बाद राहुल चोटिल हो गए और गिल ने पारी का आगाज किया। इसके बाद वह चोबारा चोटिल हो गया। लाल गेंद के क्रिकेट में मध्यक्रम के लिए उसके नाम पर विचार हुआ था। कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान राहुल टीम में सलामी जोड़ी के रूप में पहली पसंद हैं। इनके बाद तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा और चौथे नंबर पर विराट कोहली का खेलना तय है। पांचवां क्रम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उम्मीद की जाती है कि इस क्रम पर उतरने वाला बल्लेबाज दूसरी नई गेंद का सामना करेगा। गिल के मामले में टेस्ट क्रिकेट में नियमित रूप से खेलने और लाल गेंद का करियर मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में शुरू करने के कारण उनका पलड़ा भारी रहेगा। पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता ने कहा, जब भारत ए की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ के हाथों में थी तो गिल वेस्टइंडीज के ए दौरे पर मध्यक्रम में खेले थे जहां उन्होंने एक दोहरा शतक भी जड़ा था। असल में शुरुआत में वह मध्यक्रम का बल्लेबाज था जिसे सलामी बल्लेबाज में बदला गया। स्पिन की अनुकूल पिचों पर स्पिनरों के खिलाफ सूर्यकुमार का दबदबा महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर नाथन लियोन अपनी ऑफ स्पिन गेंदों को अधिक टर्न कराने में सफल रहते हैं तो सूर्यकुमार अपने फुटवर्क से उनकी लय बिगाड़ सकते हैं लेकिन पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के खिलाफ गिल बेहतर विकल्प हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू श्रृंखला से बाहर रहे अय्यर चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन करा रहे हैं।

सूर्यकुमार आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार

दुबई। भारत के आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बुधवार को जारी नवीनतम टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। रांची में न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में 47 रन की पारी की बदौलत उनके 910 रेटिंग अंक हो गए थे लेकिन श्रृंखला के दूसरे मैच में नाबाद 26 रन की पारी खेलने के बावजूद उनके अंकों की संख्या 908 रह गई। सूर्यकुमार पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक के इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान के रिकॉर्ड के भी काफी करीब हैं। मलान ने 2020 में केपटाउन में 915 अंक हासिल किए थे।

सूर्यकुमार टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों में सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल करने वालों की सर्वकालिक सूची में दूसरे स्थान पर हैं। पिछले साल टी20 विश्व कप में छह मैच में 239 रन जुटाकर सूर्यकुमार टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें पिछले महीने आईसीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर भी चुना गया। सूर्यकुमार के अलावा भारत का कोई अन्य बल्लेबाज या गेंदबाज शीर्ष 10 में शामिल नहीं है। ऑलराउंडर की सूची में हार्दिक पंड्या तीसरे स्थान पर हैं। मोहम्मद सिराज एकदिवसीय गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं।

सचिन ने विश्वकप विजेता टीम को सम्मानित किया

भाषा। अहमदाबाद

पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार आयोजित हुए अंडर-19 महिला आईसीसी टी20 विश्व कप की विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को सम्मानित करते कहा कि इस उपलब्धि से कई लड़कियां खेल को अपनाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।

तेंदुलकर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के इतर आयोजित इस सम्मान समारोह में कहा, मैं आपको शानदार उपलब्धि पर बधाई देना चाहता हूं। पूरा देश आने वाले वर्षों में (जीत का) जश्न मनाएगा। मास्टर ब्लास्टर ने कहा, मेरे क्रिकेट सपने की शुरुआत भारतीय टीम के 1983 में विश्व कप विजेता बनने से शुरू हुई थी। आपने भी कई नए सपनों को जन्म दिया है। यह शानदार उपलब्धि है। उन्होंने कहा, इस विश्व कप को जीतकर आपने भारत की युवा लड़कियों को देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना दिया है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक जड़ने वाले इस पूर्व दिग्गज ने कहा, डब्ल्यूपीएल (महिला प्रीमियर लीग) की शुरुआत सबसे बड़ी चीज होने जा रही है। मैं पुरुषों और महिलाओं के लिए समानता में विश्वास करता हूं। खेलों में ही नहीं बल्कि हर जगह दोनों के पास समान अवसर होना चाहिए।

तेंदुलकर ने कहा कि बीसीसीआई देश में महिला क्रिकेट के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, बीसीसीआई और उसके अधिकारियों ने महिला क्रिकेट को समृद्ध बनाने में काफी योगदान दिया है। मुझे लगता है कि यह एक संकेत है कि हम वास्तव में अच्छा करेंगे (भविष्य में)। इस संक्षिप्त सम्मान समारोह में बीसीसीआई सचिव जय शाह, अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और कोषाध्यक्ष आशीष शेलार भी शामिल थे। इस मौके पर विश्व चैम्पियन अंडर-19 महिला टीम को पांच करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया जिसकी घोषणा बोर्ड सचिव ने पहले की थी।

नफरत और दुर्व्यवहार के कारण पाकिस्तान टीम को कभी कोचिंग देने के बारे में नहीं सोचा: अकरम

भाषा। कराची

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि देश में कोच और कप्तान की आलोचना, दुर्व्यवहार और नफरत के कारण उन्होंने राष्ट्रीय टीम को कोचिंग देने के बारे में कभी नहीं सोचा। अकरम ने यहां एक साक्षात्कार में कहा, अगर टीम अच्छा नहीं कर रही है तो मैं आलोचना स्वीकार कर सकता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट में हालांकि जिस तरह से कप्तान और कोचों की न केवल आलोचना की जाती है बल्कि सभी के द्वारा गाली-गलौज भी किया जाता है, वह असहनीय है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के क्रिकेट में कप्तान और कोच को दुर्व्यवहार और कभी-कभी जिस नफरत का सामना करना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझमें सहनशीलता का वह स्तर नहीं है, खासकर जब सोशल मीडिया के उपयोग की बात आती है। कई ऐसे लोग है जिनका काम सिर्फ नकारात्मक टिप्पणियां करना है। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से बाबर आजम को कप्तान के पद से नहीं हटाने की मांग की इस पूर्व कप्तान ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक गलती होगी। क्योंकि अगर आप उन्हें किसी भी प्रारूप में कप्तान के रूप में बदलते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा, इस मामले में हमारे पास विकल्प क्या हैं? अगर हम सब समर्थन करें तो यह सबसे अच्छा विकल्प होगा। वह युवा है और कप्तान के तौर पर वह और बेहतर होगा। मेरी सोच है कि कोई भी जन्मजात कप्तान और नेता नहीं होता, ये चीजें समय और अनुभव के साथ आती हैं।

आंध्र ने बनाए 379 रन, मप्र के चार विकेट पर 144 रन

भाषा। इंदौर

रणजी ट्रॉफी

आंध्र के कप्तान हनुमा विहारी ने बाएं हाथ में चोट के बावजूद इसी से बल्लेबाजी करते हुए आवेश खान की तेज गेंदबाजी का डटकर सामना किया और बुधवार को यहां रणजी ट्राफी क्वार्टरफाइनल मैच के दूसरे दिन 10वें विकेट के लिए 26 रन जोड़कर मध्य प्रदेश के खिलाफ 379 रन बनाने में मदद की। आंध्र ने फिर गत चैम्पियन मध्य प्रदेश के स्टंप तक 144 रन तक चार विकेट झटककर मैच पर नियत्रंण बना लिया था। दो विकेट पर 262 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए आंध्र की टीम के लिए चीजें उसके अनुरूप नहीं रहीं और मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने रिकी भुई (149 रन) और करण शिंदे (110 रन) के बीच 251 रन की विशाल साझेदारी के दौरान जूझने के बाद वापसी की। शिंदे ने 254 रन गेंद में अपना शतक पूरा किया जबकि भुई ने घरेलू टीम के गेंदबाजी आक्रमण को हताश करना जारी रखा। मध्यम गति के गेंदबाज अनुभव अग्रवाल (72 रन देकर चार विकेट) ने इस भागीदारी का अंत किया। शिंदे इस गेंदबाज की गेंद पर बल्ला छुआकर विकेटकीपर हिमांशु मंत्री को कैच दे बैठे और इस समय टीम का स्कोर 323 रन था। पांच रन बाद भुई की मैराथन पारी अग्रवाल की गेंद पर सारांश जैन के कैच लेने से समाप्त हुई। मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने फिर लगातार अंतराल पर विकेट झटके और जब आंध्र का स्कोर नौ विकेट पर 353 रन था तब विहारी बल्लेबाजी के लिए उतरे। बाएं हाथ की कलाई चोटिल होने के बाद बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए आंध्र के कप्तान ने दो बाउंड्री लगाकर टीम को 379 रन तक पहुंचाया। उन्होंने केवल एक हाथ से बल्लेबाजी की। जैन ने उन्हें 27 रन के निजी स्कोर पर पगबाधा आउट किया। वह मंगलवार को 16 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए थे जब आवेश खान के बाउंसर से वह चोटिल हो गए। विहारी की इस साहसिक पारी ने जनवरी 2021 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में उनकी शानदार पारी याद दिला दी जब हैमस्ट्रिंग चोट के बावजूद रविचंद्रन अश्विन के साथ उन्होंने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का चार घंटे तक डटकर सामना किया और प्रतिद्वंद्वी टीम को जीत से वंचित कर दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश ने सलामी बल्लेबाज मंत्री और यश दूबे के बीच पहले विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी से मजबूत शुरूआत की। केवी शशिकांत (37 रन देकर दो विकेट) ने आंध्र को पहला विकेट दूबे के रूप में दिलाया।

साथी सलामी बल्लेबाज मंत्री को पृथ्वी राज (सात रन देकर एक विकेट) ने आउट किया। शुभम शर्मा (51 रन) और फॉर्म में चल रहे रजत पाटीदार (20 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े।

पंजाब ने सौराष्ट्र के खिलाफ बनाई बढ़त

भाषा। राजकोट

सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और नमन धीर की शतकीय पारियों और दोनों के बीच शुरुआती विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी से पंजाब ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र के खिलाफ दूसरे दिन बुधवार को यहां स्टंप्स तक पांच विकेट पर 327 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। नमन ने 180 गेंद की पारी में नौ चौके और सात छक्के की मदद से 131 रन बनाए जबकि प्रभसिमरन ने 158 गेंद में 126 रन की पारी के दौरान 13 चौके और तीन छक्के जड़े। सौराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में 303 रन बनाए थे जिससे पंजाब के पास अब 24 रन की बढ़त है और उसके पांच विकेट बाकी है।

दिन का खेल खत्म होते समय कप्तान मंदीप सिंह 39 और विकेटकीपर अनमोल मल्होत्रा 16 रन बनाकर खेल रहे थे। दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान तीन रन पर करने के बाद प्रभसिमरन और नमन ने पंजाब को शानदार शुरुआत दिलाई और लंच से पहले विरोधी टीम के गेंदबाजों को सफलता से दूर रखा। लंच के बाद हालांकि गेंदबाजों ने सौराष्ट्र की वापसी कराई। सौराष्ट्र के लिए शतक लगाने वाले पार्थ भट ने प्रभसिमरन को आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए पुखराज मान (एक) भी जल्दी पवेलियन लौट गए। नमन को इसके बाद कप्तान मंदीप का अच्छा साथ मिला लेकिन उनके आउट होने के बाद पंजाब ने जल्दी जल्दी अनमोलप्रीत सिंह (नौ रन) और नेहा ल वडेरा (चार रन) के विकेट गंवा दिए। सौराष्ट्र के लिए धर्मेंद्रसिंह जडेजा और युवराजसिंह डोडिया ने दो-दो विकेट लिए। पार्थ को एक सफलता मिली।

पश्चिम बंगाल ने पहली पारी की बढ़त हासिल की

भाषा। कोलकाता

कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन और सुदीप घरामी के अर्धशतकों से बंगाल ने बुधवार को यहां रणजी ट्राफी क्वार्टरफाइनल के दूसरे दिन झारखंड के खिलाफ पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल कर ली।

झारखंड को 173 रन पर समेटने के बाद बंगाल ने दूसरे दिन स्टंप तक पांच विकेट पर 238 रन बनाकर पहली पारी में 65 रन की अहम बढ़त हासिल की। सलामी बल्लेबाज काजी जुनैद सैफी (01 रन) नौंवे ओवर में आशीष कुमार की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। जिसके बाद अभिमन्यु (77 रन) और घरामी (68 रन) ने बल्ले से दमदार प्रदर्शन किया। अभिमन्यु और घरामी ने दूसरे विकेट के लिए 136 रन जोड़कर घरेलू टीम को पहली पारी की बढ़त हासिल करने के करीब पहुंचा दिया। लेकिन इन दोनों के लगातार आउट होने के बाद टीम ने 60 रन जोड़कर चार विकेट गंवा दिए जिससे टीम का स्कोर पांच विकेट पर 207 रन हो गया। पर फिर अभिषेक पोरेल (25 रन) और शाहबाज अहमद (17 रन) ने पारी को संभालते हुए नाबाद साझेदारी निभा ली है। झारखंड के सुप्रियो चक्रवर्ती ने दो जबकि आशीष, अनुकूल रॉय और शाहबाज नदीम ने एक एक विकेट हासिल किए।

कर्नाटक ने उत्तराखंड पर कसा शिकंजा

बेंगलुरु। हरफनमौला श्रेयस गोपाल की नाबाद 103 रन की पारी के दम पर कर्नाटक ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड के खिलाफ बुधवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पांच विकेट पर 474 रन बनाकर पहली पारी में बड़ी बढ़त कायम कर ली। उत्तराखंड की पहली पारी महज 116 रन पर सिमट गई थी जिससे कर्नाटक के पास अब 358 रन की बड़ी बढ़त है और उसके पांच विकेट बचे हुए है। कर्नाटक की टीम ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 123 रन से की। कप्तान मयंक अग्रवाल (83)और रविकुमार समर्थ (82) शतक पूरा करने से चूक गए लेकिन दोनों ने पहले विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी। इन दोनों के पवेलियन जाने के बाद निकिन जोस (62) और देवदत्त पडिक्कल (69) ने तीसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 300 रन तक पहुंचाया। श्रेयस गोपाल और मनीष पांडे (39) ने इसके बाद टीम के लिए पारी की तीसरी शतकीय साझेदारी की। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 108 रन जोड़े। श्रेयस गोपाल ने इस दौरान प्रथम श्रेणी क्रिकेट का पांचवां शतक जड़ा और 3000 रन के आंकड़े को पार किया।

उन्होंने 153 गेंद की नाबाद पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया। इस दौरान मयंक मिश्रा ने 31 रन देकर तीन विकेट लिए। उनके अलावा उत्तराखंड का कोई भी गेंदबाज प्रभावी नहीं दिखा। अभय नेगी ने 82 रन देकर दो विकेट चटकाए। स्टंप्स के समय श्रेयस गोपाल के साथ विकेटकीपर बी आर शरत क्रीज पर मौजूद थे। शरत 23 रन पर खेल रहे है।

दोनों ने छठे विकेट के लिए अब तक 59 रन की अटूट साझेदारी कर ली है।